RNI No.UTTHIN/2013/50587

नेशनल फ्रंटियर

वर्ष :13 , अंक : 02 , मई 2025 , देहरादून पृष्ठ : 52 मूल्य ₹ 10/-

OPERATION SINDOOR

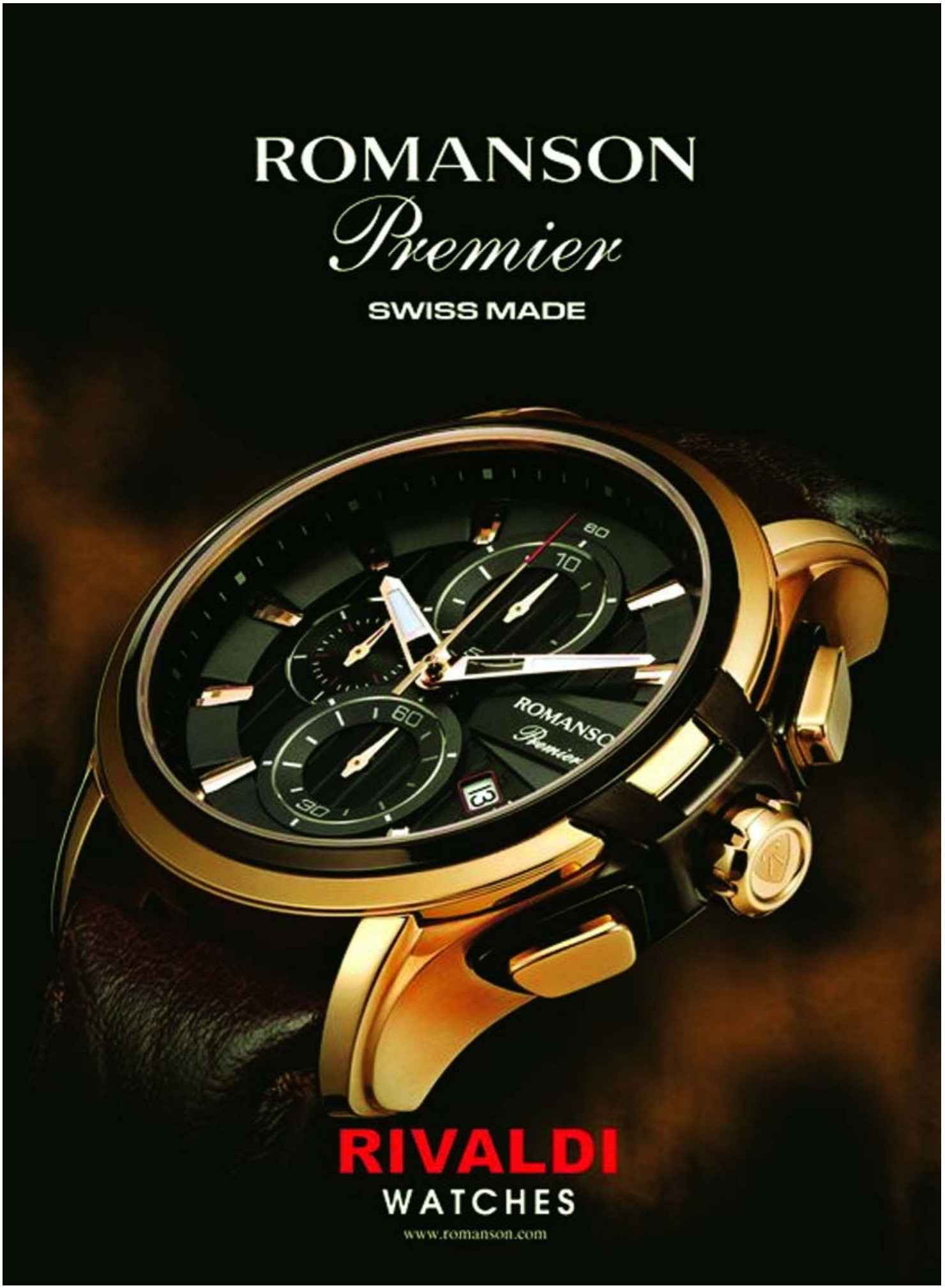

ROMANSON
Premier
SWISS MADE
ROMANSON
Premier
RIVALDI
WATCHES
www.romanson.com

संपादकीय

संपादक कोना

मुस्लिम आरक्षण का खेल खेलती कांग्रेस

कर्नाटक में मुसलमानों को सार्वजनिक ठेकों में चार प्रतिशत आरक्षण देने के मुद्दे पर संसद में भारी हंगामा हुआ। भाजपा सांसदों ने इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस पर संविधान बदलने का आरोप लगाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, कह रहे हैं कि पार्टी संविधान बदलकर मुस्लिमों को आरक्षण देगी। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में उपमुख्यमंत्री डीके षिवकुमार ने कहा है कि मुस्लिमों का ठेकों में चार प्रतिषत आरक्षण बरकरार रखने के लिए जरूरत पड़ी तो संविधान में भी बदलाव करेंगे। रिजिजू ने इस मुद्दे को बारी-बारी से संसद के दोनों सदनों में उठाया। इसे लेकर भारी हंगामा हुआ। इस मुद्दे का समर्थन करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि 'कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को बदलना चाहती है, क्योंकि इसमें साफ लिखा है कि धर्म के आधार पर किसी को भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। परंतु कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ऐसा करने जा रही है। संविधान बदलने का बयान संवैधानिक पद पर बैठे ऐसे व्यक्ति ने दिया है, जिसे हल्के से नहीं लिया जा सकता है। 'यही नहीं कर्नाटक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार ने ओबीसी, एससी और एसटी के युवाओं का हक मारकर मुसलमानों को 4.5 प्रतिषत आरक्षण देने का काम किया था। जबकि हमारे संविधान में धर्म आधारित आरक्षण की कोई जगह नहीं है। अतएव इस तरह के प्रयास संविधान निर्माताओं की देषहित से जुड़ी इच्छाओं के विरुद्ध हैं। बावजूद कांग्रेस मुस्लिमों को धर्म आधारित आरक्षण देने का तुश्टिकरण से जुड़ा खेल निरंतर खेलती आ रही है।

कांग्रेस की सोच हमेशा से तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति की रही है। 2004 से 2010 के बीच में कांग्रेस ने चार बार आंध्रप्रदेष में मुस्लिम आरक्षण लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वे अपने मंसूबे पूरे नहीं कर पाए? दरअसल यह कांग्रेस का 'पायलट प्रोजेक्ट' था, जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। अल्पसंख्यक बनाम मुस्लिमों को पिछड़ों, दलित और आदिवासियों के संविधान में निर्धारित कोटा के अंतर्गत 4.5 प्रतिशत आरक्षण देने की केंद्र सरकार की मंशा हमेषा रही है। लेकिन न्यायालय के हस्तक्षेप के चलते इस मंषा को पलीता लगता रहा है। इस आरक्षण को लेकर आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के बाद देष की सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए आंध्रप्रदेष उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध दायर आपील को खरीज कर दिया था। केंद्र सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्थगन आदेश चाहती थी। इस मंशा के विपरीत कोर्ट ने सरकार से यह और स्पष्ट करने को कहा था कि वह बताए की उसने किस आधार पर अल्पसंख्यकों को 4.5 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया? कोर्ट ने यह भी कहा था कि क्या इस तरह कोटे में उप कोटा आरक्षित करने का सिलसिला चलता रहेगा?

दरअसल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने धर्म के आधार पर' आरक्षण का लाभ संविधान के विरुद्ध बताया था। दिसम्बर 2011 के बाद से शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन केंद्र सरकार ने कुटिल चतुराई से ओबीसी के कोटे में खासतौर से मुस्लिमों को लुभाने के लिए 4.5 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का प्रावधान कर दिया था। इसे आंध्र उच्च न्यायालय ने अस्वीकारते हुए साफ किया था कि कोटा के अंतर्गत उप कोटा दिए जाने का प्रावधान अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए दिया गया है। इसे कानूनी रूप देते हुए कहा गया है कि 'अल्पसंख्यकों से संबंधित' और 'अल्पसंखयकों के लिए' जैसे वाक्यों का जो प्रयोग किया गया है वह असंगत है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। इस फैसले का व्यापक असर होना तय था। क्योंकि यह प्रावधान आईआईटी जैसे केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में भी लागू हो गया था। बहरहाल न्यायालय के फैसले के बाद कांग्रेस का मुस्लिमों को लुभाने वाले नुस्खे पर पानी फिर गया था।

वंचित समुदाय वह चाहे अल्पसंख्यक हों अथवा गरीब सवर्ण, उनको बेहतरी के उचित अवसर देना लाजिमी है, क्योंकि किसी भी बदहाली की सूरत, अल्पसंख्यक अथवा जातिवादी चश्मे से नहीं सुधारी जा सकती? खाद्य की उपलब्धता से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जितने भी ठोस मानवीय सरोकार हैं, उनको हासिल करना मौजूदा दौर में केवल पूंजी और शिक्षा से ही संभव है। ऐसे में आरक्षण के सरोकारों के जो वास्तविक हकदार हैं, वे अपरिहार्य योग्यता के दायरे में न आ पाने के कारण उपेक्षित ही रहेंगे। अलबत्ता आरक्षण का सारा लाभ वे बटोर ले जाएंगे जो आर्थिक रूप से पहले से ही सक्षम हैं और जिनके बच्चे पब्लिक स्कूलों से पढ़े हैं। इसलिए इस संदर्भ में मुसलमानों और भाषायी अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की वकालात करने वाली रंगनाथ मिश्र आयोग की रिर्पाट के भी कोई बुनियादी मायने नहीं रह गए थे? यह रिपोर्ट भी मुसलमानों को संवैधानिक प्रावधानों में आरक्षण जैसे विकल्प खोलने के लिए तैयार कराई गई थी।

हेमंतराव बी खानविलकर
मुख्य संपादक

नेशनल फ्रंटियर

वर्ष : 13 , अंक : 02 , मई 2025

RNI No. UTTHIN/2013/50587 ISSN 2324-2861

मुख्य संपादक हेमंतराव बी खानविलकर
कार्यकारी संपादक अंजन साबत
प्रबंध संपादक उमा शंकर तिवारी
कानूनी सलाहकार विजयेश नवानी
सह संपादक रिद्धिका अग्रवाल

बिहार राज्य प्रमुख पीयूष प्रसाद
फीचर संपादक वसुंधरा पाण्डेय

विशेष संवाददाता

●दिल्ली से दुर्गेश तिवारी, मो. तारिक अवि, प्रदीप कुमार, ●भोपाल से कुलदीप तिवारी, ●रायपुर से जितेंद्र कुमार साहू ●लखनऊ से राजरतन सिंह ●पटना से राजेश कुमार ●चंडीगढ़ से सज्जन सिंह ●शिमला से राजीव रानावत, ●श्रीनगर से संजय काले ●कलकत्ता से वैभव वत्स ●जयपुर से प्रियेश हजानिया ●अहमदाबाद से मयंक जोशी, ●मुंबई से जया अग्रवाल ●नागपुर सरस खेलकर।

देहरादून कार्यालय
एस-17, दून विहार काम्पलेक्स राजपुर रोड, जाखन, देहरादून, उत्तराखंड, 248001

भुवनेश्वर कार्यालय
105, लोमिनी विला, ब्लाक 01, गोथापटना, भुवनेश्वर, उड़ीसा

इंदौर कार्यालय
178, पंचवटी कालोनी, एरोड्रम रोड, इंदौर, मध्यप्रदेश, 452002

मुंबई कार्यालय
407, जय अंबे सोसायटी, सी विंग, नियर मेगा माल, आनंद नगर जोगेश्वरी, वेस्ट मुंबई 400102

हैदराबाद कार्यालय
203 वीजीसी इंटरनेशनल, अपोजिट वेस्ट साइड माल, हिमायतानगर हैदराबाद 500020

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक हेमंतराव बी खानविलकर द्वारा एस-17, दून विहार काम्पलेक्स, राजपुर रोड, जाखन , देहरादून (उत्तराखंड) से प्रकाशित एवं शब्द संस्कृति प्रिंटर्स, चकराता रोड, देहरादून (उत्तराखंड) से मुद्रित।
संपादक : हेमंतराव बी खानविलकर।

RNI NO : UTTHIN/2013/50587

email : nationalfrontier@gmail.com,
संपर्क सूत्र (मो.) : +91 9897130210
+91 7065102037

नोट :मुद्रित सामग्री के लिए संपादक-प्रकाशक एवं प्रेस की सहमति अनिवार्य नहीं। सभी विवादों का न्यायक्षेत्र देहरादून होगा।

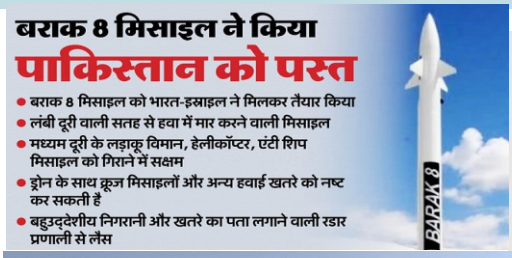

नक्सलवाद पर	05
सेवा सुरक्षा और सुश्सन के 8 वर्ष	12
सुपर फ़ूड जैसा है अंकुरित भोजन	18
हिंदी विरोध के पीछे की राजनीति	19
आप ने बदला रुख :....	21
क्रूर एवं आक्रान्ता मुग़ल शासक	23
अखाड़ा बन गया है बिहार चुनाव	25
विधानसभा चुनाव : सत्ता की लड़ाई	27
बिहार विधानसभा चुनाव : 243 सीटों	29
संघ के कर्नाटक -मंथन में नए संकल्प	30
यहाँ प्लास्टिक वहां प्लास्टिक	32
बहने लगी बसंती बयार ...	34
आखिर फ़िनलैंड की तरह हम खुश क्यों ...	35
हर दिन को जीना :	38
ऑपरेशन सिन्दूर	39
ऑपरेशन सिन्दूर द्वारा पाकिस्तान और	40
आकाश मिसाइल	45
कैसे कम करता है भारत का सुदर्शन	46
ऑपरेशन सिन्दूर में दिखा राफेल का दम	48
ब्रह्म के स्वरूप का गूढ़ रहस्य	50

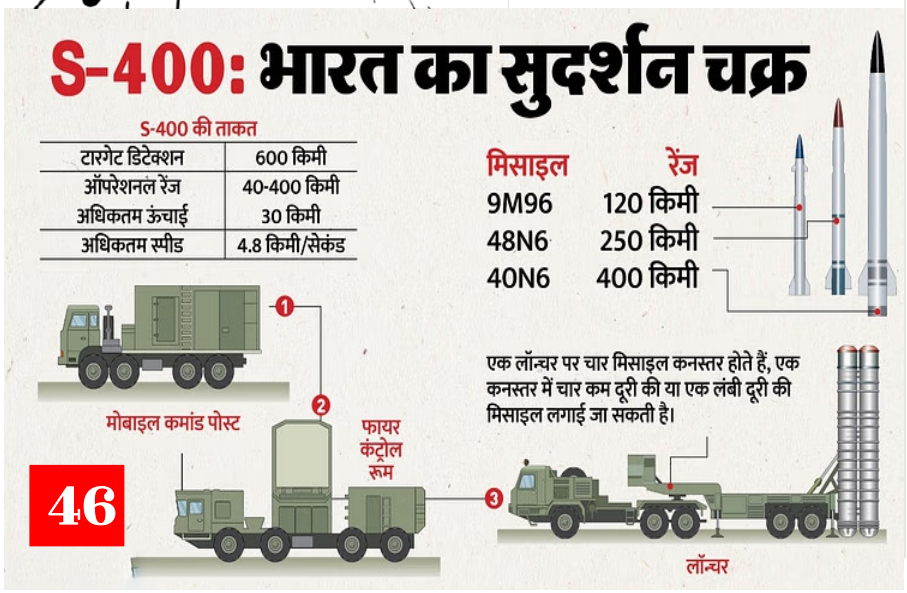

नक्सलवाद पर

इस कवर स्टोरी में पढ़िए नक्सलियों के खतरे को जड़ से मिटा डालने के मोदी सरकार के ठोस अभियान की अंदरूनी कहानी. सरकार का दावा है कि मार्च 2026 तक भारत नक्सल खतरे से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा

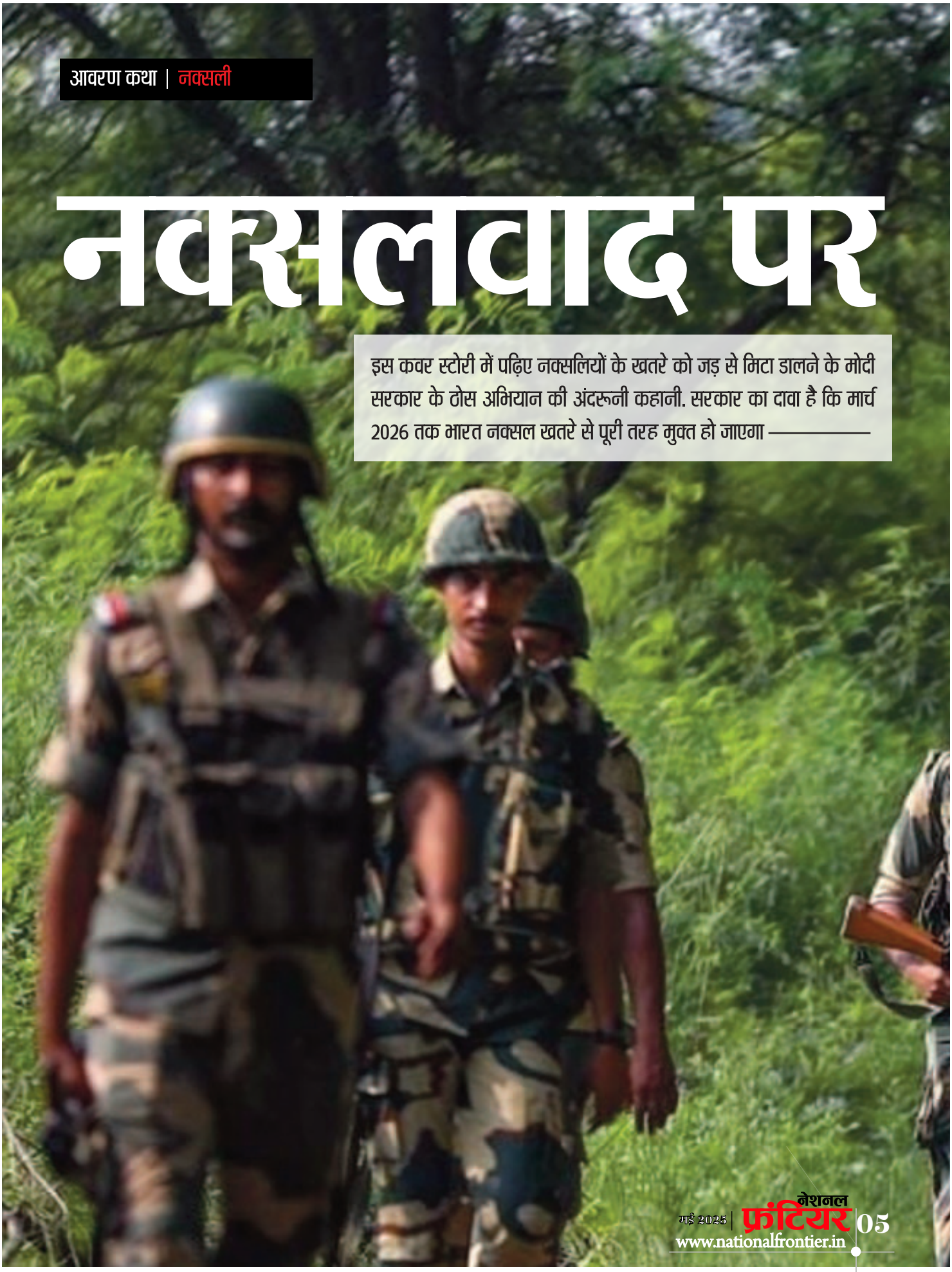

मार्च बस शुरू ही हुआ है, हवा में वसंत की गंध है और महुआ के पेड़ खिल उठे हैं, उनकी लाल छटा मध्य भारत के राज्य छत्तीसगढ़ के बस्तर में साल वन की घनघोर हरियाली में अलग ही रंग घोल रही है. ऊपर उड़ते बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) के हेलिकॉप्टर की खिड़की से इंद्रावती नदी प्रकृति की इस मनमोहक छटा को नीले फीते से लपेटती दिखती है.

वैसे, यह सुंदर सुरम्य छवि छलावा है. नीचे डरावने जंगलों में केंद्रीय और राज्य सशस्त्र पुलिस बल के जवान मरने-मारने पर उतारू हिंसक वामपंथी उग्रवादियों (एलडब्ल्यूई) या नक्सलियों के खिलाफ खूनी जंग में उलझे हुए हैं, जो पिछले छह दशकों से देश में आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं.

यह ऐसी जंग है, जो बड़ी भारी कीमत ले चुकी है. पिछले 20 साल में 2,344 पुलिस जवानों ने नक्सलियों से लड़ते हुए जान गंवाई है, जो 1999 की करगिल जंग में मारे गए सेना के जवानों की संख्या से चार गुना ज्यादा है. दरअसल, जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ने के मुकाबले नक्सलियों से लड़ाई में ज्यादा पुलिसवालों की जान गई है, जो हाल तक देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए दूसरा बड़ा खतरा थे. हताहत आम लोगों की संख्या भी बहुत अधिक है. पिछले दो दशकों में ही नक्सली हमलों में 6,258 से ज्यादा लोग मारे गए हैं.

अपने चरम पर नक्सली खतरे ने 8 करोड़ लोगों की जिंदगियों को चपेट में लिया, जिनमें अधिकांश आदिवासी हैं. यह आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश तक एक पतले लाल गलियारे के साथ 10 राज्यों में फैला हुआ था. या बकौल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नेपाल के पशुपति से लेकर आंध्र के तिरुपति तक.

हालांकि, पिछले एक साल में इसका असर घट रहा है, क्योंकि मोदी सरकार राज-सत्ता के कट्टर दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में हावी हो रही है, जिससे खतरा अब बेहद छोटे-से लाल धब्बे जैसा सिमट गया है. यह बड़े पैमाने पर बस्तर क्षेत्र तक सीमित है, जहां अब भी भीषण जंग जारी है.

मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई, तो दस राज्यों के 126 जिलों को सबसे अधिक प्रभावित दर्ज किया गया था. 2025 की शुरुआत में यह संख्या घटकर 12 हो गई है, जिनमें ज्यादातर बस्तर में हैं. बाकी ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पड़ोसी जिले हैं. बेशक, यह उपलब्धि इतनी प्रभावशाली है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली के अपने घर में एक मीडिया संस्थान के साथ बातचीत में कहा, ₹पक्के तौर पर मेरा मानना है कि मार्च 2026 तक भारत नक्सल खतरे से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा.₹

हालांकि, आसमान से देखने पर सरकार की यह सबसे बड़ी बदलावकारी मुहिम बस्तर के घने जंगल में महज दो एकड़ के खेत से ज्यादा बड़ी नहीं दिखती. वहां एस्बेस्टस की छत वाले कुछ छप्पर और कुछ मुर्गियां ही दिखती हैं. जैसे ही हेलिकॉप्टर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कैंप पुवर्ती में बने अस्थायी हेलीपैड के करीब पहुंचता है, तो उठ रहे धूल के बवंडर में छुपने के लिए ग्राउंड स्टाफ इधर-उधर भागने लगता है. धूल बैठती है, तब आपको कैंप के चारों ओर बंदूकधारी शूटरों से लैस खौफनाक निगरानी टावर दिखाई देने लगते हैं.

पुवर्ती नक्सल ग्रस्त सुकमा जिले के एक छोर पर सीआरपीएफ की 150वीं बटालियन के पहरे में है, जिसका आकर्षक नारा 'वन-फाइव जीरो, जंगल हीरो' है, जो वह वाकई है. पुवर्ती कभी खूंखार माओवादी कमांडर मादवी हिडमा का गढ़ था, जो सुरक्षा बलों पर दो दर्जन से अधिक हमलों का मास्टरमाइंड बताया जाता है. उनमें 2010 में पास के ताड़मेटला गांव में हुआ हमला भी है जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे. साल भर पहले तक कोई सरकारी आदमी, चाहे वर्दी में हो या सादे कपड़े में, पुवर्ती में पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) की बटालियन नं. 1 की इजाजत के बिना दाखिल नहीं हो सकता था.

"नक्सलियों के समूचे तंत्र पर भरी चोट पहुंची है और वह तेजी से खात्मे की ओर बढ़ रहा है. अब फिर से खड़े हो पाने की संभावना काफी कम है."
अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री

साल भर पहले जब यहां कैंप बनाया गया, तो पीएलजीए के चार बड़े हमलों को नाकाम करके 150वीं बटालियन ने नक्सल उग्रवादियों को दूर घने जंगलों में खदेड़ दिया और इस तरह इलाके में सीआरपीएफ का दबदबा कायम कर लिया. बेखौफ कैंप कमांडेंट राकेश शुक्ला अब मुस्कराते हुए बस यही चेताते हैं, "हमारे चारों ओर अब भी बिच्छू और सांप की भरमार है, खासकर करैत, जो हमारे बिस्तर को अपना समझ लेते हैं—इसलिए सोने से पहले अपना कंबल जरूर झाड़ लें.₹

बाद में उस रात एक गश्ती दल संदिग्ध गतिविधि के लिए आसपास के जंगलों की तलाशी लेता है, और आगे-आगे बारूदी सुरंग की टोह लेने वाला रास्ता साफ करता जाता है. नक्सलियों का सबसे बड़ा हथियार 'इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस' (आईईडी) या सड़कों पर लगाई गई बारूदी सुरंगें हैं, जो किसी को भी अपंग कर सकती हैं या जान भी ले सकती हैं. चारों तरफ घुप्प अंधेरा है और गश्ती दल एक-दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर कतार में आगे बढ़ रहा है, जबकि उनका अगुआ रात में दिखने वाले बाइनाकूलर से जंगल की टोह लेता चलता है. दूसरा गश्ती दल सवेरे निकलता है, एक के पीछे एक, लेकिन अब वे मोटरसाइकिलों पर हैं, जो बारूदी सुरंगों से बचने के लिए पसंदीदा वाहन है.

बहुआयामी रणनीति

पुवर्ती जैसे कैंप को फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस या एफओबी नाम दिया गया है और ये मोदी सरकार की बहुआयामी रणनीति का मुख्य आधार हैं, जिसके तहत देश को अगले वसंत तक नक्सली खतरे से मुक्त किया जाना है. छत्तीसगढ़ सेक्टर के सीआरपीएफ के मिलनसार आईजी राकेश अग्रवाल बताते हैं कि एफओबी कैसे गेम-चेंजर बन गए हैं.

छह साल पहले उनकी शुरुआत से पहले सुरक्षा शिविर मुख्य रूप से नक्सल ग्रस्त क्षेत्रों के पास राजमार्गों पर बनाए जाते थे और एक वक्त पर एक ऑपरेशन चलाते थे. नक्सलियों के खिलाफ अभियान के लिए उन्हें अपने शिविरों से 30 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था, जिससे वे थक जाते थे और घात लगाकर हुए हमलों के आसान शिकार हो जाते थे. अब एफओबी माओवादी ठिकानों के करीब घने जंगलों में हैं और एक-दूसरे से 5 किलोमीटर की दूरी पर सख्त सुरक्षा ग्रिड बनाते हैं. किसी एक शिविर पर हमला होने पर कुछ दूरी पर ही और जवान होते हैं और जरूरत पड़ने पर बुलाए जा सकते हैं.

कभी अविभाजित बस्तर (जो केरल के आकार के बराबर था) का मुख्यालय रहे जगदलपुर में स्थित कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट ऐक्शन (कोबरा) के विशाल केंद्र में अधिकांश लड़ाकू टुकड़ियां गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित हैं. अब बस्तर छत्तीसगढ़ के घने जंगलों वाले सात जिलों में बंटा है. 201वीं कोबरा यूनिट के चुस्त-दुरुस्त कमांडेंट अमित चौधरी कहते हैं, ₹हमारा सामना युद्ध के लिए प्रशिक्षण पाए विरोधी से है, जो इसी इलाके के हैं और यहां से अच्छी तरह वाकिफ है, जंगलों में बहुत सक्रिय हैं और धोखे से हम पर आईईडी या घात लगाकर हमला कर सकते हैं. उनके जोश-जज्बे के लिए सिर्फ एक बार कामयाब होने की दरकार है जबकि हमें हर दिन स्कोर करना होगा.₹

कोबरा टुकड़ी तीन बड़े मामलों में केंद्रीय और राज्य पुलिस दोनों को प्रशिक्षण देती है: बारूदी सुरंगों और घात लगाकर किए गए हमलों से अपना बचाव करना, अपने हथियारों से सटीक निशाना लगाना और दुर्गम जंगली इलाके और चालाक विरोधियों से मिलने वाले शारीरिक और मानसिक तनाव को झेलना.

फिलहाल बस्तर इलाके में 182 सुरक्षा एफओबी हैं, और उन्हें स्थापित करने की रफ्तार भी बढ़ रही है. पहले सालाना औसतन 15 शिविर स्थापित किए जाते थे, लेकिन 2024 में ही 30 नए एफओबी बनाए गए हैं. शाह की 'हथियरबंद नक्सलियों से बेरहमी से निपटो' की नीति के मद्देनजर, इन एफओबी को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है, जिससे सुरक्षा बलों को नक्सलियों के हथियारों से निपटने में मदद मिली है. सुरक्षा बलों के पास बुल्गारिया निर्मित एके सीरीज असॉल्ट राइफलों में से कुछ में अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर लगे हैं, उसके अलावा टैवर्स और जेवीपीसी कार्बाइन, कार्ल गुस्ताव 84 मिमी रॉकेट लॉन्चर, 51 और 81 मिमी मोर्टार, थर्मल इमेजिंग स्कोप के साथ-साथ नाइट विजन उपकरण जैसे हथियार हैं.

सुरक्षा बलों के शस्त्रागार में सबसे नया डब्ल्यूएचएपी या व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म है, जिसे टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने संयुक्त रूप से डिजाइन किया है. यह बख्तरबंद सैन्य वाहन है, जिसमें अंदर से हथियारों को नियंत्रित करने और बारूदी सुरंग विरोधी क्षमताएं हैं. इस प्लेटफॉर्म ने बलों को हमले के दौरान माओवादियों से लड़ाई में मदद की है. पिछले साल, जब माओवादियों ने तेलंगाना में तेकुलगुडेम में सीआरपीएफ शिविर पर हमला किया था तो सेकंड-इन-कमान एस.एस. हओकिप ने डब्ल्यूएचएपी की कमान संभाली थी, और गोलीबारी के लिए उसके एमएमजी का इस्तेमाल किया था. माओवादियों ने पहली बार डब्ल्यूएचएपी को कार्रवाई करते देखा, और उन्हें फटाफट पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा.

इसी तरह मोदी सरकार की खुफिया जानकारी जुटाने और विश्लेषण के खातिर अत्याधुनिक निगरानी तकनीक का इस्तेमाल भी गेमचेंजर साबित हुआ है. हर एफओबी नेत्र 3 और भारत ड्रोन से लैस है, जिनकी रेंज 5 किलोमीटर है और कई बैटरी के साथ 60 मिनट तक उड़ सकते हैं. ड्रोन को 10 मीटर & 10 मीटर की जगह से उड़ाया जा सकता है और बेस पर एक स्क्रीन पर मौके से बेहद साफ तस्वीरें हासिल की जा सकती हैं.

ऑपरेशन शुरू करने से पहले जवान ड्रोन को उड़ाते हैं, ताकि इलाके और माओवादियों की उपस्थिति का पता लगाया जा सके. रात के ऑपरेशन के लिए इन्फ्रारेड क्षमताएं मनुष्यों और जानवरों की हरकतों में अंतर कर सकती हैं. चौधरी कहते हैं, ₹हमारे विरोधियों के लिए अब छिपने की कोई जगह नहीं है और कई साल के बाद पहली बार नक्सली वाकई भाग रहे हैं.₹

आसमान से नजर रखने का सबसे अहम काम हेरॉन यूएवी (मानव रहित हवाई वाहन) कर रहे हैं, जिनकी उड़ान सीमा 35,000 फुट है और 10 घंटे तक उड़ने की क्षमता है. नजदीकी हवाई पट्टियों से उड़ान भरकर हेरॉन प्रभावित क्षेत्र की तस्वीरें जुटाते हैं और वायरलेस तथा सेलफोन पर बातचीत रिकॉर्ड करते हैं. यह डेटा सुरक्षाकर्मियों के पास पहुंचता है जो इसे जमीनी स्तर की खुफिया जानकारी से पुष्ट करते हैं.

किसी निर्जन स्थान से की गई बातचीत, फोन कॉल या गोलीबारी विद्रोहियों की मौजूदगी का संकेत देती है. केंद्रीय पुलिस बल के मध्य भारत के अतिरिक्त महानिदेशक अमित कुमार कहते हैं कि हाल के ऑपरेशन केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच तकनीकी खुफिया जानकारी या टेकइंट के आदान-प्रदान के कारण सटीक और बेहद सफल रहे हैं.

सटीक मौखिक खुफिया जानकारी या ह्यूमिंट स्थानीय लोगों से मिलने लगी है, जो इलाके से बखूबी वाकिफ हैं. उन्हें जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) और नवगठित बस्तरिया बटालियन में भर्ती किया जा रहा है. इसके अलावा, आत्मसमर्पण कर चुके कई नक्सली (2014 से करीब 7,500) इन बलों में शामिल हो गए हैं, जो नक्सलियों के तौर-तरीकों और उनके ठिकानों के बारे में जानकारी दे रहे हैं.

इन उपायों से ऑपरेशन में तेजी आई है और पिछले 15 महीनों में छत्तीसगढ़ में 305 माओवादियों को मार गिराया गया है, और 2024 में ही बस्तर संभाग में 217 माओवादी मारे गए. यह आंकड़ा राज्य में उग्रवाद के इतिहास के बाद से किसी भी वर्ष के मामले में सबसे अधिक है. इस बीच, नक्सलियों से मुक्त क्षेत्रों में, दबदबा बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन या बख्तरबंद थाने स्थापित किए गए

सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ के आईजी राकेश अग्रवाल सुकमा जिले के पुवर्ती गांव में लोगों को साइकिल बांटते हुए

हिंसा में कमी

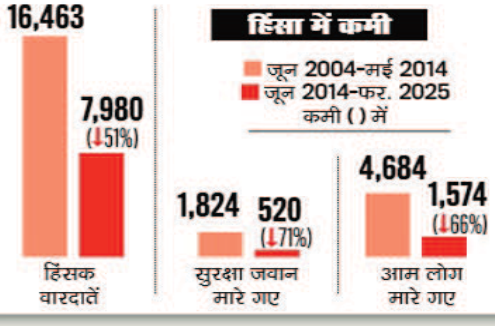

नियंत्रण कायम किया

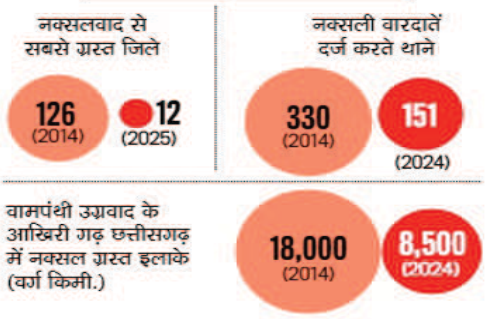

इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रगति

11,503 किमी.
वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में मई 2014 और सितंबर 2024 के बीच बनी सड़कें. 17,589 किमी. सड़कों के निर्माण के लिए कुल 20,815 करोड़ रु. की मंजूरी दी गई

2,343
मोबाइल टावर 2जी कनेक्टिविटी के लिए 4,080 करोड़ रु. की लागत से बनाए गए. इसके अलावा 2,542 टावरों के लिए 2,210 करोड़ रु. की मंजूरी दी गई है

वित्तीय समावेश

1,007
बैंक शाखाओं के अलावा 937 एटीएम खुले

शिक्षा सशक्तीकरण

495 करोड़ रु.
फंड की मंजूरी 48 जिलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए

हैं. पिछले पांच साल में 612 ऐसे थाने बन गए हैं, यही सबूत है कि कितने इलाके मुक्त करा लिए गए हैं.

दूसरे अहम उपाय के तहत केंद्र और नक्सल ग्रस्त क्षेत्रों में संबंधित राज्य सरकारों ने नक्सलियों को पैसे के प्रवाह पर अंकुश लगा दिया है. उनके आय का मुख्य स्रोत गर्मियों के महीनों में तेंदूपत्ता ठेकेदारों से लेवी और वन तथा सड़क ठेकेदारों से जबरन वसूली थी. नक्सली इस तरह अनुमानित 150 करोड़ रुपए जुटा लिया करते थे. निर्माण कार्यों को केंद्र सरकार की इकाई सीमा सड़क संगठन को सौंपने से पैसे का वह स्रोत बंद हो गया है. साथ ही खुफिया एजेंसियां तेंदूपत्ता ठेकेदारों पर कड़ी निगरानी रख रही हैं. अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले कई नक्सल ग्रस्त जिलों में तेंदूपत्ता की नीलामी ऑनलाइन की गई है, ताकि नकदी पर अंकुश लगे.

खात्मे की रूपरेखा

छत्तीसगढ़ में माओवादी आंदोलन के खात्मे के औपचारिक ऐलान के लिए सरकार को क्या करना होगा? छत्तीसगढ़ पुलिस के आईजी और बस्तर इलाके में राज्य पुलिस बलों के प्रभारी सुंदरराज पट्टिलिंगम कहते हैं, ₹सुरक्षा के नजरिए से हमारा मकसद नेतृत्व को ध्वस्त करना और यह पक्का करना है कि कोई नया माओवादी मामला सामने न आए. दूसरे शब्दों में, हम लगातार हिंसा करते रहने की माओवादी क्षमता को नष्ट कर देना चाहते हैं.₹

नक्सलियों का लंबा-चौड़ा संगठन है. इसके शीर्ष पर पोलितब्यूरो, सेंट्रल कमेटी और सेंट्रल मिलिट्री कमिशन हैं. फिलहाल 70 वर्षीय महासचिव नंबाला केशव राव पोलितब्यूरो का प्रमुख है, जो बासवराज और गगन्ना उपनामों से भी जाना जाता है. सैन्य शाखा की क्षेत्रीय, प्रांतीय और जोनल कमान हैं, और हथियारबंद मिलिशिया इस पिरामिड के आधार का निर्माण करता है. मोदी सरकार ने पिछले पांच साल में 'पता लगाओ, निशाना साधो और खत्म कर दो' तरीका अपनाया, जिसकी बदौलत 15 शीर्ष नक्सल नेता मारे गए. इनमें पोलितब्यूरो के तीन और सेंट्रल कमेटी के 12 सदस्य हैं. पुलिस सूत्रों का कहना है कि बीते साल कार्रवाइयों में मिली कामयाबी की बदौलत बस्तर में नक्सलियों के कट्टर लड़ाकों की संख्या तीन साल पहले के 1,400 से घटकर 600 रह गई है.

फिलहाल बस्तर में तीन इलाके ऐसे हैं जहां सुरक्षा का अभाव है. यहां राज्य-सत्ता उतनी असरदार नहीं जितनी दूसरी जगहों पर है. माओवादी इन्हें 'लिबरेटेड या मुक्त क्षेत्र' कहते हैं. सबसे अहम है अबूझमाड़, जो सचमुच अबूझ जंगल है. यह 4,000 वर्ग किमी में फैला है, जिसका 60 फीसद नारायणपुर, 15 फीसद बीजापुर, 10 फीसद कांकेर जिलों में आता है, जबकि और 5 फीसद महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में है.

सुंदरराज कहते हैं, ₹अबूझमाड़ अभेद्य था और पहले वहां सुरक्षा भी मौजूद नहीं थी, लेकिन अब इसके भीतर हमारे नौ कैंप हैं. इससे अबूझमाड़ में सुरक्षा का अभाव काफी घट गया है.₹ दूसरा इलाका बीजापुर जिले में इंद्रावती टाइगर रिजर्व के भीतर नेशनल पार्क या वन क्षेत्र है. हाल के दिनों में इस इलाके में सघन कार्रवाइयां की गईं. इनमें 9 फरवरी की वह हालिया कार्रवाई भी है जिसमें नेशनल पार्क एरिया कमेटी के 31 माओवादी गोलीबारी में मारे गए.

इस बीच केंद्र ने नक्सल प्रभावित जिलों में विकास की रफ्तार तेज कर दी है, जिसे 'गोली और गुलाब' नीति कहा जा सकता है ताकि इलाके के लोगों का दिल जीता जा सके और उनकी समस्याओं का निपटारा किया जा सके. उन इलाकों में नक्सलवादी आंदोलन के फैलने की जड़ में विकास का अभाव और ठेकेदारों तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा किसानों का शोषण माना जाता है. इसलिए चतुर पहल के तहत एफओबी सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि दिलों को जीतने की रणनीति का भी अहम हिस्सा हैं.

2 मार्च को पुवर्ती कैंप में सिविक ऐक्शन

प्रोग्राम (सीएपी) का आयोजन किया गया, जिसमें आईजीपी अग्रवाल ने साइकिलें, साड़ी, पानी की टंकी, कंबल और दवाइयां बांटी. दूसरे एफओबी की तरह पुवर्ती में भी दस बिस्तरों का फील्ड अस्पताल है, जिसमें स्थानीय लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर छोटे-मोटे ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर भी है और उस क्षेत्र छह फील्ड अस्पताल में एक है. जाहिर है, ऐसी पहल से लोगों में बगावत की भावना को कम करने में मदद मिलेगी.

विकास की दवा, उम्मीद की हवा

यह एहसास भी शिद्दत से है कि सुरक्षा दुरुस्त करना समस्या से निपटने का एक पहलू है, साथ ही वे विकास की बाधाएं दूर करने पर भी जोर दे रहे हैं. बीजापुर जिले में पामेड़ के पास चिंतावागु नदी पर बना नया शानदार पुल कई ऐसी ही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है, जो कई गांवों के लिए जरूरी संपर्क मुहैया करा रहा है. यह अलग बात है कि नक्सलियों ने इस पुल को विस्फोटकों से उड़ाने और पास के धर्मावरम एफओबी पर हमला करने की कई कोशिशें की हैं.

कंचल गांव के निवासी मरकम बंडी कहते हैं, ₹पुल की वजह से हमें स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में मदद मिली है और पामेड़ में मिर्ची तोड़ने का काम भी मिला है.'' इसी तरह जिन इलाकों में सड़कों की जरूरत है, लेकिन मजदूर या ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं हैं, वहां गृह मंत्रालय ने बीआरओ को सड़क बनाने में लगाया है. संचार बेहतर बनाने के लिए इन एफओबी के करीब 2,000 से ज्यादा मोबाइल टावर लगाए गए हैं. यह सुनिश्चित करने के लिए यह सब किया जा रहा है, जैसा कि शाह कहते हैं, "लोगों के पास नक्सलवाद की ओर लौटने का कोई कारण न हो.₹

छत्तीसगढ़ सरकार भी माओवादी समस्या के खिलाफ अपने प्रशासन की सक्रियता बढ़ा रही है. प्रभावित क्षेत्र में तेंदू पत्तों की तुड़ाई प्रमुख आर्थिक गतिविधि है. इसलिए राज्य सरकार ने प्रति मानक बोरा मजदूरी को 4,000 रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपए कर दिया है. प्रभावित क्षेत्रों में नियद नेल्लानार या मेरा आदर्श गांव योजना शुरू की गई है, जिसके तहत लोगों को 52 योजनाओं और 31 नागरिक सेवाओं में नामांकित किया जा रहा है.

सुरक्षा शिविर राशन कार्ड, रसोई गैस और साइकिल जैसी योजनाओं को लागू करने में अहम

भूमिका निभाते हैं. नक्सलियों से लड़ने वाली सभी प्रमुख सुरक्षा एजेंसियां जानती हैं कि मार्च, 2026 तक नक्सल समस्या का खात्मा करने की गृह मंत्री की समय सीमा को पूरा करना दुरूह कार्य है, लेकिन वे इस जंग को जीतने के लिए संकल्पित हैं.

पुवर्ती में सीआरपीएफ के कैंप को लाइट से सजाया जा रहा है, कुर्सियां और मेजें करीने से लगाई जा रही हैं और साउंड सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जो किसी डिनर पार्टी की तैयारी जैसा लग रहा है. यह समय है बड़े खाने का—सशस्त्र बलों की एक परंपरा जहां अधिकारी और जवान विशेष अवसरों पर सामूहिक भाईचारा दर्शाने के लिए एक साथ खाना खाते हैं.

समारोह की शुरुआत अधिकारियों और जवानों के एकल गीत पेश करने के साथ होती है. कैंप के चिकित्सा अधिकारी डॉ. विवेकानंद बसप्पा किशोर कुमार का मशहूर गाना-नीले नीले अंबर पर गाते हैं और जवान तालियों की लय के साथ उनका साथ देते हैं. उम्मीद है कि नक्सली हिंसा की स्याह रातें जल्द ही खत्म हो जाएंगी और वे भी देश के बाकी हिस्सों की तरह शांति के नीले आसमान को निहार सकेंगे.

तकनीकी बढ़त

सुरक्षा एजेंसियां अब निगरानी और नक्सली गतिविधियों के विश्लेषण के लिए उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल कर रही हैं.

ड्रोन, उपग्रह तस्वीरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित डेटा विश्लेषण का इस्तेमाल.

लोकेशन ट्रैकिंग, सेल फोन ट्राइंगुलेशन, एडवांस कॉल लॉगिंग और सोशल मीडिया विश्लेषण के जरिए नक्सली काडरों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है.

सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष

महाबीरजायसवाल

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल में अब तक कई ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिन्होंने राज्य की दशा और दिशा को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लव जिहाद के खिलाफ कानून हो या फिर नकल और पेपर लीक पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून, महिलाओं के सम्मान और स्वावलंबन को सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति की पहल हो या फिर किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का निर्णय इन सभी के दीर्घ प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। इन निर्णयों ने यह भी साबित किया कि उत्तर प्रदेश में वो सरकार काबिज है, जिसके पास नीयत भी है और नीतियां भी।

उत्तर प्रदेश, भारत के 'श्रम शक्ति पुंज से अर्थ शक्ति पुंज' बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश वही है, लेकिन बीते 8 वर्षों में परसेप्शन पूरी तरह से बदल चुका है। सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि और सनातन संस्कृति के क्षेत्र में जो पहचान बनी है उसका एहसास उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा भारत कर रहा है। 8 वर्ष पहले बीमारू राज्य की पहचान रखने वाला उत्तर प्रदेश आज देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन और उनके विजनरी नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष पूरे हुए हैं। डबल इंजन सरकार ने हर क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। यूपी नंबर दो की अर्थव्यवस्था है और जल्द नंबर एक बनेगा।

बात अगर 2017 से पहले की स्थिति की करें तो 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की पहचान संकट में थी। किसान आत्महत्या कर रहे थे, युवा अपनी पहचान के मोहताज थे, बेटियां और व्यापारी असुरक्षित थे। दंगों और अराजकता ने अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया था। उस समय उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य माना जाता था और इसे देश के विकास में बाधक समझा जाता था। लेकिन 8 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने इस परसेप्शन को पूरी तरह बदल दिया। आज उत्तर प्रदेश देश के विकास का ब्रेकथ्रू बनकर हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है।

उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से कृषि प्रधान रहा है। यहां उर्वर भूमि और जल संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं। लेकिन 2017 से पहले किसान आत्महत्या कर रहे थे। उसके बाद डबल इंजन की सरकार ने इस स्थिति को बदला। 2017 में पहली कैबिनेट में ही 36,000 करोड़ रुपये की लागत से लघु और सीमांत किसानों की कर्ज माफी की गई। इसके परिणामस्वरूप 2016-17 में 557 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश 2023-24 में 668 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन तक पहुंच गया, जो 20% की वृद्धि दर्शाता है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2.61 करोड़ से अधिक किसानों को 80,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि डीबीटी के जरिए दी गई। 40 वर्षों से लंबित अर्जुन सहायक, बाणसागर और सरयू नहर जैसी परियोजनाओं को पूरा कर 23,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई सुविधा दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र, नया ऋषि विश्वविद्यालय और टेक्नोलॉजी के उपयोग से धान, गेहूं, दलहन और श्री अन्न में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर पहुंच गया।

साल 2008-09 से 2017 तक गन्ना किसानों का हजारों करोड़ रुपये बकाया था। योगी सरकार ने एक भी चीनी मिल बंद नहीं

योगी सरकार के 8 साल, 8 महत्वपूर्ण फैसले

लव जिहाद के खिलाफ बनाया कानून

सीएम योगी की पहल पर नवंबर 2020 में "उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम" लागू हुआ। इस कानून के तहत जबरन या छल से धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपये तक के जुमार्ने का प्रावधान किया गया। पहले साल में ही 100 से अधिक मामले दर्ज किए गए। यह कानून महिलाओं की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी।

मिशन शक्ति की शुरूआत

अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ "मिशन शक्ति" अभियान महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन पर केंद्रित है। इसके तहत एंटी-रोमियो स्क्वाड ने छेड़छाड़ के 32 हजार से अधिक मामलों में कार्रवाई की। कन्या सुमंगला योजना के तहत 22 लाख से ज्यादा बेटियों को आर्थिक मदद दी गई। 112 और 181 जैसी हेल्पलाइन ने आपात स्थिति में सहायता प्रदान की।

किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली

किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने विगत वर्ष उत्तर प्रदेश के निजी नलकूप उपभोक्ताओं को एक अप्रैल 2024 से बिजली बिल में 100 प्रतिशत छूट का लाभ देने का निर्णय लिया। इस निर्णय को पावर कॉर्पोरेशन ने विधिवत लागू किया। सिंचाई सुविधा के लिए 4 लाख से ज्यादा निजी नलकूपों का संयोजन किया गया। किसानों को विद्युत आपूर्ति के लिए 3 हजार से अधिक ग्रामीण फीडर अलग किए गए। निजी नलकूप कनेक्शन देने में डार्क जोन में लगे प्रतिबंध हटाने से लाखों किसान लाभान्वित हुए।

सभी राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए चिकित्सा सुविधा फ्री

योगी सरकार ने 2022 में उत्तर प्रदेश के राज्य

कर्मचारियों और पेंशनर्स व उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया, जिसका लाभ लाखों लोगों को मिलने लगा। इसके तहत, राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के स्टेट हेल्थ कार्ड बनाए गए। स्टेट हेल्थ कार्ड में कर्मचारियों व उनके आश्रितों से संबंधित सभी डाटा संरक्षित रखने की सुविधा है। इस हेल्थ कार्ड को दिखाकर वे किसी भी सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा प्राप्त कर पा रहे हैं। योजना के तहत लाभार्थियों के इलाज के लिए प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में प्रचलित दरें ही मान्य हैं।

नकल और पेपर लीक पर बनाया सख्त कानून

परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक करने और नकल के खिलाफ भी योगी सरकार ने 2024 में सख्त कानून बनाकर मिसाल पेश की। पेपर लीक कानून के तहत सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली धोखाधड़ी (नकल) पर अंकुश लगाने के लिए न्यूनतम 3 से 5 साल की कैद की सजा का प्राविधान है और पेपर लीक गिरोह में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की कैद और न्यूनतम एक करोड़ रुपए के जुमार्ने का प्राविधान है। यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कोई संगठित अपराध करता है, जिसमें परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था, सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्थान शामिल है तो उन्हें कम से कम 5 साल की कैद की सजा दी जाएगी, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन

योगी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 'उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण' के गठन को मंजूरी दे दी है। इस प्राधिकरण के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 'उत्तर प्रदेश जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली 2025' को प्रख्यापित किया गया है। देश में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना सहित कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग मौजूद हैं। जलमार्गों के जरिए परिवहन को किफायती और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से इस प्राधिकरण की स्थापना की जा रही है। सरकार का मानना है कि जल परिवहन प्रणाली विकसित होने से यातायात के अन्य साधनों पर दबाव कम होगा और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

एनसीआर की तर्ज पर एससीआर बनाने का निर्णय

योगी सरकार ने एक और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीआर) की तरह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आसपास के इलाकों को मिलाकर राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) के गठन को मंजूरी दी है। इसे उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए योगी सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। लखनऊ और आसपास के 6 जिलों के कुल 27826 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।

47 वर्षों के बाद एक और औद्योगिक शहर के गठन का फैसला

ऐतिहासिक निर्णयों की कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) की तर्ज पर बुंदेलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के गठन की अधिसूचना को भी 2023 में मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश में इससे पहले 1976 में नोएडा नाम से एक नए शहर के गठन का निर्णय लिया गया था। 47 वर्षों के बाद एक और नए नगर की स्थापना का फैसला किया गया। झांसी जिले के 33 गांवों को शामिल करके बीडा का गठन किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक निर्णय से बुन्देलखण्ड के बहुआयामी विकास को रफ्तार मिलेगी।

उत्तराखण्ड शासन

देवभूमि रजत उत्सव

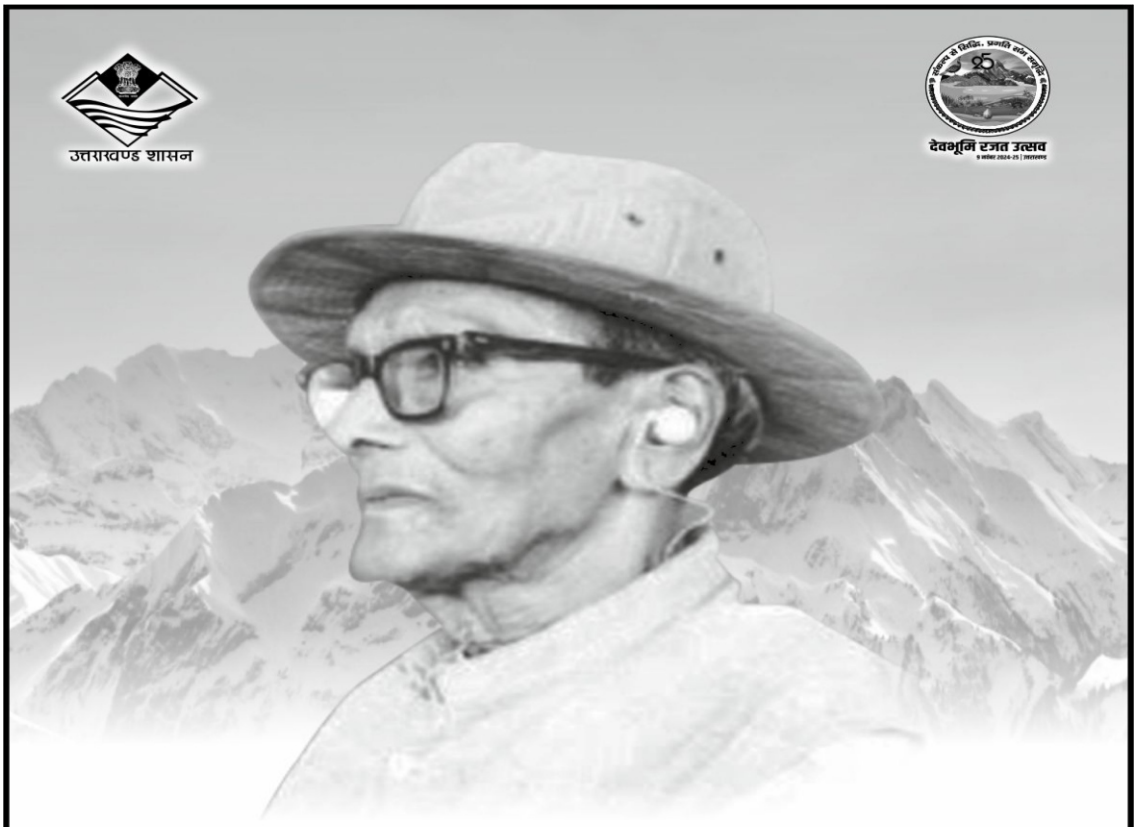

Ro2025050224732

उत्तराखण्ड की माटी में जन्मे,
भारत माँ के वीर सपूत

पेशावर कांड के नायक

स्व. वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली जी

तथा उनके साथियों को
पेशावर कांड की वर्षगांठ पर
प्रदेशवासियों की ओर से

॥ शत्-शत् नमन ॥

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी

Website: www.uttarainformation.gov.in UttarakhandDIPR DIPR_UK

होने दी। तीन नई चीनी मिलें स्थापित कीं, छह का पुनः संचालन किया और 38 का विस्तार किया। साल 2017 से अब तक 2.80 लाख करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया, जो पिछली सरकारों के 22 वर्षों के भुगतान से 60,000 करोड़ रुपये अधिक है। एथेनॉल उत्पादन 42 करोड़ लीटर से बढ़कर 177 करोड़ लीटर तक पहुंच गया।

उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था में सुधार लाना योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। साल 2017 से पहले हर तीसरे दिन दंगे होते थे। बेटियां और व्यापारी असुरक्षित थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। प्रयागराज महाकुंभ का इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 45 दिनों के इस आयोजन में कोई छेड़छाड़, लूटपाट या अपहरण की घटना नहीं हुई। साल 2017 में 1.50 लाख पुलिस पद खाली थे। डबल इंजन सरकार ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए 1,56,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की और हाल ही में 60,200 नई भर्तियां की गईं।

यही नहीं, प्रदेश के 10 जनपदों में पुलिस लाइन नहीं थी। अब सभी जगह पुलिस लाइन बन गई है। ट्रेनिंग क्षमता 6,000 से बढ़ाकर 60,244 कर दी गई। पीएसी की 54 कंपनियां पिछली सरकारों ने खत्म कर दी थीं, जिन्हें योगी सरकार ने बहाल किया। तीन महिला बटालियन और पांच नई पीएसी बटालियन गठित की गईं। साइबर थानों और हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। पीआरबी 112 का रिस्पांस टाइम 25 मिनट 42 सेकंड से घटकर 7 मिनट 24 सेकंड हो गया। 11 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाकर सेफ सिटी की परिकल्पना को साकार किया गया।

शिक्षा क्षेत्र में सुधार हुआ है। पहले नकल को जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता था। आज नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 50 लाख से अधिक बच्चों की बढ़ोतरी हुई। सभी बच्चों को 1,200 रुपये यूनिफॉर्म, बैग, किताबें, जूते और स्वेटर के लिए दिए जा रहे हैं। स्कूलों में टॉयलेट, पेयजल, डिजिटल लाइब्रेरी और फ्लोरिंग की व्यवस्था की गई। माध्यमिक स्कूलों के लिए अलंकार योजना शुरू की गई।

नारी की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन संपूर्ण समाज के स्वावलंबन का आधार है। साल 1947 से 2017 तक पुलिस बल में केवल 10,000 महिला पुलिसकर्मी थीं। लेकिन हाल की भर्ती में 12,000 और अब तक 25,000 से अधिक महिलाओं को पुलिस बल में शामिल किया गया। महिला वर्कफोर्स 14% से बढ़कर 35% से अधिक हो गई। मातृ वंदना योजना से 60 लाख माताएं लाभान्वित हुईं। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के तहत 22.11 लाख बेटियों को जन्म से स्नातक तक 25,000 रुपये की सहायता दी गई।

प्रदेश के 57,000 ग्राम पंचायतों में बीसी सखी बैंकिंग सुविधा दे रही हैं। एक करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर स्वावलंबी बनी हैं। सामूहिक विवाह योजना में 4.76 लाख विवाह संपन्न हुए, और अब इसकी राशि 51,000 से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये करने की घोषणा की गई। स्वामित्व योजना में एक करोड़ महिलाओं को मालिकाना हक दिया गया। कामकाजी महिलाओं के लिए अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर छह शहरों में हॉस्टल बनाए जा रहे हैं।

साल 2016-17 में बेरोजगारी दर 19% थी, जो आज घटकर 3% रह गई है। बीते आठ वर्षों में 8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गईं। एमएसएमई सेक्टर में 2 करोड़ से अधिक युवा स्वरोजगार से जुड़े। 50 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देकर डिजिटल सक्षम बनाया गया। 96 लाख एमएसएमई यूनिट्स के साथ उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में अग्रणी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) योजना ने परंपरागत उद्यमिता को बढ़ावा दिया। निर्यात 86,000 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के तहत 31 मार्च तक 1 लाख नए युवा उद्यमी बनाने का लक्ष्य है, जिसमें 5 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त और गारंटी मुक्त लोन दिया जा रहा है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत हस्तशिल्पियों को स्किल डेवलपमेंट और टूलकिट्स दी गईं।

शिक्षा क्षेत्र में सुधार हुआ है। पहले नकल को जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता था। आज नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 50 लाख से अधिक बच्चों की बढ़ोतरी हुई। सभी बच्चों को 1,200 रुपये यूनिफॉर्म, बैग, किताबें, जूते और स्वेटर के लिए दिए जा रहे हैं। स्कूलों में टॉयलेट, पेयजल, डिजिटल लाइब्रेरी और फ्लोरिंग की व्यवस्था की गई। माध्यमिक स्कूलों के लिए अलंकार योजना शुरू की गई। छह कमिश्नरियों में नए राज्य विश्वविद्यालय, मेडिकल यूनिवर्सिटी, आयुष विश्वविद्यालय और एक अतिरिक्त एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 10 नए विश्वविद्यालय और 21 निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। प्रत्येक जनपद में मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग

किसानों को मिली राहत

- 36,000 करोड़ रुपये की कर्जमाफी से किसानों को राहत मिली।
- पीएम किसान सम्मान योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से सीधा लाभ पहुंचाया गया।
- 23 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई।
- 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र और एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।
- गन्ना किसानों के लिए 2.80 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
- पीएम कुसुम योजना के तहत 86,000 किसानों को सोलर पैनल का लाभ मिला।
- 14 लाख निजी नलकूपों को मुफ्त बिजली दी गई।

चीनी उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव

- 2017 से पहले चीनी उद्योग बंद होने की कगार पर था, लेकिन अब 3 नई चीनी मिलें स्थापित की गईं।
- 6 चीनी मिलों को पुनः चालू किया गया।
- 38 चीनी मिलों का विस्तार हुआ।
- वर्तमान में 122 चीनी मिलें क्रियाशील हैं।

क ानून व्यवस्था में ऐतिह ासिक सुधार

- महाकुंभ में 45 दिनों के आयोजन के दौरान एक भी अपराध नहीं हुआ।
- पुलिस बल में 1.56 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई।
- 60,200 पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था में सुधार लाना योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। साल 2017 से पहले हर तीसरे दिन दंगे होते थे। बेटियां और व्यापारी असुरक्षित थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। प्रयागराज महाकुंभ का इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 45 दिनों के इस आयोजन में कोई छेड़छाड़, लूटपाट या अपहरण की घटना नहीं हुई। साल 2017 में 1.50 लाख पुलिस पद खाली थे। डबल इंजन सरकार ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए 1,56,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की और हाल ही में 60,200 नई भर्तियां की गईं।

शुरू की गई। अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी छात्रों को 100% स्कॉलरशिप दी जा रही है।

पिछले 8 वर्षों में 6 करोड़ से अधिक गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया। 15 करोड़ लोग पिछले 5 वर्षों से मुफ्त राशन प्राप्त कर रहे हैं। 1.86 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन दिए गए। होली और दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर दिए जा रहे हैं। 9 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड दिए गए। 56 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध कराए गए। साल 2017 से पहले 55 लाख निराश्रित महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगों को पेंशन मिलती थी। आज यह संख्या 1.06 करोड़ हो गई है। पेंशन राशि 300 से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी गई। साल 2024-25 में 9.08 करोड़ लोगों को 1.10 लाख करोड़ रुपये डीबीटी के जरिए दिए गए, जिससे 10,000 करोड़ रुपये की बचत हुई।

उत्तर प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तेजी के साथ प्रगति की है। पहले कहा जाता था कि जहां गड्ढे शुरू हो जाएं, समझो उत्तर प्रदेश आ गया। आज यूपी एक्सप्रेसवे का पर्याय बन गया है। आज 6 एक्सप्रेसवे संचालित हैं और 11 पर काम चल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद देश के 55% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में होंगे। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है। सर्वाधिक मेट्रो संचालन यूपी में हो रहा है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली-मेरठ के बीच और पहला वॉटरवे हल्दिया-वाराणसी के बीच शुरू हुआ। वाराणसी से प्रयागराज और बलिया से अयोध्या तक वॉटरवे की सुविधा बढ़ाई जा रही है। हर जनपद मुख्यालय फोरलेन से जुड़ा है। 2017 में 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, आज 16 एयरपोर्ट हैं, जिनमें 4 इंटरनेशनल हैं। जेवर में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जल्द शुरू होगा। लैंडलॉक्ड स्टेट से उत्तर प्रदेश मुक्त हो चुका है।

प्रदेश के अंदर नगरीय विकास के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं। 2016-17 में देश के 10 सबसे गंदे शहर यूपी के थे। आज 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्मार्ट सिटी बन चुके हैं। इस बार के बजट में हर जिला मुख्यालय की नगर पालिका को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है। लखनऊ, वाराणसी और कानपुर को स्टेट डेवलपमेंट रीजन के रूप में विकसित किया जा रहा है। वाराणसी में देश की पहली रोप-वे

सेवा जल्द शुरू होगी।

साल 1947 से 2017 तक 1,28,494 मजरों तक बिजली पहुंची थी। पिछले 8 वर्षों में 1,21,000 मजरों को बिजली दी गई। 2012-17 में 8.44 लाख बिजली कनेक्शन दिए गए, जबकि 2017-24 में 1.65 करोड़ गरीबों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 20 घंटे और जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। पावर जेनरेशन में 6,000 मेगावाट से बढ़कर 33,000 मेगावाट की आपूर्ति हो रही है। सौर ऊर्जा में 228 मेगावाट से बढ़कर 2,653 मेगावाट उत्पादन हो रहा है।

बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के जरिए 4,000 मेगावाट सोलर पावर की स्थापना हो रही है और अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी का लक्ष्य है।

साल 2017 से पहले इज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी 14वें स्थान पर था। आज टॉप अचीवर स्टेट है। 33 सेक्टोरियल पॉलिसी और सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए 500 से अधिक एनओसी एक प्लेटफॉर्म पर दी जा रही हैं। 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की निवेश परियोजनाएं जमीनी धरातल पर उतारी गईं। आज उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन बन गया है।

साल 1947 से 2017 तक केवल 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। आज 80 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 44 सरकारी हैं।

उत्तर प्रदेश ने टूरिज्म के क्षेत्र में भी एक लंबी छलांग लगाई है। यूपी के अलग-अलग क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों का असर यूपी के पर्यटन क्षेत्र में भी देखने को मिला है। 2017 से पहले 21 करोड़ पर्यटक आते थे, उसमें स्पिरिचुअल भी होता था इको टूरिज्म भी होता था हेरिटेज भी होता था और अन्य तमाम आयोजन के साथ भी जुड़ते थे आज यह संख्या बहुत बड़ी हो चुकी है। 2023 में 67 करोड़ पर्यटक आए। प्रयागराज महाकुंभ में भी 67 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। आस्था अब अर्थव्यवस्था का सशक्त माध्यम बन गई है।

प्रदेश के अंदर इससे पहले नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या थी ताले लटकते थे। ना इंफ्रास्ट्रक्चर था ना फैकल्टी थी, आज प्रदेश के अंदर हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज बनाने की कार्यवाही को तेजी के साथ आगे बढ़ने का कार्य हो रहा है।

प्रदेश के अंदर 36 जनपद ऐसे थे जिनमें संचारित रोग में खास तौर पर इंसेफेलाइटिस थे, उत्तर प्रदेश के मासूम तड़प तड़प कर मरते थे आज उसे पर प्रभावी नियंत्रण करने में उत्तर प्रदेश में सफलता प्राप्त की है। इंसेफेलाइटिस पर 85% और जापानी इंसेफेलाइटिस पर 99% नियंत्रण हासिल किया गया। डेंगू मृत्यु दर 95% और मलेरिया 56% कम हुआ। आयुष्मान भारत योजना में यूपी नंबर एक है। एमबीबीएस सीटें 1,990 से बढ़कर 5,250 और पीजी सीटें 741 से बढ़कर 1,871 हो गईं।

उत्तर प्रदेश ने टूरिज्म के क्षेत्र में भी एक लंबी छलांग लगाई है। यूपी के अलग-अलग क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों का असर यूपी के पर्यटन क्षेत्र में भी देखने को मिला है। 2017 से पहले 21 करोड़ पर्यटक आते थे, उसमें स्पिरिचुअल भी होता था इको टूरिज्म भी होता था हेरिटेज भी होता था और अन्य तमाम आयोजन के साथ भी जुड़ते थे आज यह संख्या बहुत बड़ी हो चुकी है। 2023 में 67 करोड़ पर्यटक आए। प्रयागराज महाकुंभ में भी 67 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। आस्था अब अर्थव्यवस्था का सशक्त माध्यम बन गई है। कनेक्टिविटी, सुरक्षा और सुविधाओं के विकास ने पर्यटन को बढ़ावा दिया। डबल इंजन की सरकार ने काफी बड़े पैमाने पर अवस्थापना सुविधाओं का विकास भी किया है। आज उसका परिणाम हम सभी के सामने है।

पिछले 8 वर्ष में हमने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। इसके लिए भ्रष्टाचार पर प्रभावी प्रहार किया, लीकेज को रोकना, सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाकर रेवेन्यू बढ़ाई हैं और परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश देश का एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। 2017 में यूपी की अर्थव्यवस्था 12.75 लाख करोड़ रुपये थी, जो आज 27.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई। प्रति व्यक्ति आय 46,000 से बढ़कर 1,24,000 रुपये हो गई। साल 2000 से 2017 तक 3,300 करोड़ रुपये का एफडीआई आया, जबकि 2017-24 में 14,808 करोड़ रुपये का एफडीआई आया। बैंकिंग व्यवसाय 12.30 लाख करोड़ से बढ़कर 29.66 लाख करोड़ रुपये हो गया। सीडी रेशियो 46% से बढ़कर 61% हो गया।

प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए फंड आकर्षित करने में 16.2 % हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश से देश के अंदर शीर्ष स्थान पर है। मुंबई स्टॉक में 132 कंपनियों ने केवल उत्तर प्रदेश की है, जो जिन्होंने वहां पर पंजीकरण कराया और जिनका मार्केट कैपिटल 368162 करोड रुपए से अधिक का है। वह प्रदेश के अंदर 2017 तक कुछ 13000 फैक्ट्रियां आज इनकी संख्या इन 8 वर्ष इनकी संख्या बढ़कर के 26900 से अधिक है। यह संख्या बताती है कि उत्तर प्रदेश एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ा है। खाद्यान्न, गन्ना, आलू, इथेनॉल उत्पादन, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, आयकर रिटर्न, जेम पोर्टल खरीद, कौशल विकास, एमएसएमई, पीएम आवास, उज्ज्वला, स्वामित्व, जन धन, सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा योजना में यूपी नंबर एक है।

सुपर फूड जैसा है अंकुरित भोजन

शरीर में प्रोटीन की कमी होने पर थकान महसूस होती हैं। ऐसे में लोग सप्लीमेंट के तौर पर प्रोटीन लेना शुरू करते हैं। नतीजा हमारे स्वास्थ्य पर उनका बुरा प्रभाव पड़ता है। जबकि प्रोटीन का भी विकल्प मौजूद है। दरअसल, स्प्राउट्स ऐसी चीज है, जिसके खाने से कभी परेशानी नहीं होती। यह प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व व प्रोटीन से भरा है। नट्स, अनाज और फलियों को जब पानी में डाला जाता है तो इनमें मौजूद फाइटेट्स खत्म हो जाते हैं। जिससे इसे पचाने में बेहद आसानी होती है। किसी भी अनाज को जब अंकुरित किया जाता है, तो उसमें मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन और अन्य पोषक तत्व अच्छी तरह अवशोषित हो जाते हैं।

जहां तक एंटी-आक्सीडेंट की बात है तो स्प्राउट्स में प्रचुर मात्रा में एंटी-आक्सीडेंट पाए जाते हैं। एंटी-आक्सीडेंट शरीर की प्रक्रिया के सही ढंग से चलाने में सहायक होते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम मंहगी से महंगी दवाइयां खरीद लेते हैं पर अपना देसी और सस्ता इलाज भूल जाते हैं। जबकि स्प्राउट्स सबसे बढ़िया व सस्ता विकल्प हैं अपने आप को स्वस्थ रखने का चना, मूंग, राजमा और मटर को रात भर पानी में डाल कर रखें और अगले दिन इसे सब्जी के साथ पका कर या फिर अंकुरित कर खा सकते हैं। स्प्राउट्स बनाने की विधि कच्चे अनाज को सुपर फूड बना देती है। उनमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन की मात्रा काफी बढ़ जाती है।

लंबे समय तक स्वस्थ रहने का सबसे अचछा तरीका है स्प्राउट्स। यह हमें कई तरह की बीमारियों और लाइफस्टाइल संबंधी परेशानी से बचाती है। स्प्राउट्स को पोषक तत्वों का बंडल भी कहा जाता है। अनाज जैसे गेहूं, मक्का रागी, बार्ली और बाजरे को 12 घंटे पानी में भिगोकर मिट्टी में डाल दिया जाता हैं। इनके नन्हें पौधे 10-12 दिनों में तैयार हो जाते हैं। इनका जूस सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। तिल, मूली और मेथी के बीज खाने में तो कड़वे होते हैं, पर इन्हें स्प्राउट्स के साथ मिलाकर खाया जा सकता हैं। हरे और काले चने, के स्प्राउट्स के साथ-साथ ओट्स, बकवीट में उच्च मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं।

अलफा अलफा को स्प्राउट्स का राजा कहा जाता है। इसमें मैंग्नीज की उच्च मात्रा पाई जाती हैं और साथ में विटामिन ए, बी, सी, ई और के की प्रचुर मात्रा भी होते हैं। इसमें एमिनो एसिड और दूध से काफी ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है।

स्प्राउट्स में प्रोटीन, कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, आयरन, फास्फोरस, विटामिन ए, थाइमिन या विटामिन बी-1, बी-2, बी-3, विटामिन सी मौजूद होते हैं, जो हमारे शरीर की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते हैं। यह क्लोरोफिल का अच्छा स्रोत है और इसमें एंटीबैक्टेरियल व एंटीइनफ्लैमेटरी गुण मौजूद होते हैं। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो स्प्राउट्स से बेहतर कुछ नहीं। इसे खाने से पेट भरा-भरा सा रहता है और काफी दूर तक भूख नहीं लगती।

हिन्दी विरोध के पीछे की राजनीति

किशोर कुमार मालवीय

नई शिक्षा नीति पर विरोध के मामले में तमिलनाडू के मुख्यमंत्री स्टालिन की गोलबंदी ने अब हिन्दी विरोध का रुप ले लिया है। हालांकि तमिलनाडू या दूसरे दक्षिण भारतीय राज्यों की जनता को हिन्दी से परहेज या नफरत नहीं जैसा कि बताने और बनाने की सियासी कोशिश की जा रही है। फिर क्या है इस विरोध के पीछे की राजनीति? क्या ये महज हिन्दी का विरोध है या उन्हें पूरी नई शिक्षा नीति से दिक्कत है? या साफ साफ शब्दों कहें तो क्या उन्हें इन दोनो से ज्यादा केन्द्र की मोदी सरकार से दिक्कत है? पूरा घटनाक्रम देखें तो तीसरी वजह ज्यादा करीब लगती है। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि इस पूरी राजनीति में कांग्रेस फंस गई है। उसका हाल सांप-छुछुंदर वाला हो गया है।

सबसे पहले ये जानना जरुरी है कि नई शिक्षा नीति में ऐसा क्या है जिससे तमिलनाडू के मुख्यमंत्री इतना उबल रहे हैं। या केवल क्षेत्रीय राजनीति की जरुरत को ध्यान में रख कर वे नीति में दोष निकाल कर आरोप लगा रहे हैं। स्टालिन आरोप लगा रहे हैं कि नई शिक्षा नीति में 3-भाषा फॉर्मूला गैर हिन्दी राज्यों पर जबरन हिन्दी थोपने की साजिश है। काफी लम्बे समय से हिन्दी का विरोध करने वाले तमिलनाडू में 2-भाषा फॉर्मूला लागू है - तमिल और अंग्रेजी। मतलब सात समंदर पार वाली अंग्रेजी से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। नई नीति में 3-भाषा फॉर्मूला में इन दो भाषाओं के अलावा हिन्दी को एक विकल्प के रुप में रखा गया है। मतलब, हिन्दी पढ़ना जरुरी नहीं बल्कि अगर कोई चाहे तो पढ़ सकते हैं। तमिलनाडू के साथ साथ केरल, कर्नाटक और तेलंगाना ने भी केन्द्र पर हिन्दी और संस्कृत को जरुरत से ज्यादा महत्व देने का आरोप लगाया है। हालांकि, उन्होंने नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से नहीं नकारा है।

> **हिन्दी विरोध पर राजनीति करने वाले स्टालिन का एक आरोप ये भी है कि नई शिक्षा नीति केन्द्र को शिक्षा पर नियंत्रण का अधिकार देता है। यानी ये शिक्षा के केन्द्रीयकरण की कोशिश है। इससे राज्यों की स्वायत्ता खतरे में पड़ सकती है। उनका तर्क है कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जिसपर केन्द्र और राज्य दोनों का समान अधिकार है जबकि नई नीति केन्द्र को ज्यादा अधिकार देती है।**

हिन्दी विरोध पर राजनीति करने वाले स्टालिन का एक आरोप ये भी है कि नई शिक्षा नीति केन्द्र को शिक्षा पर नियंत्रण का अधिकार देता है। यानी ये शिक्षा के केन्द्रीयकरण की कोशिश है। इससे राज्यों की स्वायत्ता खतरे में पड़ सकती है। उनका तर्क है कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जिसपर केन्द्र और राज्य दोनों का समान अधिकार है जबकि नई नीति केन्द्र को ज्यादा अधिकार देती है।

सच ये है कि नई नीति में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे राज्यों के अधिकारों में थोड़ी भी कमी की गई हो। हां, केन्द्र की ओर से कुछ सुविधाएं जरुर दी गई हैं, जिनका स्वागत होना चाहिए। उदाहरण के लिए, तमिलनाडू सहित कुछ दक्षिणी राज्यों को समान प्रवेश परीक्षा से समस्या है। देश भर के विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए नई शिक्षा नीति में नैशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराने का प्रस्ताव है। प्रोफेशनल कोर्सेज में ये पहले से लागू है पर किसी को आपत्ति नहीं है।

अब वे कह रहे हैं कि राज्य शिक्षा बोर्ड से पास हुए छात्रों को इससे दिक्कत

होगी जो एनसीइआरटी सिलेबस से परिचित नहीं हैं।

राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद के गठन को कुछ राज्य नीति निर्धारण में राज्यों के अधिकारों में कटौती के रुप में देख रहे हैं।

केन्द्र सरकार के खिलाफ गोलबंद हुए राज्यों का एक आरोप ये भी है कि नई शिक्षा नीति तमिलनाडू और केरल जैसे राज्यों में शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायिकरण को बढ़ावा देगी, जिससे वंचित समुदाय के लिए शिक्षा महंगी और पहुंच से दूर हो जाएगी। लेकिन असलियत ये है की पुरानी नीति में भी प्राइवेट कॉलेज या विश्वविद्यालय खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आज पूरे देश में प्राइवेट कॉलेजों का जाल बिछा हुआ है, जो पूरी तरह व्यवसायिक हैं और फीस के नाम पर मोटी रकम वसुलते हैं। फिर भी, वंचित समाज के बच्चे शिक्षा से वंचित नहीं हैं, क्योंकि उनके लिए सरकारी कॉलेजों का विकल्प खुला है, जो नई नीति के बाद भी जारी रहेगा। जहां तक प्राइवेट और व्यवसायिक कॉलेज या यूनिवर्सिटी खोलने का सवाल है, उसमें राज्यों की भूमिका में कोई कटौती नहीं की गई है। फिर कुछ राज्य सरकार बच्चों को मनपसंद कॉलेज चुनने के अधिकार से क्यों वंचित रखना चाहती है। उन्हें स्व वित्तीय संस्थानों से आपत्ति है, क्योंकि ये सरकार प्रदत्त संस्थानों की अवधारणा के खिलाफ है। ये बात किसा से छिपी नहीं है कि राज्य सरकारों के पास संसाधनो की कमी होने से वे शिक्षा को अपग्रेड नहीं कर पा रहे।

गैर भाजपा शासित राज्यों को नई शिक्षा नीति से सबसे ज्यादा परेशानी इस बात पर है कि इससे क्षेत्रीय पहचान को खतरा है। नई नीति में भारतीय ज्ञान पद्धति पर जोर दिया गया है, जिससे तमिलनाडू को लगता है कि ये विविध परम्परा और इतिहास के खिलाफ है और उन्हें पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है। दक्षिणी राज्यों को आशंका है कि इससे क्षेत्रीय साहित्य, इतिहास और संस्कृति साइडलाइन हो जाएगी। ये आशंका अपने आप में हास्यास्पद है क्योंकि भारतीय ज्ञान पद्धति से क्षेत्रीय साहित्य, संस्कृति और इतिहास को अलग नहीं किया जा सकता है।

तमिलनाडू के आरोपों का भाजपा और केन्द्र सरकार ने भी जवाब दिया है। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनके पास राजभाषा विभाग भी है, ने स्टालिन को चुनौती दी है कि अगर सचमुच वे तमिल भाषा के लिए चिंतित हैं तो अपने राज्य मे सभी मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्सेस की पढ़ाई तमिल में शुरू कराएं। उन्होंने स्टालिन पर भारतीय भाषाओं का अपमान कर विदेशी भाषा का पक्ष लेने का आरोप भी लगाया है। स्टालिन को हजारों किलोमीटर दूर की भाषा अंग्रेजी पसंद है पर हिन्दी नहीं, वो भी राज्य की तीसरी वैकल्पिक भाषा के रुप में।

तमिलनाडू के साथ केरल को भी चार साल के अंडर ग्रैजुएट कार्यक्रम से परेशानी है। तर्क ये है कि इससे ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ेगी और छात्रों पर पढ़ाई का खर्च भी बढ़ेगा। वैसे, ड्रॉप आउट का इससे कोई लेना देना नहीं है।

तमिलनाडू ने नई शिक्षा नीति को पुरी तरह से नकार दिया है, जबकि केरल ने इसे आंशिक रुप से स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस शासित कर्नाटक और तेलंगाना ने स्वीकार तो किया है, पर विरोध में तमिलनाडू के साथ खड़े हैं। कांग्रेस ने मोदी सरकार के विरोध के लिए स्टालिन का साथ दिया है क्योंकि उसे भाजपा के खिलाफ एक मौका हाथ लग गया है। तमिलनाडू में अगले साल विधानसभा चुनाव है, तब तक सभी विपक्षी पार्टियां इस मामले को जीवित रखना चाहती है ताकि भाजपा के तमिलनाडू में बढ़ रहे प्रभाव को रोका जा सके। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार और तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने खुलकर स्टालिन का समर्थन किया है और सभी गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों को नई शिक्षा नीति के विरोध में लामबंद कर रहे हैं।

मुश्किल ये है कि कांग्रेस के हिन्दी विरोध का उत्तर भारत में उनके अपने लोग ही विरोध कर रहे हैं। पहले हिन्दू विरोधी छवि बनाने के बाद अब कांग्रेस हिन्दी विरोधी छवि बनाने में जुटी है, जिसका खमियाजा उसे उत्तर भारत में भुगतना पड़ सकता है।

तमिलनाडू के आरोपों का भाजपा और केन्द्र सरकार ने भी जवाब दिया है। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनके पास राजभाषा विभाग भी है, ने स्टालिन को चुनौती दी है कि अगर सचमुच वे तमिल भाषा के लिए चिंतित हैं तो अपने राज्य मे सभी मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्सेस की पढ़ाई तमिल में शुरू कराएं। उन्होंने स्टालिन पर भारतीय भाषाओं का अपमान कर विदेशी भाषा का पक्ष लेने का आरोप भी लगाया है। स्टालिन को हजारों किलोमीटर दूर की भाषा अंग्रेजी पसंद है पर हिन्दी नहीं, वो भी राज्य की तीसरी वैकल्पिक भाषा के रुप में। हिन्दी सभी भारतीय भाषाओं की मित्र है, प्रतिद्वन्दी नहीं।

आप ने बदला रुख : किसान आंदोलन पर कड़ा एक्शन?

अजय कुमार

पंजाब में किसान आंदोलन को लेकर लगातार बदलते घटनाक्रम ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हुई पुलिस की कार्रवाई और बुलडोजर एक्शन से किसान संगठनों में गहरा असंतोष फैल गया है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार, जो अब तक किसानों के समर्थन का दावा करती रही थी, अचानक ही उनके खिलाफ नजर आ रही है। इसका असर यह हुआ कि न केवल किसान, बल्कि विपक्षी दल भी भगवंत मान सरकार पर हमलावर हो गए हैं। बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर पंजाब सरकार ने अचानक किसानों के मामले में यू-टर्न क्यों लिया?

लंबे समय से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पंजाब पुलिस ने 19 मार्च को हिरासत में ले लिया। उनके साथ-साथ किसान मजदूर मोर्चा के प्रमुख सरवन सिंह पंढेर और आंदोलन में शामिल अन्य किसानों को भी मोहाली में हिरासत में लिया गया। ये सभी किसान नेता चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करके लौट रहे थे, जब पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस ने देर रात शंभू और खनौरी बॉर्डर को खाली करा दिया। आंदोलनरत किसानों के स्थायी और अस्थायी ढांचों को भी बुलडोजर से हटा दिया गया। पंजाब सरकार के इस कड़े रुख ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी शुरू से ही किसानों के समर्थन में खड़ी रही है।

भगवंत मान का बदला हुआ रुख हैरान करने वाला है। शुरूआत में पंजाब सरकार ने कोर्ट में किसानों के पक्ष में दलील दी थी कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, तो इससे देशभर में अशांति फैल सकती है। इसके बावजूद

लंबे समय से अनशन पर बैठे किसान नेताओं को पंजाब पुलिस ने पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस ने देर रात शंभू और खनौरी बॉर्डर को खाली करा दिया। आंदोलनरत किसानों के स्थायी और अस्थायी ढांचों को भी बुलडोजर से हटा दिया गया। पंजाब सरकार के इस कड़े रुख ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी शुरू से ही किसानों के समर्थन में खड़ी रही है।

सरकार ने किसान नेताओं के साथ बातचीत जारी रखी, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर कमेटी भी बनाई, लेकिन फिर भी समाधान नहीं निकला। किसानों का विरोध लगातार जारी रहा, खासकर जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया था।

10 जुलाई 2024 को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि एक हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर को खोला जाए। हालांकि, हरियाणा सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, लेकिन अब पंजाब सरकार ने खुद ही बॉर्डर को खाली करा दिया है। यह फैसला इसलिए चौंकाने वाला है, क्योंकि 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था और उनके साथ खड़े रहने का वादा किया था। किसानों के समर्थन के चलते आम आदमी पार्टी को पंजाब में सत्ता भी मिली थी।

शुरूआती दौर में पंजाब सरकार किसान आंदोलनकारियों का समर्थन करती दिखी और केंद्र सरकार पर निशाना साधती रही, लेकिन अब उसी पंजाब सरकार ने किसानों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर दी है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस मामले पर कहा कि सरकार शंभू और खनौरी बॉर्डर को खोलना चाहती है, ताकि राज्य में सुचारू यातायात व्यवस्था बनी रहे। उनका यह भी कहना था कि किसानों को विरोध-प्रदर्शन के लिए दिल्ली जाना चाहिए, क्योंकि उनकी मांगें केंद्र सरकार से जुड़ी हुई हैं।

किसानों का कहना है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की किसानों से निजी खुन्नस हो सकती है, जिसकी वजह से यह कार्रवाई हुई है। मार्च की शुरूआत में पंजाब सरकार और किसान नेताओं के बीच एक बैठक हुई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ में प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसका विरोध किया। बैठक के दौरान किसानों और मुख्यमंत्री के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद भगवंत मान ने गुस्से में बैठक छोड़ दी और कहा कि अब कुछ नहीं होगा। इसके तुरंत बाद पंजाब पुलिस ने किसानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी।

इसके अगले ही दिन भगवंत मान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने बैठक छोड़ी थी और सरकार किसानों को हिरासत में लेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि किसानों को रेलवे ट्रैक और सड़कों पर धरना देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद पुलिस ने कई किसान नेताओं को उनके गांवों में ही रोक लिया। बलबीर सिंह राजेवाल और जोगिंदर उगराहां समेत कई बड़े किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद पंजाब पुलिस ने बॉर्डर पर भी कड़ा एक्शन लिया। इस पूरे घटनाक्रम से यह समझना मुश्किल हो रहा है कि क्या यह कार्रवाई केवल भगवंत मान की नाराजगी के कारण हुई या फिर इसके पीछे अरविंद केजरीवाल का भी कोई निर्देश था।

अगर पंजाब सरकार को यह पता था कि किसानों की मांगें केंद्र सरकार से जुड़ी हैं, तो यह कार्रवाई पहले ही क्यों नहीं हुई? अगर सरकार पहले ही कदम उठा लेती, तो यह विवाद इतना बड़ा नहीं बनता। इससे आम आदमी पार्टी और भगवंत मान विपक्षी दलों के निशाने पर आने से बच सकते थे।

विशेषज्ञों का मानना है कि पंजाब सरकार इस पूरे मुद्दे पर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रही है। पहले भी ऐसा देखा गया था, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे। उस समय उन्होंने किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर भेज दिया था और केंद्र सरकार को ही इसका समाधान निकालने के लिए मजबूर कर दिया था। तब केंद्र सरकार को काफी आलोचनाओं

पंजाब सरकार की कार्रवाई से आम आदमी पार्टी को राजनीतिक नुकसान हो सकता है। 2022 में किसानों के समर्थन के दम पर सत्ता में आई यह पार्टी अब उन्हीं किसानों के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है। ऐसे में किसान संगठनों की नाराजगी भविष्य में आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है।

का सामना करना पड़ा था और अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। लेकिन इस बार मामला उल्टा नजर आ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवंत मान और उनकी सरकार खुद ही इस विवाद को अपने सिर ले रही है।

राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी हो रही है कि किसानों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की एक वजह लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर संभावित उपचुनाव भी हो सकता है। खबरों के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल को लुधियाना के व्यापारियों से यह फीडबैक मिला था कि अगर किसानों का प्रदर्शन जारी रहा, तो वे आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे। इससे व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हो रहा था। इसी कारण पंजाब सरकार ने बॉर्डर खाली कराने का फैसला लिया। हालांकि, यह उपचुनाव अभी कब होगा, इसका भी कोई ठोस संकेत नहीं मिला है।

ऐसी भी संभावना थी कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ-साथ लुधियाना वेस्ट सीट पर उपचुनाव हो सकता है। अगर ऐसा होता, तो आम आदमी पार्टी किसानों से बातचीत कर इस मामले का शांतिपूर्ण हल निकाल सकती थी। लेकिन सरकार ने जल्दबाजी में किसानों के खिलाफ कार्रवाई कर दी, जिससे मामला और बिगड़ गया।

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि हाल ही में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल की जमानत को चुनौती दी है। ऐसे में कुछ लोग मान रहे हैं कि इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए भी यह कार्रवाई हो सकती है।

पंजाब सरकार की इस कार्रवाई से आम आदमी पार्टी को राजनीतिक नुकसान हो सकता है। 2022 में किसानों के समर्थन के दम पर सत्ता में आई यह पार्टी अब उन्हीं किसानों के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है। ऐसे में किसान संगठनों की नाराजगी भविष्य में आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है।

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, भगवंत मान सरकार ने इस मामले में जो जल्दबाजी दिखाई, वह नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर सरकार इस मसले को सुप्रीम कोर्ट के निदेर्शों के आधार पर हल करने देती, तो पंजाब सरकार पर कोई दोष नहीं आता। लेकिन अब सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसानों के खिलाफ इतना सख्त एक्शन क्यों लिया गया। पूरे घटनाक्रम को देखते हुए कहा जा सकता है कि मामला पूरी तरह से राजनीतिक है और इसके पीछे कोई न कोई रणनीति जरूर है।

क्रूर एवं आक्रांता मुगल शासक हमारे आदर्श कैसे?

प्रमोद शर्मा

मुगल बादशाह औरंगजेब की क्रूरता, अत्याचार एवं यातनाएं एक बार फिर बॉलीवुड की फिल्म छावा के कारण सुर्खियों में है। इस बार मामला सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है बल्कि राजनीति में भी गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल ला दिया है एवं देश के बहुसंख्य समाज की भावनाओं को आहत किया है। भारत में आज भी एक ऐसा वर्ग है जो इस्लामिक कट्टरता के साथ जुड़ने में गर्व एवं गौरव की अनुभूति करता है, भले ही इससे देश की एकता एवं अखण्डता क्षत-विक्षत होती हो। इस्लाम के नाम पर जिसने हजारों हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया, तलवार की नोक पर बड़ी संख्या में लोगों को जबरन मुसलमान बनाया, ऐसे क्रूर एवं सांप्रदायिक शासक औरंगजेब को नेकदिल और महान शासक बताना, आखिर किस तरह की सोच है? भारत के अतीत को जघन्य अपराधों, कट्टरतावादी सोच एवं यातनाओं से सींचने वाले मुगल शासकों के प्रति यह कैसा मोह एवं ममत्व है? हिन्दू धर्म एवं संस्कृति पर आक्रमण करने वाले हमारे आदर्श कैसे हो सकते हैं? भारत की सांस्कृतिक विरासत एवं समृद्धि को कुचलने वाले महान शासक कैसे हो सकता है? इन प्रश्नों को लेकर देशभर में छिड़ी बहस हमें आत्मावलोकन एवं मंथन का अवसर दे रही है।

फिल्म 'छावा' कोरी फिल्म ही नहीं, हिन्दुओं को संगठित करने का अभियान है, जिसने औरंगजेब के क्रूर एवं बर्बर चरित्र को प्रस्तुत किया है, यह फिल्म मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक और छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी महाराज की जिंदगी पर आधारित है। फिल्म में संभाजी के साहस, बलिदान और औरंगजेब के अत्याचारों को दिखाया

समाजवादी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र विधायक अबू आजमी ने फिल्म छावा में इतिहास को गलत ढंग से पेश करने का आरोप लगाते हुए औरंगजेब की तारीफ करके विवाद को और हवा दे दी। आजमी ने कहा, औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था। उसने कई मंदिर बनवाए और उसके शासन में भारत सोने की चिड़िया था।

गया है। संभाजी को औरंगजेब ने छलपूर्वक 1689 में क्रूरता से मरवा दिया था, जिसे फिल्म में भावनात्मक ढंग से पेश करने की सफल एवं सार्थक कोशिश हुई है। इस फिल्म में समाजवादी पार्टी के नेता और महाराष्ट्र विधायक अबू आजमी ने इतिहास को गलत ढंग से पेश करने का आरोप लगाते हुए औरंगजेब की तारीफ करके विवाद को और हवा दे दी। आजमी ने कहा, औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था। उसने कई मंदिर बनवाए और उसके शासन में भारत सोने की चिड़िया था। आजमी ने यह भी दावा किया कि औरंगजेब और संभाजी के बीच की लड़ाई धार्मिक नहीं, बल्कि सत्ता की थी। इस तरह मुगल आक्रांताओं की तारीफ करना सपा के डीएनए में है। हो सकता है आजमी का यह औरंगजेब प्रेम एवं मुस्लिम कट्टरतावादी सोच हो, लेकिन औरंगजेब ने संभाजी महाराज को 40 दिनों तक जो यातनाएं दीं, वह क्या थी? उनकी आंखें निकाली गईं, जीभ काटी गई, उनके शरीर को लहूलुहान करके उस पर नमक छिडका और फिर उनकी हत्या कर दी गई, इस तरह क्रूरता एवं बर्बरता बरतने वाले शासक को कैसे आदर्श कहा जाये? असंख्य महिलाओं एवं बच्चों पर अत्याचार करना, जबरन धर्म परिवर्तन कराना, हिन्दू मन्दिरों को तोड़ना, देश की समृद्धि का गलत उपयोग करना कैसे प्रेरणास्पद हो सकता है?

औरंगजेब पोत राज्यों, राजपूताना और मराठा शासकों के परिवारों का अपहरण कर लेता था और उन्हें बंधक बना लेता था। ताकि वह निर्विरोध शासन करते हुए सम्पूर्ण भारत पर आधिपत्य कर सके। उसने सभी गैर-मुस्लिम प्रजा और पोत राज्यों से धार्मिक असहिष्णुता कर 'जजिया' वसूला। औरंगजेब एक असहिष्णु, क्रूर एवं कट्टरपंथी था और उसकी कट्टरता के कारण करोड़ों लोगों को कष्ट सहना पड़ा। शांति और बहुसंस्कृतिवाद की भूमि भारत में ऐसे अत्याचारी को आदर्श नहीं बनाया जाना चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब औरंगजेब जैसे मुगल शासकों के प्रति प्रेम का प्रदर्शन उमड़ा हो, जब दिल्ली की एक सड़क का नाम औरंगजेब रोड से बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया था, तब भी बहुत हाय-तौबा मचाई गयी थी। उस समय भी अनेक लोगों ने औरंगजेब को महान शासक बताया था। जबकि इतिहासकारों ने भी दर्ज किया है छल से छत्रपति संभाजी को पकड़ने के बाद औरंगजेब ने अत्याचार एवं अमानवीयता की सभी हद पार करते हुए जुल्म किए। औरंगजेब छत्रपति संभाजी को इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर कर रहा था लेकिन छत्रपति ने सब प्रकार के कष्ट सहे लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। जब फिल्मकार ने इस सच को सिनेमा के माध्यम से सबके सामने रखा

तो अबू आजमी ने सच को स्वीकारने की बजाय इतिहास को ही झुठलाने का प्रयास किया। उनके बयान की पक्ष-विपक्ष सबने आलोचना की है। कुल मिलाकर, औरंगजेब की तारीफ करने पर चौतरफा घिरे सपा विधायक अबू आजमी को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। उनके खिलाफ दो एफआईआर भी दर्ज की गई हैं जब मामला और बिगड़ गया तो अबू आजमी ने माफी मांगी। हालांकि, उनका कहना है कि उन्होंने जो कहा, वह इतिहासकारों के हवाले से कहा। लेकिन बड़ा प्रश्न है कि वे कौन से इतिहासकार हैं जिनका हवाला अबू आजमी दे रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि अबू आजमी सरीखे कुछ चाटुकार एवं चारण लोग इतिहासकारों में भी हुए हैं, कांग्रेस के शासन में ऐसे इतिहासकारों से मुगल शासन को महिमामंडित करके लिखवाया गया एवं स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाकर हिन्दुस्तान की रग-रग में उतारा गया है। औरंगजेब जैसे तानाशाही शासकों के क्रूर चेहरे को छिपाने के लिए झूठे-सच्चे कुछ किस्सों का सहारा लिया है। परंतु ये फर्जी इतिहासकार सच को छिपा नहीं सके। सिद्धांत, सच और व्यवस्था के आधारभूत मूल्यों को मटियामेट कर सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक स्तर पर कीमत वसूलने की ऐसी कोशिशों से बहुत नुकसान हो चुका है, अब इन मनसूंबों को कामयाब नहीं होने दिया जा सकता। सत्य को ढका जाता रहा है पर स्वीकारा नहीं गया। और जो सत्य के दीपक को पीछे रखते हैं वे मार्ग में अपनी ही छाया डालते हैं, भ्रम पालते हैं, झूठ एवं फरेब के सहारे गलत को सही ठहराने की कुचेष्ठा करते हैं।

शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके बेटे संभाजी ने मराठा साम्राज्य को संभाला। उन्होंने स्वराज्य के संकल्प को ही आकार नहीं दिया बल्कि एक नवीन राज्य निर्मित किया एवं एक नवीन महत्तर महाराष्ट्र को पुनर्जीवित किया।

मराठों में साहसिक वीरता, उत्कृष्ट सहनशीलता, घोर निराशा में आशा की भावना, आत्मविश्वास, उच्च आदर्शों के प्रति निष्ठा, श्रेष्ठ सैनिक नैतिक बल, आत्म बलिदान, राष्ट्रीय और देशप्रेम की उत्कृष्ट भावना जैसे गुण विकसित किए और इससे वे इतने शक्तिशाली हो गए कि आगामी 3 पीढ़ियों में वे उत्तरी भारत में विजेता के रूप में पहुंच गए। छत्रपति शिवाजी एवं उनके वंशज देश के अस्तित्व एवं अस्मिता को कुचलने की हर कोशिश को नाकाम करते रहे हैं।

औरंगजेब की क्रूरताएं सिर्फ दुश्मनों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके शिकार उसके भाई और पिता भी हुए। इतिहासकार इरफान हबीब ने औरंगजेब की क्रूरता के अनेक किस्सों को उजागर करते हुए बताया कि मुगल सत्ता पाने की लालच में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को जेल भिजवाया। फिर दारा शिकोह को जंग में हराया। हालांकि जंग हारने के बाद दारा मैदान छोड़कर भाग गया था। लेकिन औरंगजेब ने दारा को गिरफ्तार करवाया और षडयंत्र रचकर उसकी गर्दन कलम करवा दी। औरंगजेब सिर्फ दारा शिकोह की हत्या से खुश नहीं हुआ। उसने हत्या की बाद क्रूरता की हदें भी पार की। एक भाई के साथ ऐसी क्रूरता भारतीय इतिहास में देखने को नहीं मिलती। उसने दारा का कटा हुआ सिर जेल में बंद पिता को भेजा।

मुगल शासक औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र से शुरू हुई बयानबाजी की आंच समूचे देश मे पहुंच गयी है। हिन्दुओं में गहरा आक्रोश एवं रोष है। मांग उठ रही है कि मुगल सम्राट औरंगजेब को बर्बर शासक घोषित किया जाए और भारत में उसके नाम पर रखे गए सभी सड़कों और स्थानों के नाम बदलने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। जैसाकि संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने ओसामा बिन लादेन और फ्रांसीसी व रूसी क्रांति के अवशेषों के साथ किया था। किसी भी राष्ट्र एवं समाज का निर्माण इतिहास के सच और ईमानदारी से ही बनता है। और यह सब प्राप्त करने के लिए ईमानदारी के साथ सौदा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि राष्ट्र, सरकार एवं समाज ईमानदारी से चलते एवं बनते हैं, न कि झूठे इतिहास से। सच को झुठलाना, सच को ढ़कना एवं सच की अनभिज्ञता संसार में जितनी क्रूर है, उतनी क्रूर मृत्यु भी नहीं होती। नया भारत-विकसित भारत-समृद्ध भारत को निर्मित करते हुए हमें हमारे गौरवपूर्ण सांस्कृतिक इतिहास को जीवंतता देनी होगी एवं हमारी संस्कृति एवं इतिहास को कुचलने वाले आक्रमणकारी शक्तियों के विकृत एवं विरूप चेहरों को बेनकाब करना होगा।

मुगल शासक औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र से शुरू हुई बयानबाजी की आंच समूचे देश मे पहुंच गयी है। हिन्दुओं में गहरा आक्रोश एवं रोष है। मांग उठ रही है कि मुगल सम्राट औरंगजेब को बर्बर शासक घोषित किया जाए और भारत में उसके नाम पर रखे गए सभी सड़कों और स्थानों के नाम बदलने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। जैसाकि संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने ओसामा बिन लादेन और फ्रांसीसी व रूसी क्रांति के अवशेषों के साथ किया था। किसी भी राष्ट्र एवं समाज का निर्माण इतिहास के सच और ईमानदारी से ही बनता है। सच को झुठलाना, सच को ढ़कना एवं सच की अनभिज्ञता संसार में जितनी क्रूर है, उतनी क्रूर मृत्यु भी नहीं होती।

अखाड़ा बन गया है बिहार चुनाव

मनोज कुमारमिश्र

दिल्ली के बाद बिहार चुनावी अखाड़ा बन गया है। लोक सभा चुनाव के बाद पहले हरियाणा, महाराष्ट्र और फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा के हौसले बुलंद हैं। बावजूद इसके भाजपा बिहार में फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री और जनता दल (एकी) के नेता नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। भाजपा ने बिहार में छोटे-छोटे दलों के साथ चुनाव लड़ कर देख लिया है। उसे अच्छी सफलता जद(एकी) के साथ लड़ने पर ही मिली। दूसरे, बिहार के जातीय समीकरण में भाजपा को इस गठबंधन के साथ यानि राजग(राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन) के नाम से चुनाव लड़ने में राजनीतिक लाभ भी दिख रहा है। नीतीश कुमार भी भाजपा से उपकृत हैं। 2020 के चुनाव में ज्यादा सीटें लड़ने के बावजूद जनता दल(एकी) को भाजपा से काफी कम सीटें आई। भाजपा ने बड़ा दिल दिखाते और चुनावी वादे के अनुरूप नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया था। 243 सीटों वाली विधानसभा में जद(एकी) 115 सीटें लड़ कर 43 सीटें जीती जबकि भाजपा 110 सीटें लड़कर 74 सीटें जीती। सवाल यह इस बार के लिए महत्वपूर्ण है कि राजग के घटकों में कौन कितनी सीटें पाएगा और क्या ज्यादा सीटें लाकर भी भाजपा फिर से नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएगी।

यह तो तय ही है कि पिछली बार की तरह इस बार भी मुख्य मुकाबला भाजपा, जद (एकी), चिराग पासवान की पार्टी लोजपा और जीतन राम मांझी की पार्टी हम आदि राजग के दलों और लालू यादव के

> **दावे चाहे जो किए जाएं लेकिन बिहार की सबसे बड़ी समस्या जातिवाद है,इस चुनाव में भी जातिवाद ही सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। अगर जातिवाद के बजाए विकास, रोजगार, शिक्षा आदि मुद्दे चुनाव तक मुख्य मुद्दे बन जाएं तो बिहार का कल्याण ही हो जाए और सालों से उस पर लगा गरीबी, पिछड़ेपन का ठप्पा हट जाए।**

पुत्र तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस और महागठबंधन के दलो के बीच ही होना है। सीटों और तालमेल का जितना विवाद राजग में होने की आशंका है उससे कई गुणा विवाद महागठबंधन में होता दिख रहा है। अभी तो जिस तरह की पैंतराबाजी राजद और कांग्रेस में चल रही है, उससे तो साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के वजूद पर ही सवाल उठने लगे हैं। 2020 विधानसभा और 2024 लोक सभा चुनाव में बिहार में इन दलों की हैसियत में काफी बदलाव आया। सत्ता में न आ पाने के बावजूद विधानसभा चुनाव में राजद को सबसे ज्यादा 75 सीटें आई थी। लोक सभा चुनाव में राजग को 40 में से 30 सीटें मिली। उस चुनाव में भी महागठबंधन के दोनों बड़े दलों में तानातानी खूब हो गई थी। राजीव रंजन उर्फ पप्पु यादव के लिए लालू यादव पूर्णिया का सीट छोड़ने को तैयार नहीं हुए। विपरित परिस्थियों में पप्पु यादव ने बतौर बागी उम्मीदवार लड़कर वह सीट जीत ली। वे पहले भी काफी समय से लालू यादव और उनके लोगों के खिलाफ बोलते थे, लोक सभा चुनाव के बाद वे खुलकर खिलाफ बोल रहे हैं।

दोनों दलों में विवाद का दूसरा नाम जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार का है। वे भाकपा की छात्र शाखा एआईएसएफ से भाकपा में आकर 2019 का लोक सभा चुनाव बिहार के बेगुसराय से लड़े। कहते हैं कि तब ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी उन्हें अपनी पार्टी से उसी सीट से लड़ाना चाहते थे। उस चुनाव में कन्हैया कुमार को सफलता नहीं मिली। 2024 के लोक सभा चुनाव में कांग्रेस में शामिल होने पर कांग्रेस उन्हें बिहार से चुनाव लड़वाना चाहती थी लेकिन लालू यादव के विरोध के चलते उन्हें दिल्ली उत्तर पूर्व सीट से चुनाव लड़वाया गया। उन्हें इस बार भी सफलता नहीं मिली। बावजूद इसके उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में सक्रियता से कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार किया। उसके तुरंत बाद उन्हें बिहार में सक्रिय किया गया। वे एनएसयूआई की पलायन रोको और नौकरी दो, पदयात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। चुनाव की तैयारी शुरू करते हा कांग्रेस ने दलित विधायक राजेश कुमार को प्रदेश की बागडोर सौंपी है। कहा जाता है कि लालू यादव अपने गठबंधन में ऐसा कोई नेता स्वीकारने को तैयार नहीं हैं, जो मुख्यमंत्री के लिए उनके पुत्र तेजस्वी यादव की दावेदारी को चुनौती दे।

वैसे तो देश भर के चुनाव में ही जातीय समीकरण प्रभावी रहता है लेकिन बिहार तो जातिवाद और जाति के हिसाब से राजनीति के लिए शुरू से ही बदनाम रहा है। संख्याबल के हिसाब से ऊंची कहे जाने वाली(सवर्ण) जातियों की संख्या कम है इसलिए हर दल को फोकस पिछड़ी जाति, दलित और अल्पसंख्यक हैं। माना जाता है कि भाजपा के खिलाफ ही अल्पसंख्यक(मुसलिम) वोट डलते हैं लेकिन भाजपा के साथ चुनाव लड़ने पर भी उसके सहयोगी दलों को अल्पसंख्यकों के एक वर्ग का वोट मिल जाता है।यह भी माना ही जा रहा है कि करीब 20 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार का यह आखिरी चुनाव है। वे खुद एक मजबूत पिछड़ी जाति से आते हैं। इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने पर उन पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। तमाम विरोध के बावजूद उनके शराबबंदी के फैसले का बड़ी तादात में गरीब महिलाओं का समर्थन आज भी उन्हें मिलता है। उनकी लगातार होती जीत का एक आधार महिलाएं हैं। लालू यादव के जंगल राज से उलट उनकी छवि सुशासन बाबू की बनी हुई है। कई उल्लेखनीय काम उनके खाते में है लेकिन वे बिहार को विकास की दौड़ में शामिल करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। न ही पलायन रूका और न ही बड़े पैमाने पर रोजराग के अवसर पैदा हुए। केन्द्र सरकार के सहयोग से हर गांव सड़क से जुड़ा। हर गांव में बिजली पहुंची। कई और केन्द्रीय योजनाओं का लाभ बिहार के लोगों को मिला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता का लाब इस गठबंधन और खास करके भाजपा को होगा ही। अगर सीटों पर विवाद नहीं हुआ तो इस गठबंधन की राय ज्यादा कठिन नहीं है। नीतीश कुमार सरकार के राजगीर, नालंदा में हुए काम मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। उम्र बढ़ने का उन पर हो रहे असर से उन्हें और उनकी सरकार का नुकसान हो रहा है। उनके हाल के कुछ बयान विवादास्पद रहे हैं। यह भी सत्य है कि शराबबंदी से राज्य के राजस्व का काफी नुकसान हुआ है और बड़ी मात्रा में बिहार में शराब की तस्करी हो रही है।

अभी हाल ही में एक जाति विशेष के गुंडों ने अलग-अलग स्थानों पर दो एएसआई की हत्या कर दी। कई और बड़े अपराध हुए। बावजूद इसके जिस बिहार ने लालू यादव

“ पिछली बार की तरह इस बार भी मुख्य मुकाबला भाजपा, जद (एकी), चिराग पासवान की पार्टी लोजपा और जीतन राम मांझी की पार्टी हम आदि राजग के दलों और लालू यादव के पुत्र तेजस्वी की राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और महागठबंधन के दलो के बीच ही होना है। सीटों और तालमेल का जितना विवाद राजग में होने की आशंका है उससे कई गुणा विवाद महागठबंधन में होता दिख रहा है।

और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का जंगल राज भोगा है, वे कानून व्यवस्था के नाम पर लालू यादव की पार्टी का साथ नहीं दे सकते। बिहार चुनाव में जातिवाद प्रभावी होता है इसलिए यादव बिरादरी का भरपूर समर्थन राजद को मिलेगा ही। उसी तरह कुर्मी वोटों पर बड़ी दावेदारी जनतादल(एकी) का माना जाता है। बाकी पिछड़ी जातियों को अपने पक्ष में लाने की होड़ सभी दलों में लगी है। भाजपा ने पहले एक मजबूत परिछड़ी जाति के नेता सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री बनाया, अब दूसरी पिछड़ी जाति के दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। वैसे पढ़े लिखे कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद उन जैसा दूसरे कद्दावर नेता की भाजपा को तलाश है। राजग के एक घटक के नेता उपेन्द्र कुशवाहा भी अपनी बिरादरी में बड़ी दखल रखते हैं। दलित वोटों के दावेदार दोनों ही गठबंधनों में हैं। भाजपा और जद(एकी) को दलितों के एक वर्ग का समर्थन मिलता ही रहा है केन्द्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी इस गठबंधन में दलित वर्ग को जोड़ेते ही हैं। दलित वोटों में राजद और कांग्रेस की भी दावेदारी रहेगी। असली भिड़त तो अल्पसंख्यक वोटों पर होगा। अब तो बिहार की राजनीति में सवर्ण जातियों की दखलंदाजी लगातार घट रही है। बावजूद इसके लालू-राबड़ी राज में उन जातियों के दमन ने उन्हें राजद का स्थाई विरोधी बना दिया है। वैसे यह भी कम चौंकाने वाली जानकारी नहीं है उसी पार्टी के नेता रहे रघुबंश प्रसाद सिंह(अब स्वर्गीय) और जगदानंद सिंह को एक सवर्ण जाति का भरपूर समर्थन मिलता रहा है।

बिहार चुनाव अभी करीब छह महीने दूर है लेकिन वहां सत्ता के दावेदार अनेक बड़े दलों की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। इस बार के केन्द्रीय बजट में भी केन्द्र की भाजपा की अगुवाई वाली सरकार का फोकस बिहार पर दिखा। देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल बिहार अब भी किसी बड़े चमत्कार के भरोसे है, जो उसे पिछड़े से विकास की दौड़ में शामिल करा दे। पलायन का प्रयाय बना बिहार में भरपूर रोजगार के अवसर दिलाकर पलायन पर रोक लगवा दे। बिहार में गुरूग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तरह समृध औद्योगिक नगरी बना दे। लंबे समय से इसी मुद्दे पर अलख जगाने वाले जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर के अभियान की भी इस चुनाव में परीक्षा होनी है। हाल ही के विधानसभा उप चुनाव में उनकी पार्टी को ढंग का समर्थन नहीं मिला। दावे चाहे जो किए जाएं लेकिन बिहार की सबसे बड़ी समस्या जातिवाद है,इस चुनाव में भी जातिवाद ही सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। अगर जातिवाद के बजाए विकास, रोजगार, शिक्षा आदि मुद्दे चुनाव तक मुख्य मुद्दे बन जाएं तो बिहार का कल्याण ही हो जाए और सालों से उस पर लगा गरीबी, पिछड़ेपन का ठप्पा हट जाए।

विधानसभा चुनाव : सत्ता की लड़ाई

संगीता शुक्ला

बिहार विधानसभा चुनाव, जो लगभग सात महीने बाद होने वाला है, संभावित परिणामों को लेकर जबरदस्त अटकलों को जन्म दे रहा है। वर्तमान में, जनता दल (यूनाइटेड) के नेता नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के समर्थन से एक अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। जैसे-जैसे राजनीतिक हलचल तेज हो रही है, नेतृत्व का सवाल चर्चाओं के केंद्र में बना हुआ है, और भाजपा अपने स्वयं के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को पेश करने के बारे में पुनर्विचार कर सकती है।

पिछले कुछ वर्षों में, बिहार की राजनीतिक स्थिति बदलते गठबंधनों और सत्ता संघर्षों से प्रभावित रही है। भाजपा और जद (यू) ने पिछले लोकसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया था, 40 में से 39 सीटें जीतकर। हालांकि, राज्य विधानसभा चुनाव अक्सर अलग होते हैं, जो क्षेत्रीय चिंताओं, जातीय समीकरणों और सत्तारूढ़ सरकार के प्रदर्शन से प्रभावित होते हैं। बिहार के पिछड़ेपन को लेकर आलोचनाओं के बावजूद, नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक कुशलता का प्रदर्शन किया है और 2005 से, 2017 की संक्षिप्त अवधि को छोड़कर, मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं।

नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा और शासन

नीतीश कुमार का शासन बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण नीतियों का मिश्रण रहा है। उनके कार्यकाल में सड़क कनेक्टिविटी, ग्रामीण विद्युतीकरण और स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए साइकिल योजना जैसी योजनाओं में सुधार हुआ है। हालांकि, बिहार अब भी बुनियादी चुनौतियों से जूझ रहा है, जिसमें कमजोर औद्योगीकरण, अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं और संघर्षरत शिक्षा प्रणाली शामिल हैं। 'बीमारू राज्य' शब्द, जो बिहार की पिछड़ेपन को दर्शाता है, आर्थिक और सामाजिक सुधार के प्रयासों के बावजूद विवाद का विषय बना हुआ है।

नीतीश कुमार का शासन बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण नीतियों का मिश्रण रहा है। उनके कार्यकाल में सड़क कनेक्टिविटी, ग्रामीण विद्युतीकरण और स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए साइकिल योजना जैसी योजनाओं में सुधार हुआ है। हालांकि, बिहार अब भी बुनियादी चुनौतियों से जूझ रहा है, जिसमें कमजोर औद्योगीकरण, अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं और संघर्षरत शिक्षा प्रणाली शामिल हैं। 'बीमारू राज्य' शब्द, जो बिहार की पिछड़ेपन को दर्शाता है, आर्थिक और सामाजिक सुधार के प्रयासों के बावजूद विवाद का विषय बना हुआ है।

नीतीश कुमार की बिहार की राजनीतिक अस्थिरता में बने रहने की

क्षमता उनके रणनीतिक गठबंधनों से जुड़ी है। भाजपा के साथ उनका संबंध कई बार बना और टूटा। 2013 में, उन्होंने नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के विरोध में भाजपा से नाता तोड़ लिया, लेकिन 2017 में राजद और कांग्रेस के महागठबंधन से अलग होकर फिर भाजपा के साथ आ गए।

भाजपा की दुविधा: मुख्यमंत्री उम्मीदवार पेश करना या गठबंधन जारी रखना?

भाजपा नीतीश कुमार के साथ अपने गठबंधन को लेकर दोराहे पर खड़ी है। जहां गठबंधन बनाए रखना स्थिरता और एक आजमाई हुई चुनावी रणनीति प्रदान करता है, वहीं पार्टी बिहार में अपनी अलग पहचान स्थापित करने और एक मुख्यमंत्री उम्मीदवार प्रस्तुत करने पर भी विचार कर सकती है। भाजपा का बढ़ता मतदाता आधार और विचारधारात्मक अपील उसे जद (यू) के प्रभाव से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। हालांकि, यह कदम जोखिमभरा भी हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार की कुर्मी और कोइरी समुदायों में मजबूत पकड़ और उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि एक महत्वपूर्ण चुनावी कारक बनी हुई है।

दूसरी ओर, तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन (एमजीबी) सत्ता विरोधी लहर को भुनाने की कोशिश कर रहा है। हाल के जनमत सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि महागठबंधन को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) पर हल्की बढ़त मिल सकती है। तेजस्वी यादव बेरोजगारी, शिक्षा और कल्याणकारी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर एक मजबूत विपक्षी नेता के रूप में उभरे हैं। उनकी चुनावी रणनीति यादव-मुस्लिम-दलित वोट बैंक को मजबूत करने पर टिकी हुई है, जो पारंपरिक रूप से राजद का गढ़ रहा है।

प्रमुख चुनौतियां और मतदाता चिंताएं

बिहार के मतदाता जातीय समीकरण, विकास के मुद्दे और रोजगार के अवसरों से प्रभावित होते हैं। आगामी चुनाव को आकार देने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक इस प्रकार हैं:

> **तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन (एमजीबी) सत्ता विरोधी लहर को भुनाने की कोशिश कर रहा है। हाल के जनमत सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि महागठबंधन को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) पर हल्की बढ़त मिल सकती है। तेजस्वी यादव बेरोजगारी, शिक्षा और कल्याणकारी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर एक मजबूत विपक्षी नेता के रूप में उभरे हैं। उनकी चुनावी रणनीति यादव-मुस्लिम-दलित वोट बैंक को मजबूत करने पर टिकी हुई है, जो पारंपरिक रूप से राजद का गढ़ रहा है।**

1. रोजगार और प्रवास: बिहार की उच्च बेरोजगारी दर और अन्य राज्यों में काम करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रवास एक गंभीर चिंता का विषय है। कोविड-19 महामारी ने प्रवासी श्रमिकों की कमजोरियों को उजागर किया और स्थानीय रोजगार के अवसरों की आवश्यकता को रेखांकित किया।

2. कृषि संकट: कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण बिहार के किसान अनियमित मानसून, सिंचाई सुविधाओं की कमी और सरकारी सहायता के अभाव जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं।

3. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं: सुधार के बावजूद, बिहार अब भी साक्षरता दर और स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में पिछड़ा हुआ है। गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संस्थानों की कमी और कुशल रोजगार के अवसरों के अभाव में छात्र अन्य राज्यों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर हैं।

4. जातीय और पह चान आधारि राजनीति: बिहार में राजनीतिक समर्थन अक्सर जातिगत समीकरणों द्वारा निर्धारित होता है। भाजपा ने गैर-यादव ओबीसी समुदायों में अपनी पैठ बनाई है, जबकि राजद अपने पारंपरिक मुस्लिम-यादव वोट बैंक पर निर्भर है।

आगे की राह: कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री?

जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएगा, सभी दल अपनी प्रचार रणनीतियों को तेज करेंगे। भाजपा विकास के एजेंडे और राष्ट्रवादी अपील पर ध्यान केंद्रित करेगी, जबकि जद (यू) स्थिरता और शासन पर जोर देगा। वहीं, महागठबंधन मौजूदा सरकार के प्रति असंतोष को भुनाने की कोशिश करेगा।

अंततः, बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम कई कारकों पर निर्भर करेगा– नेतृत्व विकल्प, गठबंधन समीकरण, मतदाता भावनाएं और अंतिम समय के राजनीतिक समीकरण। चाहे नीतीश कुमार अपनी सत्ता बनाए रखें, भाजपा अपनी स्थिति मजबूत करे, या महागठबंधन वापसी करे, बिहार का राजनीतिक परिदृश्य एक रोमांचक मुकाबले के लिए तैयार है।

बिहार विधानसभा चुनाव: 243 सीटों पर इस बार 2010 वाला खेला होगा?

➲ कुमार जितेंद्र ज्योति

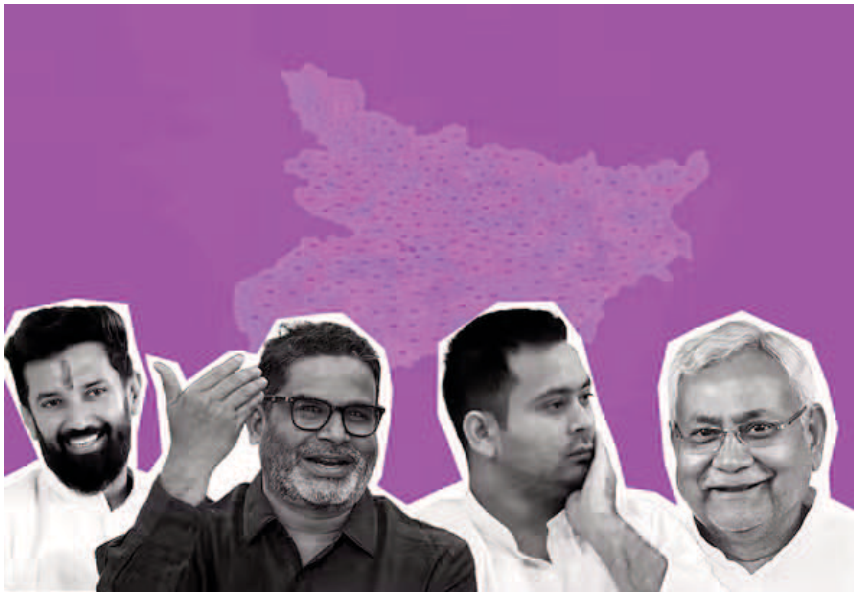

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी, यह बार-बार कहा जा रहा है। विपक्षी दल जो कहें, सत्तारूढ़ दलों के अंदर इस बात की बाहरी तौर पर तो सहमति साफ-साफ है। अब संकट सामने के खेमों में दिख रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जो दावे और तैयारी बता कर पटना से लौटे हैं, उससे तो लग रहा है कि कहीं कांग्रेस 2010 वाला खेला करने न उतर आए! ऐसा हुआ तो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को कदम फूंक-फूंक कर उठाना होगा। वैसे, अबतक के दावों और तैयारियों को देखें तो वर्ष 2000 और 2010 के बाद इस सदी में तीसरी बार बिहार की सभी सीटों पर कोई एक या कई दल चुनाव लड़ेंगे।

»» सभी सीटों पर लड़ने का कांग्रेस का रहा है रिकॉर्ड

आजादी के बाद, पिछली शताब्दी में तो कांग्रेस बिहार विधानसभा की अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी रही ही थी, इस सदी में भी दो बार इसने यह किया है। वर्ष 2000 और 2010 के बिहार चुनाव में कांग्रेस ने बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था। वर्ष 2000 में झारखंड बंटवारा नहीं हुआ था तो बिहार में 324 सीटें थीं। उस समय कांग्रेस ने सभी पर प्रत्याशी उतारे, हालांकि उसे महज 23 सीटों पर जीत मिली और 231 पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। इस समय जनता दल से निकलकर बनी लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ी धमक दिखाई थी। राजद ने 293 सीटों पर प्रत्याशी दिए थे, जिनमें से 124 ने जीत दर्ज की थी। झारखंड बंटवारे के बाद अबतक एक ही बार 2010 में बिहार की सभी सीटों पर किसी दल ने प्रत्याशी उतारे और वह भी कांग्रेस ही थी। कांग्रेस ने 2010 के बिहार चुनाव में सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। इस चुनाव में कांग्रेस की हिम्मत को जनता ने हिमाकत करार दिया। कांग्रेस के महज चार विधायक बने और 216 की जमानत जब्त हो गई थी।

बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस सीटों को लेकर बात नहीं कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में वह बात ही करती रह गई थी और राजद की ओर से अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बगैर समन्वय किए ही अपनी ओर से प्रत्याशी दिए जा रहे थे। बाद में सीटों पर कांग्रेस को 'समझौता' करना पड़ा। इस बार कांग्रेस ने बिहार चुनाव की तैयारी शायद महागठबंधन के दलों में सबसे पहले शुरू की है। कांग्रेस ने बिहार प्रदेश का प्रभारी बदला। फिर बिहार प्रदेश का अध्यक्ष भी दलित विधयक राजेश राम को बना दिया। राहुल गांधी लगातार बिहार दौरे पर आ रहे। इस बार तो उन्होंने राजद का नाम लिए बगैर उसके कोर वोटरों- पिछड़ा, अतिपिछड़ा और गरीब-गुरबा को अपने साथ जोड़ने की पूरी योजना बता दी। योजना बताने से पहले बिहार कांग्रेस में भारी संख्या में पिछड़ी जातियों के जिलाध्यक्षों को कमान भी सौंपी गई।

»» कांग्रेस का फैसला बाकी, इन दो दलों ने कर दिया एलान

बिहार की सभी 243 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी उतारेगी या दबाव बनाकर राजद से सीटें हासिल करेगी, यह फैसला सामने आना बाकी है। जो परिस्थितयां बन रही हैं, उनमें तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को कांग्रेस से बात करने के लिए उतरना ही पड़ेगा। ऐसा होता है या नहीं, यह वक्त बताएगा। फिलहाल दो दलों ने बता दिया है कि वह बिहार चुनाव में सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगा। जन सुराज पार्टी के संरक्षक प्रशांत किशोर ने पिछले साल उप चुनाव के समय ही बता दिया था कि वह बिहार की सभी सीटों पर प्रत्याशी देंगे। वह इस बात को कई बार दुहरा चुके हैं। पार्टी कल इसी के हिसाब से पटना में फिर एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। इन तैयारियों के बीच चौंकाते हुए भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा देने वाले बिहार में 'सिंघम' के नाम से मशहूर शिवदीप वामनराव लांडे ने 'हिंद सेना' पार्टी का गठन करते हुए सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने का एलान कर दिया है।

संघ के कर्नाटक-मंथन में नये संकल्प-नयी दिशाएं

ललित गर्ग

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की तीन दिवसीय बैठक अपने स्थापना के शताब्दी वर्ष प्रवेश के पावन एवं ऐतिहासिक अवसर पर बेंगलुरु में सफलतापूर्णक एवं ऊर्जामय माहौल में संपन्न हुई, जिसमें औरंगजेब विवाद, तीन-भाषा फॉमूर्ला, परिसीमन और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चर्चा ने एक अपूर्व वातावरण का निर्माण किया। जिसमें दुनिया में शांति और समृद्धि लाने के तर्क पर एक सौहार्दपूर्ण और संगठित हिंदू समाज के निर्माण का आ'ान किया गया। इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत, महासचिव दत्तात्रेय होसबोले, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा महासचिव बीएल संतोष सहित आरएसएस से जुड़े 32 संगठनों के प्रमुखों ने भाग लिया। आरएसएस की स्थापना विशेष रूप से भारतीय हिन्दू समाज में राष्ट्रीयत्व भाव जागृत करने, हिन्दुओं को संगठित करने एवं हिन्दू समाज के बीच समरसता स्थापित करने के उद्देश्य से हुई और इन सौ वर्षों में न केवल इन लक्ष्यों को हासिल किया गया है बल्कि अनेक रचनात्मक एवं सृजनात्मक गतिविधियों एवं योजनाओं के साथ अपनी एक स्वतंत्र एवं अलग छवि का निर्माण किया है। इस वर्ष की वार्षिक बैठक न केवल विशेष बल्कि नवीन संकल्पों की वाहक बनी है, क्योंकि बैठक ने सकारात्मक क्रांतिकारी विचारों से न केवल राष्ट्र में सक्रिय नकारात्मक एवं अराष्ट्रीय ताकतों को सख्त संदेश दिया गया बल्कि पडौसी बांग्लादेश-पाकिस्तान-चीन आदि देशों की कुचेष्टाओं के लिये ललकारा भी गया एवं सावधान भी किया गया है। अठहत्तर वर्ष की देहरी पर खड़े होकर राष्ट्र के अतीत को देखा-परखा जाए तो ऐसा लगता है कि अब राष्ट्र का कायाकल्प हो रहा है। मूलभूत आस्थाओं एवं राष्ट्रीयता के दृढ़ीकरण के साथ देश में जो नई चेतना आई है, वह संघ जैसे शक्तिशाली संगठन का जीवंत साक्ष्य है। राष्ट्रीयता, स्व-पहचान, स्वदेशी-भावना, हिन्दू-संस्कृति के ऊर्जा के अक्षय स्रोतों की खोज में जो प्रयत्न किया जा रहा है, वह अभूतपूर्व है। जन-आकांक्षा के अनुरूप राष्ट्र को जिस युगीन परिवेश में प्रस्तुति दी जा रही है, वह असाधारण है। इन सब परिवर्तनों-परिवर्धनों एवं राष्ट्र को सशक्त करने के बावजूद संघ की सादगी का सौन्दर्य निराला है और कर्नाटक बैठक इसी सादगी के सौन्दर्य के अनूठेपन को लिये हुई थी।

> **कर्नाटक बैठक से एक बार फिर पुरजोर तरीके से उजागर हुआ कि संघ हिन्दू सनातन संस्कृति को भारत के जन-जन के मानस में प्रवाहित करने का सफल एवं सार्थक कार्य करने को प्रतिबद्ध है। ताकि प्रत्येक भारतीय के मन में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो एवं उनके लिये भारत प्रथम प्राथमिकता बन सके। यह कार्य संघ अपने स्वयंसेवकों द्वारा समाज के बीच जाकर करने का प्रयास करता है और यह कार्य आज पूरे विश्व में शांति एवं समरसतापूर्ण जीवन स्थापित करने के लिये एक जरूरी आवश्यकता है।**

दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन ने अपनी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में सभी स्वयंसेवकों से आग्रह किया कि वे पूरे समाज को सज्जन शक्ति के नेतृत्व में एकजुट कर, दुनिया के सामने एक संगठित और सामंजस्यपूर्ण भारत का आदर्श प्रस्तुत करें। इसमें बैठक में मुख्य रूप से कहा गया है कि भारत एक प्राचीन और समृद्ध संस्कृति वाला देश है और इसमें एकजुट दुनिया बनाने का अद्भुत ज्ञान एवं सक्षमता है। आरएसएस ने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य पूरी मानवता को विभाजन और विनाश की प्रवृत्तियों से बचाना है और सभी जीवों के बीच शांति और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, आरएसएस ने हिंदू समाज को अपने वैश्विक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए संगठित और सामूहिक जीवन की आवश्यकता पर बल दिया है, जो 'धर्म' पर आधारित आत्मविश्वास से भरा हो। साथ ही बैठक में पारित प्रस्तावों में यह भी कहा गया कि सभी प्रकार के भेदभावों को खारिज कर, एकजुट आचरण और पर्यावरण के अनुकूल जीवन

शैली को अपनाते हुए हमें एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहिए। यह समाज भौतिक समृद्धि के साथ-साथ आध्यात्मिकता से भी परिपूर्ण होगा, जो समाज की समस्याओं का समाधान करेगा और चुनौतियों को कम करेगा। इस वर्ष की बैठक का हर बोल अनमोल है, हर चरण एक मंजिल है, हर संकल्प नये भारत-सशक्त भारत की दिशा है और हर क्रिया एक सन्देश है। संघ का जीवन और दर्शन, विचार और सोच अन्तरमन को कुरेदने वाली ऐसी प्रेरणा है जो जागृत अवस्था में सोने वाले लोगों का झकझोर देती है।

इस बैठक की खास बात यह रही है कि इसमें संघ की तरफ से भाजपा के बारे में सीधे सवालों से दूरी बनाए रखी गयी। हालांकि, परिसीमन के मुद्दे पर दक्षिण के राज्यों में सीटें कम नहीं होने को लेकर भाजपा को संदेश भी दे दिया। परिसीमन को लेकर संघ ने साफ कहा कि दक्षिणी राज्यों का लोकसभा में अनुपात वही रहेगा। इसके साथ ही संघ ने तीन-भाषा फामूर्ले पर संतुलित रुख बनाए रखा गया। ऐसे समय में जब भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार त्रिभाषा फामूर्ले को लेकर असमंजस में हैं, आरएसएस ने इस विवाद को दरकिनार करते हुए मातृभाषा, व्यक्ति के निवास स्थान की क्षेत्रीय भाषा तथा करियर की भाषा, जो अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा हो सकती है, के उपयोग की वकालत की है। संघ ने महाराष्ट्र में मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर चल रहे विवाद को लेकर मुगल शासक की तीव्र एवं तीखी आलोचना की। खास बात यह देखने को मिली कि संघ की तरफ से औरंगजेब की आलोचना के साथ ही उसके भाई दारा शिकोह का जश्न भी मनाया, क्योंकि दारा शिकोह सामाजिक सद्भाव में विश्वास करने वाला व्यक्ति था। दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि भारत के मूल्यों के खिलाफ जाने वाले लोगों को आदर्श बनाया गया था। औरंगजेब 'भारत के लोकाचार' के खिलाफ था और अगर वैसी ही 'आक्रमणकारी मानसिकता' अभी भी मौजूद है तो यह देश के लिए खतरा है। जो इस भूमि की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने की कुचेष्टा भी है। निश्चित ही इस तरह कोई विकृत संस्करण या नैरेटिव प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसका मुकाबला किया ही जाना चाहिए।

कर्नाटक बैठक की टंकार में संघ ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों

हिन्दू धर्म नहीं, संस्कृति है। हिन्दू राष्ट्र होने का अर्थ धर्म से न होकर हिन्दू संस्कृति के सर्वग्राही भाव से है। हिन्दू संस्कृति उदारता का अन्तर्निहित शंखनाद है क्योंकि पूरे विश्व में यह अकेली संस्कृति है जो बहुविचारवाद यानी सभी धर्म, विचार एवं संस्कृतियों को स्वयं में समेटे हैं। कर्नाटक बैठक हिन्दू संस्कृति के वृहद स्वरूप का ही सौपान बनी है।

पर गंभीर चिंता व्यक्त की। 'बांग्लादेश के हिन्दू समाज के साथ एकजुटता से खड़े होने का आ'ान' शीर्षक वाले एक प्रस्ताव में अंतरराष्ट्रीय ताकतों और 'अमेरिका में डीप स्टेट' के प्रयासों का उल्लेख किया गया।

संघ ने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं की जिम्मेदारी भारत की है और 'हम इस कर्तव्य से बच नहीं सकते।' निश्चित ही धार्मिक संस्थानों पर व्यवस्थित हमलों, क्रूर हत्याओं, जबरन धर्मांतरण और हिन्दुओं की संपत्तियों को नष्ट करने के चक्र ने बांग्लादेश में हिन्दू समुदाय के लिए अस्तित्व का संकट पैदा कर दिया है। इसलिये संघ द्वारा धार्मिक असहिष्णुता और मानवाधिकारों के उल्लंघन के इन कृत्यों की कड़ी निंदा की गई है और वैश्विक समुदाय से निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। इस बैठक ने हिन्दुओं को आश्वस्त किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के भविष्य में कोई मुश्किल स्थिति आती है, तो हम पीछे नहीं हट सकते। अगर ऐसी स्थिति आती है, तो हम उसका समाधान करेंगे। भाजपा के नये अध्यक्ष के चयन को लेकर भी संघ ने स्पष्ट किया कि भाजपा के नए अध्यक्ष के चयन को लेकर उसका पार्टी के साथ कोई मतभेद नहीं है। संघ ने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह से भाजपा पर निर्भर है। भाजपा की प्रक्रिया चल रही है, सदस्यता पूरी हो चुकी है और विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन हो चुका है। आने वाले दिनों में भाजपा अध्यक्ष का चुनाव होगा। इससे पहले चर्चा चल थी कि भाजपा और आरएसएस किसी उपयुक्त उम्मीदवार पर सहमत नहीं हो पाए हैं, जिससे दोनों संगठनों के बीच टकराव की अटकलें लगाई जा रही हैं।

कर्नाटक बैठक से एक बार फिर पुरजोर तरीके से उजागर हुआ कि संघ हिन्दू सनातन संस्कृति को भारत के जन-जन के मानस में प्रवाहित करने का सफल एवं सार्थक कार्य करने को प्रतिबद्ध है। ताकि प्रत्येक भारतीय के मन में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो एवं उनके लिये भारत प्रथम प्राथमिकता बन सके। यह कार्य संघ अपने स्वयंसेवकों द्वारा समाज के बीच जाकर करने का प्रयास करता है और यह कार्य आज पूरे विश्व में शांति एवं समरसतापूर्ण जीवन स्थापित करने के लिये एक जरूरी आवश्यकता है। पिछले आठ दशकों में लगातार हिन्दू-संस्कृति को कमजोर करने की राजनीतिक चालों को भी संघ ने समय-समय पर आड़े हाथ लिया है। दरअसल हिन्दू धर्म नहीं, विचार है, संस्कृति है। हिन्दू राष्ट्र होने का अर्थ धर्म से न होकर हिन्दू संस्कृति के सर्वग्राही भाव से है। हिन्दू संस्कृति उदारता का अन्तर्निहित शंखनाद है क्योंकि पूरे विश्व में यह अकेली संस्कृति है जो बहुविचारवाद यानी सभी धर्म, विचार एवं संस्कृतियों को स्वयं में समेटे हैं। कर्नाटक बैठक हिन्दू संस्कृति के वृहद स्वरूप का ही सौपान बनी है।

यहां प्लास्टिक, वहां प्लास्टिक, आखिर कहां नहीं है प्लास्टिक?

➲ सुनील कुमार महला

प्लास्टिक मनुष्य से लेकर धरती के समस्त जीवों, हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए एक प्रकार से ज़हर है। आज देश-दुनिया को भले ही प्लास्टिक ने कितनी ही सहूलियतें प्रदान क्यों न की हो, लेकिन यह मनुष्य, जीवों, वनस्पतियों के साथ-साथ संपूर्ण धरती के पर्यावरण के लिए विनाश ला रहा है। पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि हाल ही में भारत के केरल में हुए एक हालिया अध्ययन में बोतलबंद पानी में प्लास्टिक माइक्रोबीड्स की मौजूदगी का खुलासा हुआ है। यह पहली बार नहीं है जब बोतलबंद पानी में प्लास्टिक के महीन कण मिले हों। इससे पहले भी बोतलबंद पानी में प्लास्टिक की मौजूदगी के अनेक खुलासे हो चुके हैं। कुछ समय पहले नमक व चीनी तक के नमूनों में प्लास्टिक के महीन कणों की मौजूदगी के संबंध में एक अध्ययन सामने आया था। हाल ही में जो अध्ययन सामने आया है, उससे पता चलता है कि 10 प्रमुख ब्रांडों के बोतलबंद पानी में प्लास्टिक के माइक्रोबीड्स पाए गए हैं। इस स्टडी से सामने आया है कि औसतन प्रति लीटर तीन से दस माइक्रोबीड्स थे। फाइबर, टुकड़े, फिल्म और छर्रे सहित विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पाए गए, जो कि चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए क्यों कि आज भारत में बोतलबंद पानी का व्यापार लगातार बढ़ रहा है और बच्चों से लेकर बूढ़े, महिलाएं सभी बोतलबंद पानी का धड़ल्ले से उपयोग करते नजर आते हैं। आंकड़े बताते हैं कि बोतलबंद पानी के माध्यम से हर साल औसतन 153.3 प्लास्टिक कण उपभोक्ता के शरीर में प्रवेश करते हैं। पाठकों को बताता चलूं कि केरल में बिकने वाले बोतलबंद पानी पर केंद्रित यह अध्ययन अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिका स्प्रिंगर नेचर के डिस्कवर एनवायरनमेंट में प्रकाशित हुआ था। अध्ययन ने नमूनों में आठ अलग-अलग प्रकार के पॉलीमर कणों की उपस्थिति की पुष्टि की है, जिसमें फाइबर सबसे आम थे, जो 58.928% थे। कुल कणों का लगभग 35.714% लाल रंग का था। विश्लेषण से पता चलता है कि नमूनों में पाए गए रेशे अनुपचारित जल स्रोतों से उत्पन्न हो सकते हैं, जबकि अन्य जल शोधन में उपयोग किए जाने वाले घटकों या पैकेजिंग के लिए उपयोग की जाने वाली बोतलों से मिश्रित हो सकते हैं। बहरहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि केरल में बोतलबंद पानी पर हुआ ताजा अध्ययन हो या चीन, अमेरिका और जर्मनी के शोधकर्ताओं की रिपोर्ट, सब यही बताते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक मनुष्य के जीवन और पर्यावरण, दोनों के लिए बड़ा खतरा बन गया है। कहना ग़लत नहीं होगा कि यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और अगर गंभीरता नहीं बरती गई, तो प्लास्टिक मानवजाति ही नहीं अपितु संपूर्ण जीवों व धरती के लिए एक बहुत बड़ा व गंभीर खतरा बन जाएगा। आज प्लास्टिक का जिम्मेदार उपयोग नहीं किया जा रहा है और न ही इसकी उचित रिसाइक्लिंग (पुनर्चक्रण) पर ही किसी का ध्यान है। आज हमारे घरों, आफिसेज से लेकर हर जगह प्लास्टिक का बोलबाला है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है, जहां प्लास्टिक का किसी न किसी रूप में आविर्भाव नहीं हो। प्लास्टिक हमारी जिंदगी का बहुत ही अहम्, महत्वपूर्ण व जरूरी हिस्सा बन चुका है। हमारे शेविंग रेजर से लेकर हमारे टुथब्रश, नहाने की बाल्टी, मग, हमारे चश्मे, हमारे पेन(कलम), हमारे भोजन की थाली, प्लेट, कटोरी तक सब प्लास्टिक का ही है। संक्षेप में कहें तो हम माइक्रोप्लास्टिक्स का सामना हर जगह करते हैं। मसलन, कचरा, धूल, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन, सफाई उत्पाद, बारिश, समुद्री भोजन, उपज, नमक, आदि में। आज मिट्टी, पानी, भोजन, हवा और मानव शरीर सहित सभी जीवित जीवों में माइक्रो-प्लास्टिक कण पाए गए हैं। पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि माइक्रोप्लास्टिक, प्लास्टिक के टूटने से बनते हैं और ये हवा, पानी, और ज़मीन में भी पाए जाते हैं। वास्तव में ये हमारे शरीर में सांस लेने और खाने के ज़रिए पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, ये हमारे रक्त, फेफड़े, और प्लेसेंटा में भी पाए गए हैं। सच तो यह है कि ये हमारे शरीर के लगभग हर हिस्से में पाए जाते हैं, क्यों कि आज हम बेतहाशा रूप से हर चीज़ में प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं। आज हम चाय, कोफी तक प्लास्टिक के

डिस्पोजेबल कप्स में पीते हैं। बहरहाल, पाठकों को बताता चलूं कि अध्ययन बताते हैं कि औसतन, मनुष्य प्रतिदिन 240 कणों को साँस के ज़रिए अंदर लेता है। यूएनईपी के अनुसार, हर साल 23 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा दुनिया की जल प्रणालियों में लीक हो जाता है। हाल ही में जो शोध सामने आया है वह बोतलबंद पानी के उत्पादन में बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं की आवश्यकता पर गंभीरता से प्रकाश डालता है। कहना ग़लत नहीं होगा कि यह प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर देता है कि उपयोग के बाद इसे(प्लास्टिक को) वैज्ञानिक रूप से संसाधित किया जाए। बहरहाल, यहां यह उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले साइंस एडवांस में प्रकाशित एक अध्ययन ने भी बताया था कि प्लास्टिक के नैनो कण इन्सान के दिमाग में प्रवेश कर रहे हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि माइक्रो-प्लास्टिक के मानव स्वास्थ्य पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। मसलन, ये सूजन, जीनोटॉक्सिसिटी, ऑक्सीडेटिव तनाव, एपोप्टोसिस, और नेक्रोसिस जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये कैंसर, हृदय रोग, सूजन आंत्र रोग, मधुमेह, रुमेटी गठिया, और ऑटो-इम्यून स्थिति जैसी बीमारियों से जुड़े हो सकते हैं। यहां तक कि ये प्रजनन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। पाठकों को बताता चलूं कि माइक्रोप्लास्टिक कण पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को भी बाधित कर रहे हैं, जिससे गेहूं, धान और मक्का जैसी प्रमुख फसलों की पैदावार में सालाना 14 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है। प्रकाश संश्लेषण दरअसल, पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया है, जिसमें वे श्वसन के विपरीत, कार्बन डाई ऑक्साइड ग्रहण करते हैं, और वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लिहाजा यह प्रक्रिया हमारे ग्रह पर कार्बन डाई ऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित रखने के लिए भी जरूरी है। प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो करोड़ों सालों तक भी नष्ट नहीं होती है। कुछ लोग यह समझते हैं कि प्लास्टिक को जलाने से यह खत्म हो जाता है, लेकिन यह ग़लत है। प्लास्टिक को जलाना तो और भी अधिक खतरनाक है। गौरतलब है कि प्लास्टिक को जलाने से डाइऑक्सिन, फ़्यूरान, और पीसीबी जैसे हानिकारक रसायन निकलते हैं। बहरहाल, यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्लास्टिक के उत्पादन और विनाश से ऐसे कण और गैसें पैदा होती हैं, जो जलवायु परिवर्तन(क्लाइमेट चेंज) में योगदान करती हैं, और पर्यावरण में विघटित होने के लिए छोड़े गए प्लास्टिक से ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं। ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ोतरी से धरती के तापमान में बढ़ोत्तरी होती है और हमारी धरती की पारिस्थितिकी गड़बड़ा जाती है। अध्ययन बताते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक समुद्री सूक्ष्मजीवों की कार्बन डाइ-ऑक्साइड को अलग करने और ऑक्सीजन का उत्पादन करने की वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण भूमिकाओं को बाधित करते हैं। ये कमी हमारे और हमारे नीले ग्रह(धरती) के स्वास्थ्य को और ख़तरे में डालती है। आज हमारी धरती निरंतर प्लास्टिक की जद में आती चली जा रही है। प्लास्टिक के आंकड़े जानकर हर किसी को घोर आश्चर्य हो सकता है। मसलन, दुनिया भर में करीब 903 करोड़ टन प्लास्टिक है। यह 110 हाथियों के वज़न के बराबर है। दुनिया भर में हर साल करीब 450 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। गौरतलब है कि 1950 में दुनिया भर में महज 15 लाख टन प्लास्टिक का उत्पादन होता था, जबकि वर्ष 2022 तक यह आंकड़ा 400 करोड़ टन पर पहुंच गया है, जिससे स्थिति की गंभीरता समझी जा सकती है। क्या यह आश्चर्यजनक और गंभीर बात नहीं है कि हर साल करीब 1.3 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में गिराया जाता है। एक उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्लास्टिक 11 किलोमीटर गहराई तक पाया गया है। इतना ही नहीं, दुनिया भर में पैदा हुए सात अरब टन प्लास्टिक कचरे में से 10 प्रतिशत से भी कम को रिसाइकिल किया गया है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल प्लास्टिक प्रदूषण से 10 लाख से अधिक समुद्री पक्षी और 100, 000 समुद्री जानवर मर जाते हैं। जानकारी मिलती है कि 100% शिशु समुद्री कछुओं के पेट में प्लास्टिक होता है। उल्लेखनीय है कि हमारे महासागर में अब 5.25 ट्रिलियन प्लास्टिक के वृहद और सूक्ष्म टुकड़े हैं, तथा महासागर के प्रत्येक वर्ग मील में 46, 000 टुकड़े हैं, जिनका वजन 269, 000 टन तक है। क्या यह गंभीर बात नहीं है कि वर्तमान में हमारे महासागरों में अनुमानतः 75 से 199 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा है, तथा प्रतिवर्ष 33 बिलियन पाउंड प्लास्टिक समुद्री पर्यावरण में प्रवेश कर रहा है और हर दिन लगभग 8 मिलियन प्लास्टिक के टुकड़े हमारे महासागरों में पहुँचते हैं। विश्व में प्रतिवर्ष 381 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जो वर्ष 2034 तक दोगुना हो जाएगा। इसमें से 50% एकल-उपयोग प्लास्टिक है और केवल 9% का ही पुनर्चक्रण किया गया है। आंकड़े बताते हैं कि समुद्र की सतह का 88% हिस्सा प्लास्टिक कचरे से प्रदूषित है और हर साल 8 से 14 मिलियन टन तक कचरा हमारे महासागर में प्रवेश करता है। ब्रिटेन प्रतिवर्ष 1.7 मिलियन टन प्लास्टिक तथा अमेरिका हर साल 38 मिलियन टन प्लास्टिक का योगदान देता है। वास्तव में, प्लास्टिक पैकेजिंग इसका सबसे बड़ा दोषी है, जिसके कारण अकेले अमेरिका में प्रतिवर्ष 80 मिलियन टन कचरा उत्पन्न होता है। आज हर चीज की पैकेजिंग प्लास्टिक में की जाती है, हमें इससे बचना होगा और इसके बेहतर विकल्प तलाशने होंगे। आज हर मिनट 10 लाख से अधिक प्लास्टिक थैलियां कूड़े में फेंकी जाती हैं। इतना ही नहीं, विश्व में प्रति वर्ष 500 बिलियन से अधिक प्लास्टिक बैग का उपयोग किया जाता है-यानि पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए 150 बैग। प्लास्टिक के आंकड़े वास्तव में बहुत ही गंभीर हैं। 8.3 बिलियन प्लास्टिक स्ट्रॉ दुनिया के समुद्र तटों को प्रदूषित करते हैं, लेकिन केवल 1% स्ट्रॉ ही समुद्र में अपशिष्ट के रूप में पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, मानव उपभोग के लिए पकड़ी गई 3 में से 1 मछली में प्लास्टिक होता है। अंत में यही कहूंगा कि वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (यूएनईए) में प्लास्टिक संधि पर प्रस्ताव लाए जाने के बावजूद अब तक प्लास्टिक पर कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा सकें हैं। वास्तव में यह दर्शाता है कि हम सभी प्लास्टिक को लेकर बहुत ही लापरवाही बरत रहे हैं। आज भी हमारे देश में सिंगल यूजर प्लास्टिक का धड़ल्ले से उपयोग किया जाता है। यह पर्यावरण प्रदूषण, मानव स्वास्थ्य और वन्य जीवों को बेतहाशा नुकसान पहुंचा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग को जन्म दे रहा है। पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि भारत में 1 जुलाई, 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रतिबंध के तहत, एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री, और इस्तेमाल पर रोक है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बदस्तूर जारी है, वह वाकई चिंतित करने वाला है। आज जरूरत इस बात की है कि हम प्लास्टिक के उपयोग को लेकर सतर्कता बरतें, लोगों को जागरूक करें और हमारी प्रकृति, पर्यावरण को प्लास्टिक के ख़तरों से बचाएं। प्लास्टिक प्रदूषण आज एक वैश्विक समस्या है, हम सभी को इस समस्या से निपटने के लिए सामूहिकता से आगे आना होगा। तभी हम वास्तव में अपने नीले ग्रह को प्लास्टिक असुर से बचा पायेंगे।

(लेखक फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार है)

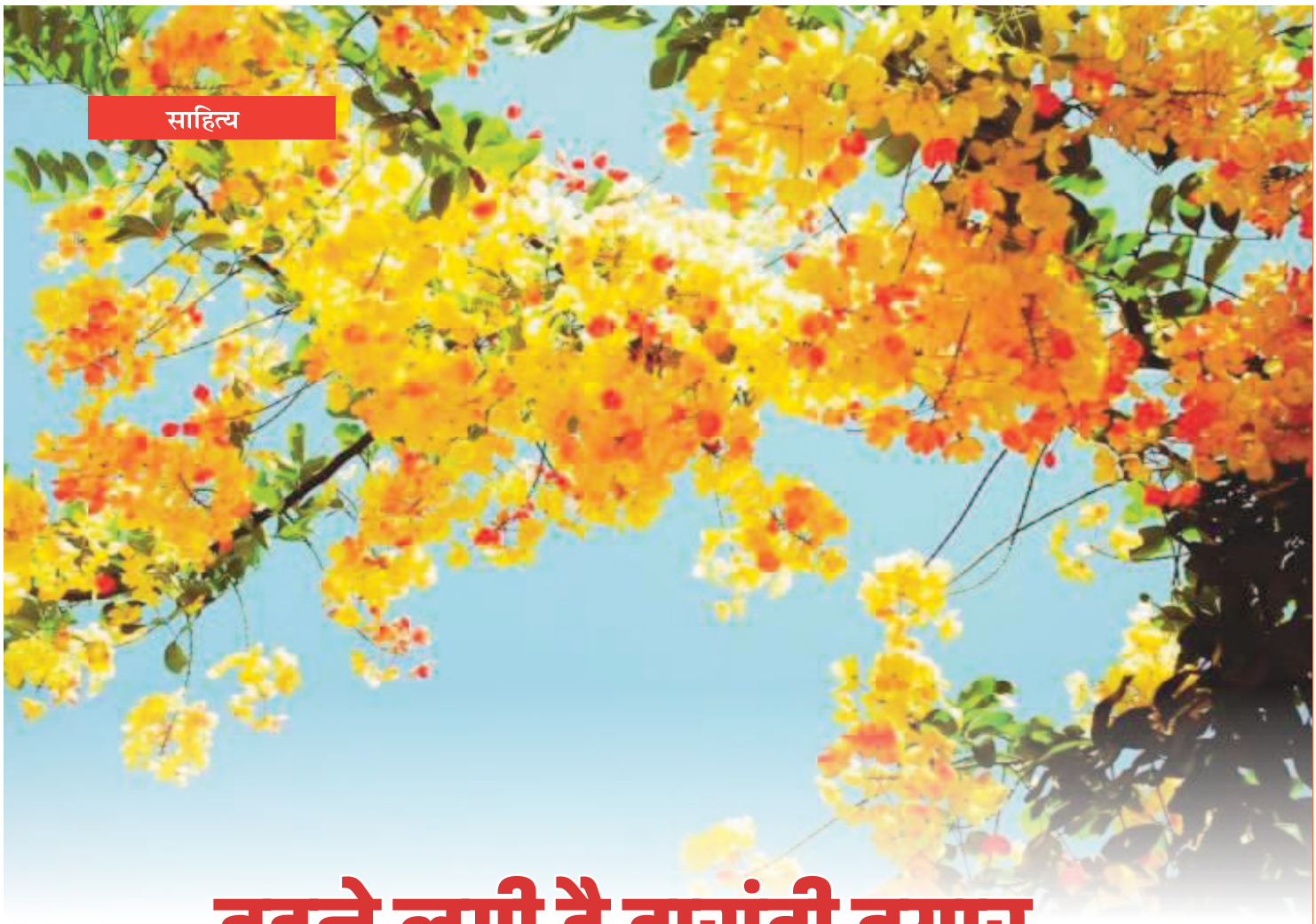

बहने लगी है वासंती बयार...

बहने लगी है वासंती बयार
मौसम बहुत हो चुका है खुशगवार
वासंती बयार जब मंद-मंद चलती है
फूलों की खुशबू सारे फिजां में महकती है
सच! वसंत में तुम्हारी याद आती है...

वसंत ऋतु प्रकृति का अनुपम उपहार
ऋतुराज वसंत में हमारे ख्वाब हुए थे साकार
हमने देखे थे सपने बसाने को इक सुंदर संसार
नई कोंपल, चारों तरफ हरियाली
कोयल गूँजती डाली-डाली
सच में ये ऋतु होती मतवाली
सच! वसंत में तुम्हारी याद आती है...

नए रंग लिए आता मधुमास
प्रेमी-प्रेमिका के प्रीत की बढ़ जाती प्यास
हमें ऋतुराज में तुमसे हुआ था प्यार
हमारे हृदय में प्रकृति जैसी हरियाली का आभास
वसंत ऋतु हमें आता था रास
हमारे सपने सच होते हुए काश!
सच! वसंत में तुम्हारी याद आती है...

आमों की डालों पर आ गए हैं बौर
सजधज कर प्रकृति में है नई उमंग
प्रकृति अलौकिक शोभा रही बिखेर
हम वसंत में रहते थे घंटों संग-संग
कितनी मस्ती कितना रहता था उत्साह
खुशियों भरा होता है वसंत माह
हमने देखे थे साथ जीने के ख्वाब
तुम साथ न हो तो कितना हूँ उदास
तुम्हारे पास होने का वसंत दे रहा एहसास
सच! वसंत में तुम्हारी याद आती है...

लाल देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

आखिर फिनलैंड की तरह हम खुश क्यों नहीं हुए?

सुनील कुमार महला

जीवन फूलों की सेज नहीं है। यहां यह पल कहीं न कहीं संघर्ष है, परेशानियां हैं,कष्ट हैं,लेकिन इन संघर्षों, परेशानियों और कष्टों में भी जो व्यक्ति हमेशा सकारात्मक सोच और ऊर्जा से जीवन को बहुत ही सहजता, धैर्य,संयम और खुशी (प्रसन्नता) से जीता है, वही तो वास्तव में असली जीवन है।

वास्तव में, जीवन के हर क्षण में आनंद और संतोष का अनुभव करना ही प्रसन्नता है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि 'प्रसन्नता तब होती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं, सब एक साथ हों।'

यह ठीक है कि व्यक्ति जब किसी उपलब्धि विशेष, सफलता को प्राप्त कर लेता है तो उसे खुशी या प्रसन्नता का अनुभव होता है, लेकिन यदि वास्तव में देखा जाए तो किसी उपलब्धि या स्थिति विशेष तक पहुंचना ही खुशी नहीं है।

दरअसल, खुशी या प्रसन्नता का भाव हमेशा अंतर्मन में निहित होता है, यह(खुशी) आंतरिक होती है, बा' नहीं। संपत्ति, पद और प्रतिष्ठा(नेम एंड फेम) या सफलता प्राप्त करना ही खुशी या प्रसन्नता नहीं है, यह इससे भी ऊपर थोड़ा हटकर है। खूब सारी संपत्ति हमें प्रसन्नता दे सकती है, इसी तरह से प्रतिष्ठा से भी हमें खुशी का अहसास हो सकता है, लेकिन यदि प्रसन्नता का भाव देखा जाए तो यह भौतिकता में तो कतई नहीं है।

वास्तव में, यह हमारे भावनात्मक और मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। असल में हमारे भीतर (अंतर्मन) की शांति और संतोष ही असली प्रसन्नता है।हाल ही में 'विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट' जारी की गई है।

पाठकों को बताता चलूं कि 20 मार्च 2025 गुरूवार को यह रिपोर्ट जारी की गई है, जो यह बताती है कि खुशी सूचकांक में भारत का स्कोर 10 में से 4.389 पर आ गया है, जो पहले 4.054 था। निश्चित रूप से स्कोर बढ़ा है, लेकिन खुशी इतनी नहीं। मामूली सी बढ़ोत्तरी हुई है इसमें।

यहां यह भी गौरतलब है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबींग रिसर्च सेंटर ने गैलप,

फिनलैंड में समुदाय में भावना बहुत ही प्रबल है। वास्तव में, फिनिश समाज समुदाय और सामूहिक कल्याण पर बहुत जोर देता है। घनिष्ठ पड़ोस से लेकर जीवंत सामाजिक मंडलियों तक, फिनिश लोग रिश्तों, एकजुटता और आपसी सहयोग को प्राथमिकता देते हैं, जिससे एक दूसरे से जुड़ाव और जुड़ाव की भावना पैदा होती है जो समग्र खुशी को बढ़ाती है। अंत में यही कहूंगा कि यदि हमें भी प्रसन्नता में नंबर वन बनना है तो हमें फिनलैंड से प्रेरणा लेते हुए बहुत से सुधार अपने यहां करने होंगे तभी हम प्रसन्नता सूचकांक में सिरमौर देश बन सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के साथ साझेदारी में वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट (डब्ल्यू एच आर) 2025 जारी की है। इस रिपोर्ट में जिन 147 देशों का विश्लेषण शामिल किया गया, उनमें भारत 118वें नंबर है। हालांकि, यह रैंकिंग अभी भी भारत को यूक्रेन, मोजाम्बिक और इराक सहित कई संघर्ष-प्रभावित देशों से पीछे रखती है। पूर्व में 143 देशों में यह 126वें स्थान पर था। मतलब यह है कि भारतीय लोग पिछले सालों की तुलना में अब थोड़ा सा अधिक प्रसन्न रहने लगे हैं। यानी विश्व में खुश रहने के मामले में भारत की रैंकिंग में कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन यहां यह गौरतलब है कि हमारे पड़ोसी नेपाल (92) और पाकिस्तान (109) प्रसन्नता के मामले में हमसे आगे हैं।

क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि जो पाकिस्तान लगातार आर्थिक चुनौतियों, महंगाई, आतंकवाद और अराजकता से जूझ रहा है, वह भी प्रसन्नता के मामले में हमारे देश से आगे है?

रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान का प्रदर्शन भारत से बेहतर रहा है। पाठकों को बताता चलूं कि हैप्पीनेस इंडेक्स पर उसका स्कोर 4.657 से बढ़कर इस बार 4.768 दर्ज किया गया है, लेकिन उसकी रैंकिंग 108 से गिरकर 109 पर आ गई है।

यहां पाठकों को बताता चलूं कि विभिन्न देशों की प्रसन्नता पर आधारित यह रैंकिंग लोगों के जीवन मूल्यांकन के तीन वर्षों के औसत से तैयार की जाती है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस 'खुश स्कोर' में भिन्नता की व्याख्या करने के लिए रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति जीडीपी, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, सामाजिक स्थिति, जीवन जीने की आजादी, उदारता और भ्रष्टाचार जैसे छह संकेतकों को मापा जाता है, लेकिन खुशहाली रैंकिंग इन छह कारकों में से किसी पर भी आधारित नहीं होती है।

बहरहाल, यहां पाठकों को यह जानकारी देना चाहूंगा कि प्रति व्यक्ति आय जैसे गणनात्मक पैमाने पर भारत की स्थिति पाकिस्तान से कहीं बेहतर दर्शाई गई है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में जहां वर्ष 2023 में प्रति व्यक्ति आय जहां 2,480.8 डॉलर रही, वहीं पाकिस्तान में यह 1,365.3 डॉलर के स्तर पर ही अटक गई।

यहां गौरतलब है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2021 में पाकिस्तान की स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा (जन्म के समय) जहां 56.9 साल थी, वहीं भारत की स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा 58.1 साल थी। इसके अतिरिक्त ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, 2024 रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान जहां 135वें नंबर रहा, वहीं भारत का स्थान इसमें 96वां था। बहरहाल, यदि हम यहां 'विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट' में टॉपर्स की लिस्ट की बात करें तो एकबार फिर फिनलैंड (लगातार आठवीं बार) नंबर 1 पर कायम है।

गौरतलब है कि फिनलैंड ने 7.74 का प्रभावशाली औसत स्कोर किया, जिससे वैश्विक स्तर पर सबसे खुशहाल राष्ट्र के रूप में अपनी पोजीशन बरकरार रखी है। जानकारों के अनुसार फिनलैंड में दिन में केवल चार घंटे सूरज निकलता है। यहां बहुत ठंड का मौसम रहता है, लेकिन कितनी बड़ी बात है इन सब विकट परिस्थितियों के बावजूद फिनलैंड के लोग दुनिया में सबसे प्रसन्न हैं।

सूची में फिनलैंड के बाद डेनमार्क, आइसलैंड, नीदरलैंड,कोस्टा रीका,नार्वे , इजरायल, लक्जमबर्ग, मेक्सिको और स्वीडन का स्थान है। वास्तव में,इन देशों ने अपनी स्ट्रांग सोशल सपोर्ट सिस्टम, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लीविंग और वर्क-लाइफ बैलेंस के प्रति प्रतिबद्धता के कारण लगातार खुशी रिपोर्ट में टॉप रैंक को प्राप्त किया है।दिलचस्प बात यह है कि कोस्टा रिका और मैक्सिको ने शीर्ष 10 में अपनी शुरूआत की, क्रमशः 6वां और 10वां स्थान हासिल किया।

वहीं पर दूसरी ओर, संयुक्त राज्य अमेरिका 24वें स्थान पर अपनी सबसे निचली रैंकिंग पर आ गया, वहीं पर यूनाइटेड किंगडम 23वें स्थान पर है। रिपोर्ट में चीन 68वें स्थान पर रखा गया है।

पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा दक्षिण एशियाई देशों में म्यांमार (126वाँ), श्रीलंका (133वाँ), बांग्लादेश (134वाँ) का स्थान पर रखे गए हैं। वहीं पर अफगानिस्तान (147वाँ) (लगातार चौथे वर्ष) स्थान पर है।

वास्तव में, अफगानिस्तान को दुनिया का

सबसे दुखी देश माना गया है। देश की निम्न रैंकिंग का मुख्य कारण अफगान महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले संघर्ष हैं, जिन्होंने बताया कि उनका जीवन लगातार कठिन होता जा रहा है।

अन्य देशों में क्रमशः सिएरा लियोन (146वाँ), लेबनान (145वाँ), मलावी (144वाँ) और ज़िम्बाब्वे (143वाँ) का प्रदर्शन सबसे निम्नतम रहा है। वास्तव में,अफगानिस्तान के बाद, सिएरा लियोन और लेबनान क्रमशः दूसरे और तीसरे सबसे दुखी देश हैं। इन देशों ने संघर्ष, गरीबी और सामाजिक अशांति सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना किया है। पाठकों को बताता चलूं कि यह रैंकिंग लोगों के जीवन मूल्यांकन के 3-वर्षीय औसत पर आधारित है, जिसमें प्रतिक्रियादाता अपने वर्तमान जीवन को 0 से 10 के पैमाने पर रेट करते हैं।

यहां यदि हम हैप्पीनेस के निर्धारक कारकों की बात करें तो इनमें क्रमशः विश्वास, सामाजिक संबंध, शेयर्ड मील और सामुदायिक दयालुता जैसे कारक शामिल हैं, जो सामान्यतः धन से भी अधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं।

गौरतलब है कि वर्ष 2025 में विश्व प्रसन्नता दिवस की थीमः 'केयरिंग एंड शेयरिंग' रखी गई थी तथा 'वर्ल्ड हैप्पीनेस डे' (विश्व प्रसन्नता दिवस) की पहल सर्वप्रथम भूटान द्वारा की गई थी, जिसने 1970 के दशक से ही ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस (जीएनएच) को जीडीपी से अधिक प्राथमिकता दी है। यहां पाठकों को यह भी बताता चलूं कि जुलाई 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 मार्च को 'वर्ल्ड हैप्पीनेस डे' के रूप में मनाने का निर्णय अंगीकृत किया गया था।

बहरहाल, यहां प्रश्न यह उठता है कि आखिर हमारा देश प्रसन्नता के मामले में इतना पीछे क्यों है? जबकि हमारे देश की स्थिति नेपाल और पाकिस्तान से तो हर मायने में बहुत ज्यादा बेहतर है। दरअसल, इसके पीछे कुछ कारण निहित हैं। कारण यह है कि आज हम अपनी परेशानियों को ज्यादा बड़ा बना कर देखते हैं। यह भी कि हमारे देश में 'जीवन की स्वतंत्रता' के पैमाने अन्य देशों की तुलना में कुछ अलग हैं, जिनको शायद इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया, इसलिए हम प्रसन्नता के मामले में पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों से भी पिछड़ गए। आज हम प्रकृति के भी उतने निकट नहीं रह गये हैं,जितने कि आज से पच्चीस तीस पहले थे।

बहरहाल, वास्तव में यह क्रूर मजाक नहीं तो और क्या है कि युद्धों में मटियामेट फिलिस्तीनी और यूक्रेनी लोग भी भारतीयों से कहीं ज्यादा खुशहाल व प्रसन्न हैं। बहरहाल, हमें यहां जरूरत इस बात की है कि प्रसन्नता के मामले में हम फिनलैंड से कुछ सीखें। कहना गलत नहीं होगा कि फिनलैंड दुनिया भर में खुशी के सूचकांक में हर बार शीर्ष पर

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबींग रिसर्च सेंटर ने गैलप, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के साथ साझेदारी में वर्ल्ड हैप्पीनेस डे पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट (डब्ल्यू एच आर) 2025 जारी की है। इस रिपोर्ट में जिन 147 देशों का विश्लेषण शामिल किया गया, उनमें भारत 118वें नंबर है। हालांकि, यह रैंकिंग अभी भी भारत को यूक्रेन, मोजाम्बिक और इराक सहित कई संघर्ष-प्रभावित देशों से पीछे रखती है। पूर्व में 143 देशों में यह 126वें स्थान पर था। मतलब यह है कि भारतीय लोग पिछले सालों की तुलना में अब थोड़ा सा अधिक प्रसन्न रहने लगे हैं।

रहता है। संभवतः, यह प्रवृत्ति इसलिए है, क्योंकि फिनलैंड के लोग सरल सुखों का आनंद लेते हैं-जैसे स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और जंगल में घूमना -पूरी तरह से, लेकिन हमारे यहां दूसरी चीजें हैं। मसलन, हम घंटों घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं, लोकल ट्रेनों में धक्के खा रहे होते हैं। हमारे यहां प्रदूषण का स्तर भी कुछ कम नहीं है। हमारे यहां मेट्रो सीटीज में बहुत प्रदूषण है। शहरों में अस्वच्छता भी है।हमारे यहां आज भी भ्रष्टाचार की जड़ें काफी गहरी हैं, लेकिन फिनलैंड में सब कुछ ठीक चलता है; मसलन, वहां पर सार्वजनिक सेवाएँ सुचारू रूप से चलती हैं, अपराध और भ्रष्टाचार का स्तर कम है, और सरकार और जनता के बीच एक अर्जित विश्वास है। यह सब मिलकर एक कार्यशील समाज और सभी का ख्याल रखने की संस्कृति बनाने के लिए काम करता है।

फिनलैंड में 40 से ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो हाइकिंग रूट, नेचर ट्रेल और कैम्पफायर साइट्स से भरे हुए हैं, जहाँ आप तारों के नीचे एक रात बिता सकते हैं। फिनलैंड के सभी जंगल अलग-अलग आकार और साइज में आते हैं; हरे-भरे दक्षिणी जंगलों से लेकर उत्तर के आर्कटिक अजूबों तक, बहुमुखी प्रतिभा और विविधता खिलती है। प्रकृति से लोगों का विशेष जुड़ाव है,जो उन्हें प्रसन्न और खुश रहने में मदद करता है।

हम भारतीयों को यह बात अपने जेहन में रखनी चाहिए कि प्रकृति के साथ निकटता रचनात्मकता और नवीनता को बढ़ावा देती है।

वास्तव में, कहना गलत नहीं होगा कि फि नलैंड की कम तनाव वाली जीवनशैली रचनात्मकता को बढ़ावा देती है, जिससे यह दुनिया के सबसे नवोन्मेषी देशों में से एक बन गया है। सच तो यह है कि फिनलैंड की खुशहाली का कारण, वहां के समाज में विश्वास और स्वतंत्रता का उच्च स्तर है। फिनलैंड के सबसे अधिक खुश व प्रसन्न होने के पीछे एक कारण यहां की आबादी भी है।

दरअसल,आबादी कम होने के कारण लोगों को मिलने वाली सुविधाएं काफी अच्छी होती हैं। यह भी कि फिनलैंड के निवासी अपने पड़ोसियों से अपनी तुलना नहीं करते हैं।

कहना गलत नहीं होगा कि सच्ची खुशी की ओर पहला कदम दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपने खुद के मानक निर्धारित करना है, जो कि फिनलैंड के लोगों ने करके दिखाया है। इतना ही नहीं,फिनलैंड के निवासी न तो प्रकृति के लाभों को नजरअंदाज करते हैं और न ही विश्वास का कम्यूनिटी सर्कल को तोड़ते हैं, इसलिए वे हमेशा खुश और प्रसन्न रहते हैं।

कहना गलत नहीं होगा फिनलैंड में काम-जीवन संतुलन पर बहुत जोर दिया जाता है, जिसमें काम के घंटे कम करना, माता-पिता को छुट्टी देने की उदार नीतियाँ और पर्याप्त छुट्टी का समय शामिल है। यह दृष्टिकोण फिन्स को अवकाश, परिवार और व्यक्तिगत गतिविधियों को प्राथमिकता देने की अनुमति देता है, जिससे समग्र कल्याण और संतुष्टि को बढ़ावा मिलता है।

इतना ही नहीं, फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली समानता, सुलभता और बालकों के समग्र विकास को प्राथमिकता देती है। फिनलैंड में लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण, एक समावेशी समाज में योगदान करते हैं। यहां की सौना संस्कृति भी उनकी(फिनलैंड वासियों) प्रसन्नता का एक बड़ा कारण है।

पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि सौना, फिनिश संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है, जो विश्राम, सामाजिक मेलजोल और कायाकल्प के लिए एक पोषित परंपरा के रूप में कार्य करता है। देश में तीन मिलियन से अधिक सौना के साथ, फिनिश लोग सौना स्नान को अपने स्वास्थ्य का एक मूलभूत पहलू मानते हैं, जो सामाजिक संबंधों और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देते हुए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। इतना ही नहीं, फिनलैंड में भ्रष्टाचार का स्तर दुनिया में सबसे कम है, जिससे सार्वजनिक संस्थाओं में विश्वास बढ़ता है और नागरिकों में निष्पक्षता और न्याय की भावना को बढ़ावा मिलता है। पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक शासन फिनलैंड की एक भरोसेमंद और विश्वसनीय समाज के रूप में प्रतिष्ठा में योगदान करते हैं। फिनलैंड में समुदाय में भावना बहुत ही प्रबल है।

वास्तव में, फिनिश समाज समुदाय और सामूहिक कल्याण पर बहुत जोर देता है। घनिष्ठ पड़ोस से लेकर जीवंत सामाजिक मंडलियों तक, फिनिश लोग रिश्तों, एकजुटता और आपसी सहयोग को प्राथमिकता देते हैं, जिससे एक दूसरे से जुड़ाव और जुड़ाव की भावना पैदा होती है जो समग्र खुशी को बढ़ाती है।

अंत में यही कहना चाहूंगा कि यदि हम भारतीयों को भी प्रसन्नता में नंबर वन बनना है तो हमें फिनलैंड से प्रेरणा लेते हुए बहुत से सुधार अपने यहां करने होंगे तभी हम प्रसन्नता सूचकांक में सिरमौर देश बन सकते हैं।

साफ-सफाई और बाल मृत्यु दर के बीच गहरा संबंध है। Gunther और Fink (2011) ने 30 देशों के 38 सर्वेक्षणों के डेटा का इस्तेमाल करके पाया कि घर में फ्लश टॉयलेट और पाइप्ड पानी की सुविधा होने से बच्चों की मृत्यु दर काफी कम हो जाती है। इससे बच्चों की शुरुआती मौत का खतरा लगभग 8 प्रतिशत कम हो सकता है। अच्छी सफाई व्यवस्था वाले घरों में रहने वाले बच्चों की मृत्यु का खतरा उन बच्चों की तुलना में 20 प्रतिशत कम होता है जो खराब सफाई व्यवस्था वाले घरों में रहते हैं।

अध्ययनों से पता चला है कि निजी शौचालय और पाइप्ड पानी जैसी बेहतर स्वच्छता सुविधाओं से बच्चों की मृत्यु दर में 8 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। स्वच्छता और सीवेज सिस्टम में सुधार से बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह कुपोषण को कम करता है और बच्चों की मृत्यु दर को कम करने में मदद करता है। कुपोषण का मतलब है शरीर को सही खाना न मिलना। इससे बच्चे कमजोर, बीमार और छोटे रह जाते हैं।

गंदगी का बच्चों की सेहत पर कैसा असर

बच्चों के कुपोषण के पीछे कई कारण होते हैं। पैसों की कमी और खाने की कमी तो अहम हैं ही, लेकिन अगर आस-पास गंदगी हो तो उसका भी बहुत बुरा असर होता है। अगर बच्चों के आस-पास गंदगी है तो बच्चों को पोषण की कमी (कुपोषण) हो सकती है। गंदगी की वजह से बीमारियां फैलती हैं, जिससे बच्चे कमजोर हो जाते हैं और खाना ठीक से नहीं पचा पाते। इससे उनका विकास रुक सकता है और कई बार मौत भी हो सकती है।

पीने के पानी में गंदगी होने से दस्त जैसी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन, पानी में गंदगी और कुपोषण का सीधा संबंध अभी तक साफ नहीं है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि पानी में गंदगी अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग होती है। दस्त से बच्चे कमजोर हो सकते हैं, लेकिन यह कुपोषण और मौत का सीधा कारण नहीं है। दस्त से पेट का सिस्टम पूरी तरह से नहीं बदलता है।

शिक्षा और बच्चों के पोषण का अनोखा संबंध

महिलाओं का पढ़ा लिखा होना बच्चों के पोषण स्तर को सीधे प्रभावित करता है। यह एक ऐसा अहम तथ्य है जिस पर शोधकर्ताओं ने गहराई से काम किया है। जब माताएं पढ़ी लिखी होती हैं, तो उनके बच्चों के पोषण स्तर में काफी सुधार होता है। खास तौर से जिन माताओं की शिक्षा 10 या उससे ज्यादा साल की होती है, उनके बच्चों में कुपोषण का खतरा 45 प्रतिशत तक कम हो जाता है।

शिक्षित महिलाएं अच्छे प्राइवेट टॉयलेट इस्तेमाल ज्यादा करती हैं। क्योंकि शिक्षित महिलाएं बच्चों की देखभाल और साफ-सफाई का ज्यादा ध्यान रखती हैं। वे बच्चों के मल का सही तरीके से निपटारा करती हैं जिससे बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जानकारी देना बहुत जरूरी है। टीवी, कैंप, स्कूल और कॉलेज के जरिए लोगों को स्वच्छता के बारे में बताया जा सकता है। अगर महिलाएं पढ़ी-लिखी होंगी, तो वे स्वास्थ्य कार्यक्रमों को ज्यादा ध्यान से सुनेंगी और समझेंगी। शिक्षित महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आसानी से समझ आती हैं और अपने बच्चों की सेहत का ज्यादा ध्यान रखती हैं।

पब्लिक टॉयलेट खुले में शौच को कम नहीं करते!

अगर 1 प्रतिशत ज्यादा लोग निजी शौचालयों का इस्तेमाल करने लगें, तो खुले में शौच 0.84 प्रतिशत कम हो जाता है। पब्लिक टॉयलेट का खुले में शौच पर कोई खास असर नहीं होता। अगर ज्यादा लोग पब्लिक टॉयलेट्स का इस्तेमाल करें, तो बच्चों में स्टंटिंग और अंडरवेट दोनों कम होते हैं। इसका असर दोनों ही मामलों में लगभग एक जैसा है।

पब्लिक टॉयलेट का खुले में शौच पर कोई खास असर नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बच्चों में स्टंटिंग और अंडरवेट कम करने में मदद करते हैं। इसका मतलब है कि पब्लिक टॉयलेट सीधे तौर पर बच्चों के स्वास्थ्य पर असर डालते हैं, न कि खुले में शौच को कम करके।

खुले में शौच कितना खतरनाक

नीति आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि खुले में शौच करने से बच्चों में कुपोषण होता है। जिन राज्यों में ज्यादा लोग खुले में शौच करते हैं, वहां 5 साल से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग (कद छोटा होना) और अंडरवेट (कम वजन) की समस्या ज्यादा है।

जब 5-10 प्रतिशत से कम लोग खुले में शौच करते हैं, तो स्टंटिंग और अंडरवेट पर इसका असर ज्यादा दिखता है। जब 10 प्रतिशत से ज्यादा लोग खुले में शौच करते हैं, तो इसका असर थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जहां ज्यादा लोग खुले में शौच करते हैं, वहां लोगों को अच्छे शौचालय और सीवर सिस्टम की सुविधा नहीं होती।

इससे गंदगी फैलती है और बच्चे बीमार पड़ते हैं। अच्छे शौचालयों का इस्तेमाल करने से बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर होता है। जितने ज्यादा लोग निजी शौचालयों का इस्तेमाल करते हैं, उतना ही बच्चों में स्टंटिंग और अंडरवेट की समस्या कम होती है। निजी शौचालयों का असर अंडरवेट कम करने में ज्यादा होता है।

ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जहां कम लोग पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं और बच्चों में स्टंटिंग (कद छोटा होना) और अंडरवेट (कम वजन) की समस्या ज्यादा है। झुग्गी-झोपड़ियों में जहां कई परिवार एक ही शौचालय इस्तेमाल करते हैं, वहां अक्सर सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। जहां कम लोग पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, वहां ज्यादा लोग खुले में शौच करते होंगे।

गंदगी से बढ़ जाता है बच्चों के मौत का खतरा

गंदगी की वजह से बच्चों की आंतों में एक बीमारी हो जाती है जिसे EED कहते हैं। इससे बच्चे खाने से पोषण नहीं ले पाते और कुपोषित हो जाते हैं। कुपोषण के कारण बच्चों की मृत्यु दर बढ़ जाती है। कुपोषित बच्चे कमजोर होते हैं और उनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होती है। इसलिए, ऐसी बीमारियां जो आम बच्चों के लिए जानलेवा नहीं होतीं, वे कुपोषित बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, बच्चों को कई जरूरी चीजें मिलनी चाहिए ताकि वे स्वस्थ रहें और उनकी जान बच सके। बच्चे के जन्म के समय एक प्रशिक्षित व्यक्ति मौजूद होना चाहिए। बच्चे के जन्म के बाद मां और बच्चे दोनों की अच्छी देखभाल होनी चाहिए। बच्चों को मां का दूध और पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। बच्चों को समय पर सभी जरूरी टीके लगवाने चाहिए। साथ ही बच्चों को होने वाली आम बीमारियों का सही इलाज मिलना चाहिए।

अध्ययन में यह पाया गया है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनने से बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई है। लेकिन, यह कमी सिर्फ शौचालयों की वजह से नहीं है। इसके पीछे कई और कारण भी हैं, जैसे कि ज्यादा मांएं शिक्षित हो रही हैं, गर्भवती महिलाओं को बेहतर देखभाल मिल रही है, ज्यादा बच्चे अस्पताल में पैदा हो रहे हैं, ज्यादा लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा है।

कितने बच्चों की बच सकती है जान?

अगर भारत में अच्छे शौचालयों का इस्तेमाल बढ़ाया जाए, तो बच्चों की मृत्यु दर में काफी कमी आ सकती है। अध्ययन के अनुसार, अगर सभी राज्यों में अच्छे प्राइवेट और पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल 7.2 प्रतिशत बढ़ जाए, तो बच्चों में स्टंटिंग (कद छोटा होना) 7.4 प्रतिशत कम हो जाएगा। स्टंटिंग कुपोषण का एक प्रकार है जो बच्चों के विकास को रोकता है और उन्हें कई बीमारियों का शिकार बनाता है।

अध्ययन के अनुसार, इससे बच्चों की मृत्यु दर में 4.8 प्रतिशत की कमी आ सकती है, जिससे 6.5 लाख बच्चों की जान बच सकती है। उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में बच्चों की मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। इन राज्यों में अच्छे शौचालयों के इस्तेमाल से बच्चों की मृत्यु दर में सबसे ज्यादा कमी आ सकती है।

महिलाओं की शिक्षा का बच्चों की सेहत पर गहरा असर होता है। अगर हर राज्य में 10वीं पास महिलाओं की संख्या में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि हो, तो बच्चों की मृत्यु दर में 6.3 प्रतिशत की कमी आ सकती है। इससे 8.5 लाख बच्चों की जान बच सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में महिलाओं की शिक्षा का स्तर बढ़ाने से बच्चों की मृत्यु दर में सबसे ज्यादा कमी आ सकती है। अगर हर राज्य में 10वीं पास महिलाओं की संख्या को 100 प्रतिशत तक पहुंचाने के लिए 10 प्रतिशत का सुधार किया जाए, तो 8.8 लाख बच्चों की जान बच सकती है।

हर दिन को जीना: जीवन, मृत्यु और आत्मचिंतन की एक भावपूर्ण यात्रा

डॉ। तनु जैन
सिविल सेवक रक्षा मंत्रालय आध्यात्मिक वक्ता

हाल ही में एक घटना ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। एक प्रिय पारिवारिक मित्र का असमय निधन हुआ। वह एक सफल करियर, सुंदर परिवार और समृद्ध बचपन की स्वामिनी थीं। उनका स्वर आज भी मेरे भीतर गूंजता है, जैसे वे अब भी यहीं हैं। उनकी उम्र, उनके हालात — सब कुछ सोचकर मैं हिल गई हूँ। उनका परिवार, उनके बच्चे... कैसे आगे बढ़ पाएँगे इस जीवन में?यह घटना मेरे भीतर एक गहरा प्रश्न छोड गई —क्या मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ? हम जीते हैं जैसे कल हमारे पास सुनिश्चित है। हम योजनाएँ बनाते हैं, संबंधों में उलझते हैं, कार्यों में खो जाते हैं — और भूल जाते हैं कि मृत्यु हर क्षण हमारे साथ चल रही है।कोई ज्योतिषी मृत्यु की सटीक घडी नहीं बता पाया है। कोई संत, कोई विद्वान — नहीं जानता कि मृत्यु कब आएगी। वह अचानक दस्तक देती है। बिना पूछे आती है। और फिर सब शांत हो जाता है। तो क्या हम जीते हैं इस सच्चाई के साथ? नहीं। हम ऐसे जीते हैं जैसे हम अमर हैं।"असल प्रश्न यह नहीं है कि मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं।

असल प्रश्न यह है कि क्या मृत्यु से पहले आप सच में जिए?" — ओशोइस क्षण ने मुझे सिखाया कि मृत्यु की सच्ची तैयारी केवल एक है —हर दिन को जागरूकता, उद्देश्य और सच्चाई के साथ जीना।ना कि दो साल बाद, या जब ज़िंदगी "ठीक" हो जाएगी। आज। अभी। इसी क्षण। मैंने खुद से पूछा: क्या मैं हर दिन को वैसे जी रही हूँ, जैसे यह मेरा आखिरी दिन हो सकता है?बहुत से लोग सलाह देते हैं, सच्चे दिल से भी। पर हर आत्मा को अपनी राह खुद चुननी होती है। जीवन आपका है। हर साँस आपकी है। आपको तय करना होगा कि आप इसे कैसे जीते हैं।

1. कार्य करें — सिर्फ परिणामों के लिए नहीं, मानसिक संतुलन के लिए कार्य आपको मानसिक संतुलन देता है। यह मन को दिशा देता है। लेकिन राह चुनिए — होश से, समझ से। अपनी शक्ति और सीमाओं को पहचानिए। कार्य बोझ नहीं, साधना बन जाए।

2. रिश्तों में सतर्कता बरतें हर संबंध में शामिल होना ज़रूरी नहीं। केवल वही रिश्ते निभाइए जो आत्मा को छूते हैं। लोगों को मत दौडिए। अपने सपनों का पीछा कीजिए।दूसरों की योजनाओं में खुद को मत गुम कीजिए।अपनी अग्नि को जगाइए। उसे संजोइए।

3. उद्देश्य पर केंद्रित रहें हम अपने विचारों में, तुलना में, चिंता में ऊर्जा गवाँ देते हैं। छोडिए ये सब। लक्ष्य पर केंद्रित रहिए। छोटी प्रगति भी प्रगति है। झूठे गुरु, डर बेचने वाले पंडितों से बचिए।आपको और नियमों की नहीं, और शांति की ज़रूरत है।

4. अपने हृदय की धडकन को सुनिएआपका हृदय हर पल कह रहा है — "तुम जीवित हो।"उस धडकन को महसूस कीजिए।हर सांस को प्रेमपूर्वक लीजिए। मृत्यु की तैयारी, जीवन को जागरूकता से जीना है।

5. ध्यान की ओर लौटिएअब आप अपनी ऊर्जा को यूँ ही बिखेर नहीं सकते।विपश्यना कीजिए, ध्यान कीजिए, मौन साधना कीजिए।जो भी आपको स्वयं से जोडता है — वही अपनाइए।मन को व्यर्थ की उलझनों से बचाइए।"भीतर जियो। बाहर की घटनाओं से मत डोलो।" — श्री अरविंद

अपने आप से पूछिए:

•क्या मैं जीवन में कुछ मिस कर रहा हूँ?
•क्या मुझे कुछ खास चाहिए?
•मेरी आत्मा की पुकार क्या है?

पहचानिए। पथ चुनिए। उसी दिशा में चलिए।जीवन का कोई निश्चित मार्गदर्शक नहीं होता। आत्मा का कोई नक्शा नहीं होता।पर यदि आप हर दिन को सजगता से जीते हैं, तो आप मृत्यु की ओर सबसे सुंदर तैयारी कर रहे हैं।हर जागरूक साँस, हर सच्चा कर्म, एक पूर्णता है।कौन जानता है कल क्या होगा?किसे पता है भाग्य क्या लाया है? कोई नहीं जानता। झूठे वादों और ढकोसलों से दूर रहिए।अपनी राह चुनिए। अपने मन की सुनिए। "जो मृत्यु को सुंदर बना दे, वही सच्चा जीवन है।"

लेखक के विचार व्यक्तिगत हैं।

ऑपरेशन सिंदूर

ऑपरेशन सिंदूर' से क्या हासिल हुआ? सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया को भी दिया स्पष्ट संदेश

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव बढ़ता गया। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया और खूंखार दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमले की तमाम कोशिशें कीं, लेकिन नाकाम रहे। जवाब में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और उसके घर में घुसकर कई जख्म दिए। इसके बाद पड़ोसी को संघर्ष विराम के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा।

6 और 7 मई, 2025 के बीच की रात 1.05 से लेकर 1.30 बजे तक भारतीय सशस्त्र बलों ने तीनों सेनाओं के साथ मिलकर एक सैन्य अभियान चलाया, जिसका कोड नाम था- ऑपरेशन सिंदूर. इसका उद्देश्य था, भारत की ज़मीन पर सीमा पार आतंकवाद के लिए ज़िम्मेदार गुटों की क्षमताओं को ख़त्म करना. इस कार्रवाई में पाकिस्तान और उसके क़ब्ज़े वाला कश्मीर (PoJK) में उन ठिकानों को निशाना बनाया गया, जहां से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता था |

भारत ने कहा कि ये कार्रवाई सीमा पार आतंकवाद को 'रोकने' और उससे 'निपटने' के इरादे के साथ किए गए थे, ख़ास तौर से 22 अप्रैल, 2025 को हुए पहलगाम जैसे हमलों को रोकने के लिए, जिनमें 26 नागरिकों (25 भारतीय और एक नेपाली) की जान ले ली गई थी. जम्मू-कश्मीर की बैसरन घाटी में हुए इस हमले के लिए भारत सरकार ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के सहयोगी गुट 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (TRF) को जिम्मेदार ठहराया. इस संगठन ने शुरू में हमले की ज़िम्मेदारी ली भी थी, लेकिन बाद में 'साइबर छेड़छाड़' का आरोप लगाते हुए इससे इनकार कर दिया था |

भारत ने अपनी कार्रवाई को ' लक्ष्य-केंद्रित, नपी-तुली और नॉन एस्केलेटरी (गैर भड़काऊ)' बताया. इस ऑपरेशन में जान-बूझकर पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं बनाया गया, ताकि तनाव बढ़ने के ख़तरे को कम किया जा सके. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर 'अब भी चल रहा है'. उनका यह भी कहना था कि इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकी मारे गए हैं, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद (JeM) का लीडर अब्दुल रऊफ अज़हर जैसा बड़ा नाम भी शामिल है|

जो दिसंबर 1999 में IC-814 की हाइजैकिंग और अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या में शामिल था. ख़बर यह भी है कि JeM प्रमुख मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य भी इसमें मारे गए हैं |

यह 1971 के युद्ध के बाद भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किया गया सबसे बड़ा सैन्य अभियान था. इसके अलावा, 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयरस्ट्राइक जैसे पिछले ऑपरेशनों के विपरीत, जो कि सीमित दायरे में एक लक्ष्य-केंद्रित कार्रवाई थी, ऑपरेशन सिंदूर बहु-क्षेत्रीय और कहीं अधिक सटीक कार्रवाई थी, जो पाकिस्तान के क़ब्ज़े वाले कश्मीर में ही नहीं, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी की गई. यह संकेत है कि सीमा पार आतंकवाद को लेकर भारत के नज़रिये में रणनीतिक बदलाव आया है.

इस ऑपरेशन में नौ जगहों को निशाना बनाया गया- चार पाकिस्तान में और पांच उसके क़ब्ज़े वाले कश्मीर में, जो लश्कर, जैश-ए-मोहम्मद और हिज़बुल मुजाहिदीन जैसे भारत-विरोधी आतंकवादी समूहों के ठिकाने थे. इनमें मुरीदके (लश्कर मुख्यालय) और बहावलपुर (जैश मुख्यालय) जैसे ठिकाने भी शामिल थे |

ऑपरेशन सिंदूर द्वारा पाकिस्तान और PoJK में ख़त्म किए गए आतंकवादी ढांचे की सूची

साइट नंबर 1 : मस्जिद सैयदना बिलाल/ हज़रत बिलाल, मुज़फ़्फ़राबाद (PoJK)

ऑपरेशन सिन्दूर के भारतीय सेना के कार्यवाही के बाद का दृश्य

साइट नंबर 2 : गुलपुर, कोटली (PoJK) का प्रशिक्षण शिविर

साइट नंबर 3 : सवाई नाला कैंप, मुज़फ़्फ़राबाद (PoJK)

साइट नंबर 4 : मस्जिद अहले-हदीस, बरनाला, भिम्बर (PoJK)

ऑपरेशन सिन्दूर के भारतीय सेना के कार्यवाही के बाद का दृश्य

साइट नंबर 5 : मस्जिद अब्बास, कोटली (PoJK)

साइट नंबर 6 : सरज़ाल कैंप, सियालकोट (पाकिस्तान)

ऑपरेशन सिन्दूर के भारतीय सेना के कार्यवाही के बाद का दृश्य

साइट नंबर 7 : महमूना ज़ोया, सियालकोट (पाकिस्तान)

ऑपरेशन सिन्दूर के भारतीय सेना के कार्यवाही के बाद का दृश्य

साइट नंबर 8 : मरकज़ तैयबा, मुरीदके (पाकिस्तान)

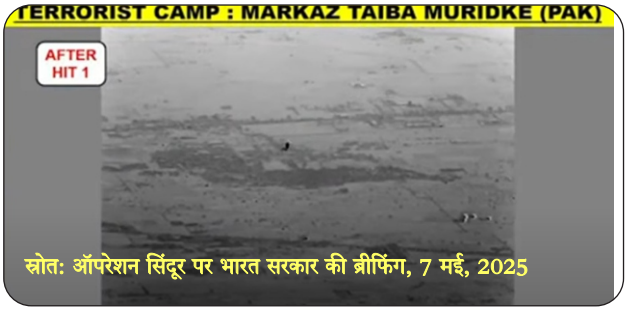

ऑपरेशन सिन्दूर के भारतीय सेना के कार्यवाही के बाद का दृश्य

साइट नंबर 9 : मस्जिद सुभान अल्लाह, बहावलपुर (पाकिस्तान)

ऑपरेशन सिन्दूर के भारतीय सेना के कार्यवाही के बाद का दृश्य

7 मई की ब्रीफिंग में भारत सरकार ने पाकिस्तान और PoJK में 21 आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों की सूची भी जारी की, जिनमें लक्ष्य बनाए गए ये 9 ठिकाने भी शामिल थे |

Barak-8/MRSAM

MRSAM यानी Medium Range Surface to Air Missile एक अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली है, इसे भारत में Barak-8 नाम से भी जाना जाता है. यह सिस्टम मध्यम दूरी तक आने वाली हवाई खतरों जैसे कि लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, क्रूज़ मिसाइल और अन्य गाइडेड हथियारों को नष्ट करने में सक्षम है.

Range | 70–100 किलोमीटर
Warhead | 60 से 70 KG
Radar | मल्टी-फंक्शन रडार

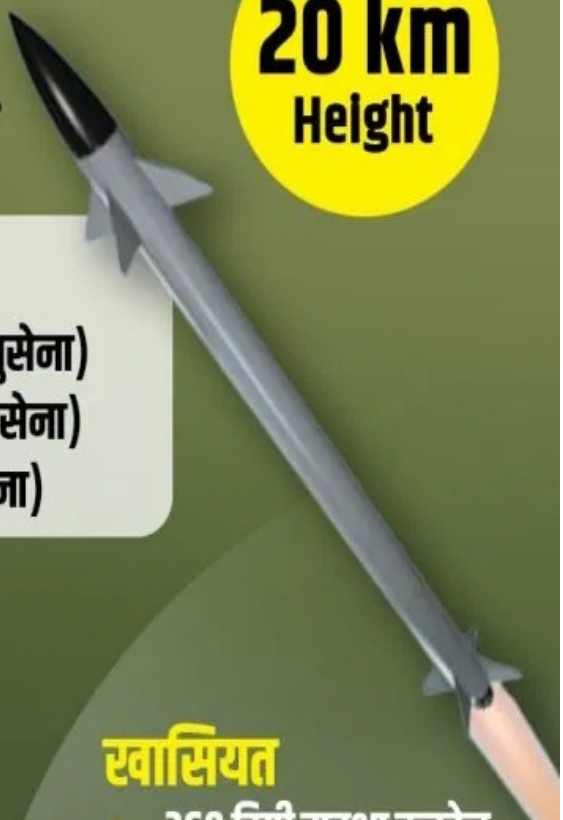

MRSAM के वेरिएंट्स

- IAF MRSAM (भारतीय वायुसेना)
- IA MRSAM (भारतीय थल सेना)
- IN LRSAM (भारतीय नौसेना)

SPEED
2 मैक से अधिक
(लगभग 2,400 किमी/घंटा)

TARGET
एक साथ कई लक्ष्यों को कर सकता है नष्ट

खासियत

- 360 डिग्री सुरक्षा कवरेज
- नेटवर्क-सेंट्रिक ऑपरेशन
- ऑल वेदर ऑपरेशन
- फुली मोबाइल सिस्टम

ऑपरेशन सिंदूर

ऑपरेशन सिंदूर खुफ़िया तरीके से की गई ऐसी कार्रवाई थी, जिसमें सैटेलाइट निगरानी, ड्रोन तकनीक और खुफ़िया सूत्रों से मिली जानकारी का पूरा लाभ उठाया गया था. भारतीय वायु सेना (IAF) के लड़ाकू विमानों ने प्रशिक्षण अभ्यास के नाम पर उड़ान भरी, जिसमें रडार ब्लैकआउट (रडार संकेतों को रोक देना, ताकि विमानों के बारे में पता न लगे) किया गया और NOTAM (नोटिस टू एयरमैन), यानी पायलटों या एयर कंट्रोल से जुड़े लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली नोटिस जारी की गई, ताकि हमारे विमानों की गतिविधियों को छिपाई जा सके और दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके. स्टैंड-ऑफ हथियारों (दूर से दागे जाने वाले मिसाइल या बम) के ज़रिये यह ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें भारतीय क्षेत्र में रहकर लड़ाकू विमानों ने मिसाइलें दागीं. भारत ने इस ऑपरेशन में दो प्रमुख हथियारों का इस्तेमाल किया- स्कैल्प (SCALP) और हैमर (HAMMER). इसके अलावा भारत ने स्काईस्ट्राइकर आत्मघाती ड्रोन का भी उपयोग किया, जो 10 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है.

SCALP को स्टार्म शैडो के नाम से भी जाना जाता है. यह हवा से लॉन्च किया जाने वाला एक क्रूज मिसाइल है, जो अपनी स्टेल्थ क्षमता के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है. यह मुख्य रूप से दुश्मन के इलाके में लंबी दूरी के बड़े हमलों के लिए उपयोग में लाया जाता है.

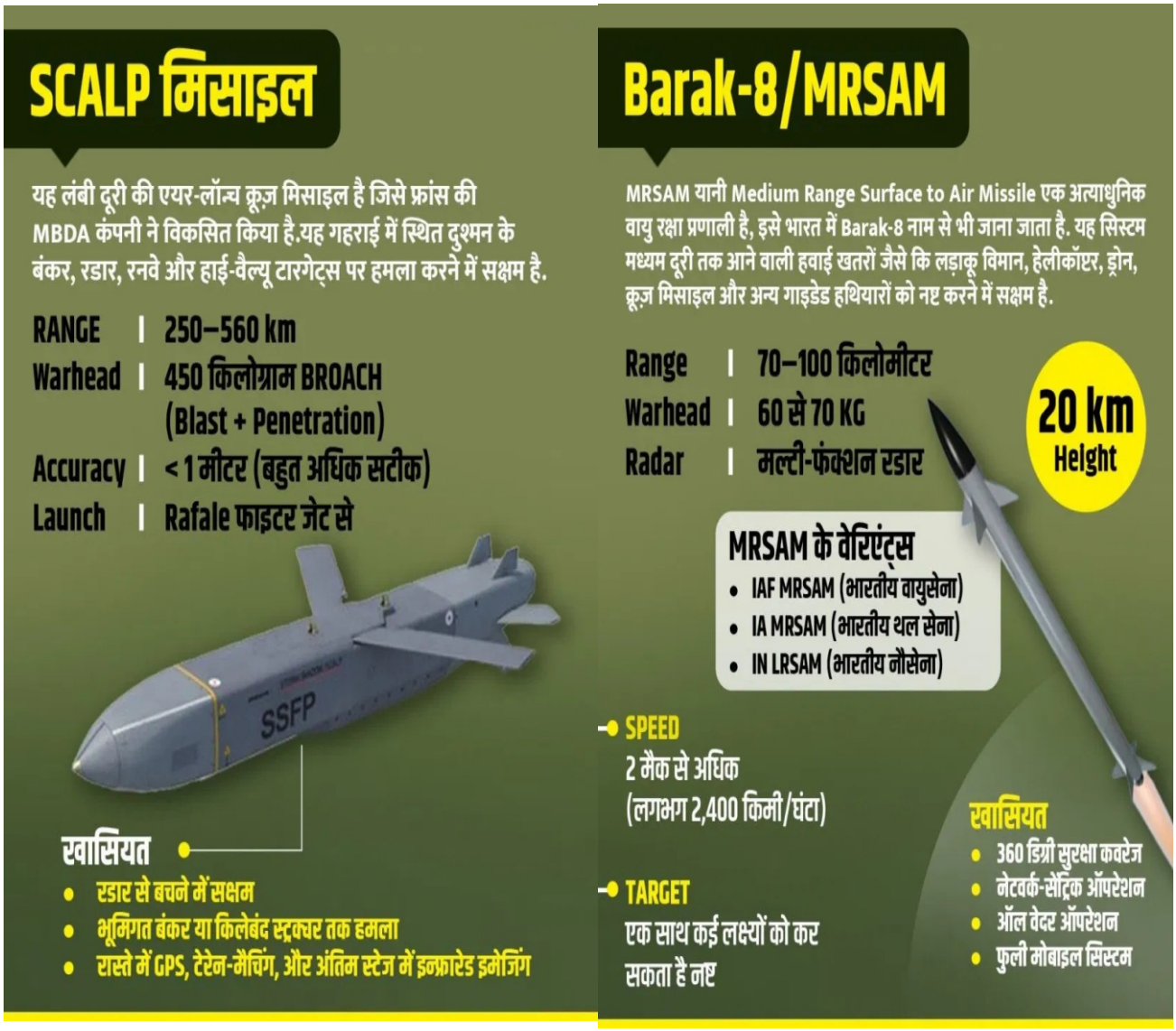

राफेल की प्रमुख खासियतें

राफेल एक अत्याधुनिक मल्टी-रोल लड़ाकू विमान है. यह वायु, समुद्र और जमीनी लक्ष्य को एक साथ नष्ट करने की क्षमता रखने वाला फाइटर जेट है.

3,700 km
रेंज

50,000 फीट
सर्विस सीलिंग

9.5 टन
हथियार क्षमता

2
इंजन

Type:
मल्टी-रोल फाइटर जेट

Speed:
1.8 मैक (लगभग 2,222 किमी/घंटा)

रडार सिस्टम :
दुश्मन के रडार और मिसाइलों से बचाव में सक्षम

नेशनल फ्रंटियर
www.nationalfrontier.in

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने 17 दिसंबर, 2023 को बताया कि 25 किलोमीटर की दूरी तक हवा में एक साथ चार लक्ष्यों को निशाना बनाने की आकाश मिसाइल प्रणाली की क्षमता का प्रदर्शन किया।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कहा कि भारत एक फायरिंग यूनिट का उपयोग करके चार टारगेट को ढेर करने की क्षमता प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है।

डीआरडीओ द्वारा देश में विकसित इस मिसाइल का प्रदर्शन 12 दिसंबर को अस्त्रशक्ति-2023 सैन्य अभ्यास के दौरान किया गया।

इस अभ्यास का आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा किया था।

आकाश 25 किलोमीटर तक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसका इस्तेमाल प्राथमिक रूप से संवेदनशील इलाकों एवं ठिकानों को हवाई हमलों से बचाने के लिए किया जाता है।

इस अभ्यास के दौरान चार लक्ष्य एक-दूसरे से बहुत नजदीक रहकर एक ही दिशा से आ रहे थे और फिर अलग-अलग दिशाओं से हमला करने के लिए अलग- अलग हो गए थे।

आकाश फायरिंग यूनिट को फायरिंग लेवल रडार (FLR), फायरिंग कंट्रोल सेंटर (FCC) और पांच मिसाइलों वाले दो आकाश एयरफोर्स लांचर (AAFL) के साथ तैनात किया गया था।

बेहद कम समय में कुल चार मिसाइलें लांच की गई और सभी चार लक्ष्यों को एक साथ अधिकतम दूरी पर सफलतापूर्वक आकाश ने निशाना बनाया ।

आकाश मिसाइल प्रणाली ऐसे प्रमुख प्लेटफार्मों में शामिल है जिनका भारत मित्र देशों को निर्यात कर रहा है।

भारत डोर्नियर-228 विमानों, 155 मिलीमीटर की अर्टिलरी गन, ब्रह्मोस मिसाइलों, बारूदी सुरंग रोधी च बख्तरबंद वाहनों, गोला-बारूद, थर्मल इमेजर्स एवं वैमानिकी से जुड़े विभिन्न उपकरणों का भी निर्यात करता है।

आकाश मिसाइल सिस्टम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) की एक छोटी दूरी की सरफेस टू एयर (एसएएम) एयर डिफेंस सिस्टम है।

यह सिस्टम दुश्मन के हवाई हमलों से एक बड़े इलाके की रक्षा कर सकता है।

आकाश वेपन सिस्टम (AWS) ग्रुप मोड या ऑटोनॉमस मोड में एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है।

इसमें बिल्ट-इन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर-काउंटर मेज़र्स (ECCM) की विशेषताएं हैं।

इस संपूर्ण हथियार प्रणाली को मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर तैनात किया जा सकता है।

आकाश मिसाइल सिस्टम 4-25 किलोमीटर की रेंज में उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर, लड़ाकू जेट और यूएवी को प्रभावी ढंग से मार गिरा सकता है।

यह लक्ष्य का पता लगाने से लेकर मार गिराने तक की पूरी प्रक्रिया को त्वरित गति से पूरा करता है।

इसके साथ ही इसका पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक है।

यह एक्टिव और पैसिव जैमिंग को प्रभावी तरीके से रोक सकता है।

इसे रेल या सड़क मार्ग से तेजी से कहीं भी ले जाया जा सकता है और जल्दी से तैनात किया जा सकता है।

कैसे काम करता है भारत का S400 'सुदर्शन चक्र' जिसने पाक मिसाइलों, ड्रोन्स को हवा में उड़ा दिया

पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भारत-पाक तनाव में गुरुवार रात अहम मोड़ आया, जब पाकिस्तान की तरफ से भारतीय शहरों, हवाई अड्डों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। भारत की तरफ से पाकिस्तान को जवाब दिया हमारे S-400 सुदर्शन चक्र (S-400 Sudarshan Chakra) ने। यह दुनिया के सबसे एडवांस्ड लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टमों में से एक है। भारत ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को रूस से खरीदा है। रिपोर्टों के अनुसार, देश में ऐसे तीन एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेशनल हैं और साल 2026 तक दो और सिस्टम आ जाएंगे। गुरुवार रात हुई कार्रवाई के बाद हर तरफ S-400 सुदर्शन चक्र की चर्चा है। इसकी तारीफ इसलिए हो रही है, क्योंकि जवाब में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम उसके कई शहरों में तबाह हो गया। आइए जानते हैं कैसे काम करता है S400 'सुदर्शन चक्र', क्या है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी।

S-400 एक मोबाइल सर्फेस टु एयर मिसाइल सिस्टम है। यहां मोबाइल से मतलब है कि इसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। इस सिस्टम को साल 1990 के दशक में रूस में डेवलप किया गया। तब इसे S-300 सिस्टम के अपग्रेड साल 2007 में इसे सेवा देने के लिए अप्रूव किया गया। रूस अब इससे भी एडवांस एस-500 सिस्टम पर काम कर रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, रूस से इस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए भारत ने कुछ साल पहले डील की थी। रिपोर्टों के अनुसार, अबतक ऐसे तीन एयर डिफेंस सिस्टम देश में ऑपरेशन हो गए हैं।

कोई भी मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम रडार और अन्य सेंसरों की मदद से अपना काम करता है। इसका मुख्य लक्ष्य होता है डिटेक्ट करना, ट्रैक करना और हवाई खतरों से भिड़ना। मोबाइल एयर डिफेंस की सबसे बड़ी खूबी है कि इसे फौरन कहीं भी तैनात किया जा सकता है। इसमें लगे रडार और अन्य सेंसर्स दुश्मन के हवाई खतरों को ट्रैक करते हैं। अन्य सेंसर्स में इन्फ्रारेड कैमरा, रेंज फाइंडर्स आदि शामिल होते हैं। जैसे ही दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर लिया जाता है, उसके बाद शुरू होता है इंगेजमेंट। इस इंगेजमेंट में मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइलों को फायर किया जाता है, जो दुश्मन की मिसाइलों से टकराकर हवा में ही सारा खेल खत्म कर देती हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार, S-400 एक साथ 300 रिपोर्ट के अनुसार, इस एयर डिफेंस सिस्टम में 4 प्रकार की मिसाइल सुरक्षा के लिए होती हैं। 40N6 एक लॉन्ग रेंज मिसाइल जो 400 किलोमीटर तक जाकर दुश्मन की मिसाइल, फाइटर जेट को तबाह कर सकती है। 48N6 की रेंज 250 किलोमीटर तक है और 9M96E और 9M96E2 शॉर्ट रेंज मिसाइलें, जिनकी रेंज 120 किलोमीटर तक है। ये सभी तेजी से दुश्मन मिसाइलों की ओर बढ़ती हैं और उनसे टकराकर उन्हें खत्म कर देती हैं।

एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में इस्राइल के आयरन डोम का नाम भी खूब आता है। लेकिन एस400 और आयरन डोम की खूबियों में फर्क है। डिफेंसएक्सपी की रिपोर्ट के अनुसार, एस400 का दायरा विशाल है। यह ना सिर्फ मिसाइलों, बल्कि ड्रोन, फाइटर जेट्स को निशाना बना सकता है।

भारत की 'बराक 8 मिसाइल' ने पाकिस्तान को कैसे चटाई धूल?

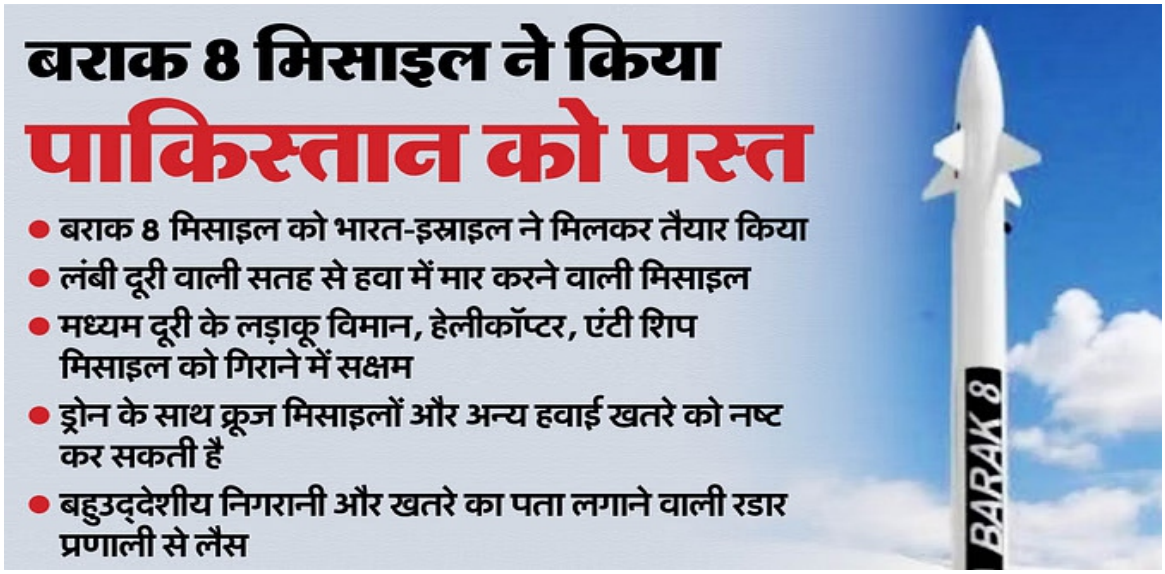

हाल ही में भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया था जिसे भारत के एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया। इस ऑपरेशन में भारत के बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी काफी चर्चा हुई है।

भारत के सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पहले पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। इसके बाद भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान पाकिस्तान के ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट को रोका। फिर भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर के पाकिस्तान को सदमे में डाल दिया। इसके बाद पाकिस्तान की मिन्नत पर दोनों देशों के बीच सीजफायर हुआ। भारत के इस पूरे ऑपरेशन में बराक-8 मिसाइल की भी खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी हमलों को रोकने में इस मिसाइल ने बड़ी भूमिका निभाई है। आइए जानते हैं कि बराक-8 क्यों है भारत के लिए खास और इसकी खूबियां क्या हैं।

भारत और इजरायल ने मिलकर बनाया

बराक-8 मिसाइल का निर्माण भारत की रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO और इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने साथ मिलकर किया है। खास बात ये भी है कि भारतीय सेना ने बीते महीने अप्रैल में ही बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अंतिम परीक्षण पूरा किया था और इसे संचालन के लिए तैयार कर लिया था। साल 2017 में भारत और इजरायल ने बराक-8 मिसाइल के निर्माण के लिए सौदा किया था। Times Of Israel के मुताबिक, ये सौदा 2.5 बिलियन डॉलर का था।

बराक-8 मीडियम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली डिफेंस मिसाइल (MR-SAM) है। बराक-8 दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन, निगरानी विमान, हेलीकॉप्टर और यहां तक कि मिसाइलों को भी मार गिराने में सक्षम है। बराक-8 मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की है। बराक-8 मिसाइल की स्पीड 2 मैक यानी आवाज की गति से दोगुनी है।

बराक-8 मिसाइल कई तरह से खतरों के खिलाफ 360 डिग्री की सुरक्षा प्रदान करती है। इसके पास मल्टी-मिशन रडार और फ्लेक्सिबल कंट्रोल और कमांड सिस्टम मौजूद है।

बराक-8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक साथ कई लक्ष्यों को टारगेट कर के निशाना बनाने में सक्षम है। इसमें मल्टी-फंक्शन सर्विलांस ट्रैक और गाइडेंस रडार लगा है जो कि सटीक तरीके से लक्ष्य को टारगेट करने में मदद करता है। ये मिसाइल सिस्टम सभी मौसम और दिन व रात दोनों समय काम कर सकता है।

पाकिस्तान का हमला किया नाकाम

भारतीय सेना ने अप्रैल 2025 की शुरुआत में बराक-8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अंतिम और सफल परीक्षण किया था और इसे संचालन के लिए तैयार किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय वायुसेना और नौसेना भी बराक-8 मिसाइल का इस्तेमाल करती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से संभावित हमले की संभावना को देखते हुए भारत ने बराक-8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर रखा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसने पाकिस्तान के कई मिसाइल और ड्रोन आदि को निशाना बनाकर ध्वस्त कर दिया है।

ऑपरेशन सिंदूर में दिखा राफेल का दम, कल्पना से भी परे दे डाली सजा

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वादे के मुताबिक कल्पना से भी परे आतंकियों को सजा दी है और सजा देने में न सिर्फ भारतीय सेना का बल्कि राफेल का भी बड़ा रोल रहा है. जी हां वहीं राफेल जिसको लेकर सियासी पारी भी कई बार हाई हो चुका है. इसी लड़ाकू विमान ने पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों की मौत का न सिर्फ बदला लिया बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों को संतुष्टि भी दी है |

पहली बार भारतीय वायुसेना ने राफेल लड़ाकू विमानों को सक्रिय युद्ध अभियान में शामिल किया, जिससे यह स्पष्ट संकेत गया कि भारत अब अपने अत्याधुनिक रक्षा संसाधनों के उपयोग में हिचक नहीं दिखाएगा.

ऑपरेशन सिंदूर, विशेष रूप से पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान गई थी, के जवाब में शुरू किया गया था. यह घटना केवल एक आतंकी हमला नहीं थी, बल्कि भारत की संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा पर सीधा हमला था. इसका उत्तर भारत ने अत्यंत सटीकता और संयम के साथ दिया.

ऑपरेशन के दौरान राफेल विमानों ने भारतीय वायुसीमा से ही अत्याधुनिक SCALP क्रूज़ मिसाइलें और HAMMER प्रिसीजन-गाइडेड बम दागे. इन हथियारों की विशेषता यह है कि वे 500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक सटीक निशाना लगा सकते हैं, जिससे पायलटों को दुश्मन की सीमा में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होती |

ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी क्षेत्रों – मुरीदके, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद और कोटली – में स्थित नौ प्रमुख आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया. भारत ने इस अभियान में पाकिस्तानी सेना के ठिकानों से सावधानीपूर्वक बचते हुए केवल आतंकवादी इन्फ्रास्ट्रक्चर को ही निशाना बनाया, जिससे यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नैतिक और सैन्य संतुलन की मिसाल बन गया |

क्यों खास थे राफेल विमान

राफेल विमानों की भूमिका इस मिशन में केंद्रीय रही. ये लड़ाकू विमान न केवल गति और मारक क्षमता में अव्वल हैं, बल्कि इनकी एवियोनिक्स, सेंसर और स्टील्थ क्षमताएं आधुनिक युद्ध की जरूरतों के अनुरूप हैं. यह पहली बार था जब भारत ने राफेल की मारक क्षमता को वास्तविक ऑपरेशन में परखा, और यह परीक्षण अत्यंत सफल रहा.

सभी लड़ाकू विमान सुरक्षित लौट आए, जिससे मिशन की तकनीकी दक्षता और पायलटों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता का भी प्रमाण मिलता है. खास बात यह रही कि भले ही पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर कुछ स्वीकार नहीं किया, लेकिन कई पाकिस्तानी मीडिया सूत्रों ने आतंकी ठिकानों पर गंभीर नुकसान और हताहतों की बात को स्वीकार किया. यह इस बात का अप्रत्यक्ष प्रमाण है कि भारत का हमला सटीक और प्रभावी रहा |

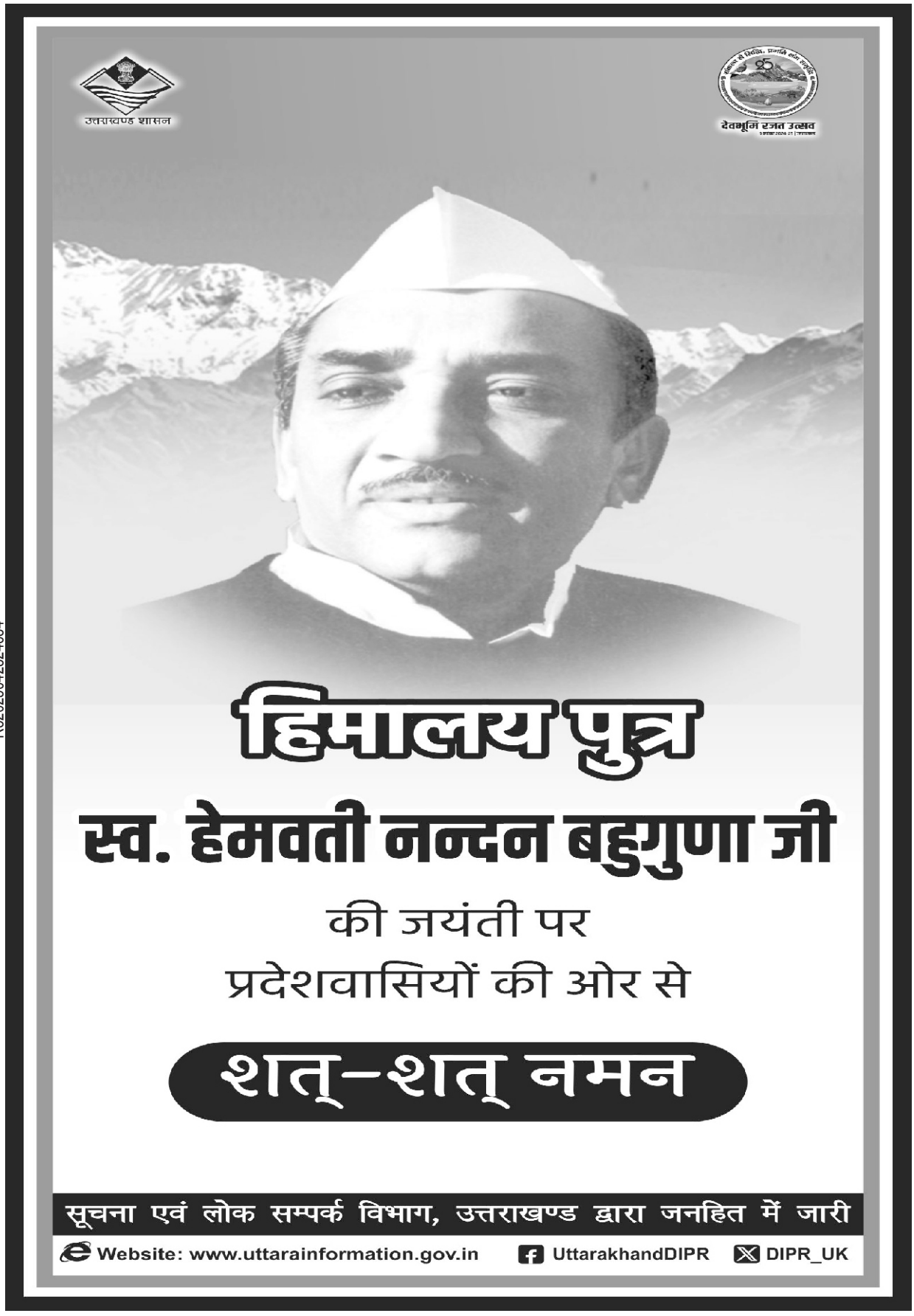

Ro2025042824684

ब्रह्म के स्वरूप का गूढ़ रहस्य

डॉ. शरद कुमार सिंह

भारत के जाने-माने आध्यात्मिक गुरु श्री शरद ठाकुर जी ने गुजरात में ब्रह्म के रूप और गुण रहस्य को उद्घाटित करते हुए धर्म सभा को संबोधित किया और श्वेताश्वतर उपनिषद् 6.11 पर दार्शनिक विवेचना करते हुए समझाया कि

> एको देवः सर्वभूतेषु गूढःसर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा।कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासःसाक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च॥

उपनिषदों का मूल संदेश है – "य आत्मा ब्रह्म" अर्थात् आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद् का यह मंत्र उसी ब्रह्म-तत्व को अत्यंत वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक भाषा में प्रकट करता है।

यह श्लोक न केवल ईश्वर के अद्वैत स्वरूप का उद्घाटन करता है, बल्कि जगत, जीव और ईश्वर के मध्य संबंध को भी स्पष्ट करता है। यह उपनिषद का घोषवाक्य नहीं, बल्कि अन्तर्ज्ञान की चरम स्थिति का कथन है।

1. "एको देवः" – एकमेव अद्वितीय ब्रह्म

"एको" अर्थात् केवल एक ही, न द्वितीयो अस्ति। यह 'एक' गणनात्मक नहीं, बल्कि अखण्ड एकत्व को सूचित करता है। यह वही ब्रह्म है जो :

बनकर सर्वत्र व्याप्त होता है।

ऋग्वेद में "एकोहं बहुस्याम" कहकर प्रकट होता है,

मुण्डक उपनिषद में "ब्रह्मैवेदं सर्वम्"

यह 'एक' देव न तो मूर्त है, न अमूर्त – वह चेतना है, जो हर रूप में प्रकट हो सकती है, और हर सीमाओं से परे भी है।

2. "सर्वभूतेषु गूढः" – परमात्मा की लीलामयी अदृश्यता

'गूढ' का अर्थ है – छिपा हुआ, अदृश्य। यह वह सत्य है जो प्रत्येक जीव में तो है, परंतु ज्ञेय नहीं बनता। उसकी उपस्थिति इतनी सूक्ष्म है कि:

वह अनुभव का विषय है, बौद्धिक विश्लेषण का नहीं।

जैसे गंध वायु में लुप्त होती है, वैसे ही आत्मा शरीर में।

शंकराचार्य की भाषा में – "न गृहीतेऽस्मिन आत्मनि किञ्चिद् गृहीतम्, न विगृहीते किञ्चिद् अवगृहीतम्।"(यदि आत्मा को नहीं जाना, तो कुछ भी नहीं जाना; और यदि उसे जान लिया, तो सब कुछ जाना।)

3. "सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा" – व्यापकता और अंतर्ज्ञान का रहस्य

सर्वव्यापी – वह समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है;सर्वभूतान्तरात्मा – और प्रत्येक जीव के भीतर भी।

यहाँ ईश्वर केवल एक सृष्टिकर्ता नहीं है – वह जीवन की प्रत्येक स्पंदन का स्रोत है।

यहाँ अद्वैत वेदांत, सांख्य और योग का संगम है:

सांख्य कहता है – पुरुष चेतन है, प्रकृति जड है।

योग कहता है – चित्त की वृत्तियाँ बाधक हैं, आत्मा साक्षी है।

वेदांत कहता है – आत्मा और ब्रह्म एक हैं।

यही अंतर्ज्ञान उपनिषद का हृदय है – ब्रह्म न केवल बाहर है, वह भीतर भी है – 'अन्तर्यामि' है।

4. "कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः" – नियंता, परन्तु अकर्मा

कर्मों का 'अध्यक्ष' वह है, परन्तु स्वयं कर्म से परे है। यह अत्यंत गूढ़ है।यहाँ उपनिषद एक "गवर्निंग इंटेलिजेंस" की बात करता है –जो सभी जीवों के अंदर बैठकर उनके संस्कारों और वासनाओं के अनुसार फल प्रदान करता है, लेकिन स्वयं कर्ता नहीं है।

सर्वभूताधिवासः – वह सभी में वास करता है, परन्तु किसी से बंधता नहीं।यह योगवशिष्ठ का सिद्धांत है – "आत्मा न करता, न भोक्ता, वह केवल द्रष्टा और साक्षी है।"

5. "साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च" – साक्षी भाव और निर्गुण ब्रह्म की महिमा

यह सबसे उच्चतम विवेचना है:

साक्षी – वह दृष्टा है, जो सब देखता है, परंतु कभी बंधता नहीं।

चेता – वह चेतना है, जिससे समस्त जीव चेतन होते हैं।

केवलः – वह अकेला है, स्वतंत्र है – किसी द्वैत से बंधा नहीं।

निर्गुणः – वह गुणों (सत्त्व, रज, तम) से परे है, गुणातीत है।

यहाँ हम ब्रह्म की उस अवस्था तक पहुँचते हैं जहाँ वह सभी सीमाओं से परे है –न वहाँ नाम है, न रूप; न वहाँ कारण है, न कार्य।केवल शुद्ध 'अहं', शुद्ध 'स्व'।

श्वेताश्वतर उपनिषद् का यह श्लोक केवल एक दार्शनिक उद्घोष नहीं है, यह जीवन और जगत के मूल सत्य का उद्घाटन है। यह हमें सिखाता है:

हम किसी बाह्य देवता को खोजने न निकलें, क्योंकि वह हमारे भीतर ही छिपा हुआ है।

कर्म करते हुए भी हम साक्षी बन सकते हैं – यही योग का सार है।

आत्मा, जो भीतर स्थित है – वह न बदलती है, न बंधती है, केवल देखती है और जानती है।उपनिषद् हमें बताता है:

"नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन।

यमेवैष व णुते तेन लभ्यः – तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्॥"

(यह आत्मा न तो वाक् से, न बुद्धि से, न ही शास्त्रों से प्राप्त होती है, वह उसी को प्राप्त होती है जिसे वह स्वयं प्रकट होना

लेखक के विचार व्यक्तिगत हैं।

ORGANIC INDIA®
BOOST YOUR METABOLISM
with the delicate flavours of spices.
CERTIFIED ORGANIC
NATURALLY DETOXIFYING
NATURALLY DELICIOUS
#SavourTheFlavoursofHealth
with GREEN TEA, Ginger & Cinnamon
ORGANIC INDIA®
MADE WITH ORGANIC INGREDIENTS
TULSI DETOX KAHWA
EARTH SEER
Helps Improve Digestion & Detoxification
CONTAINS CAFFEINE
25N
HEALTHY CONSCIOUS LIVING

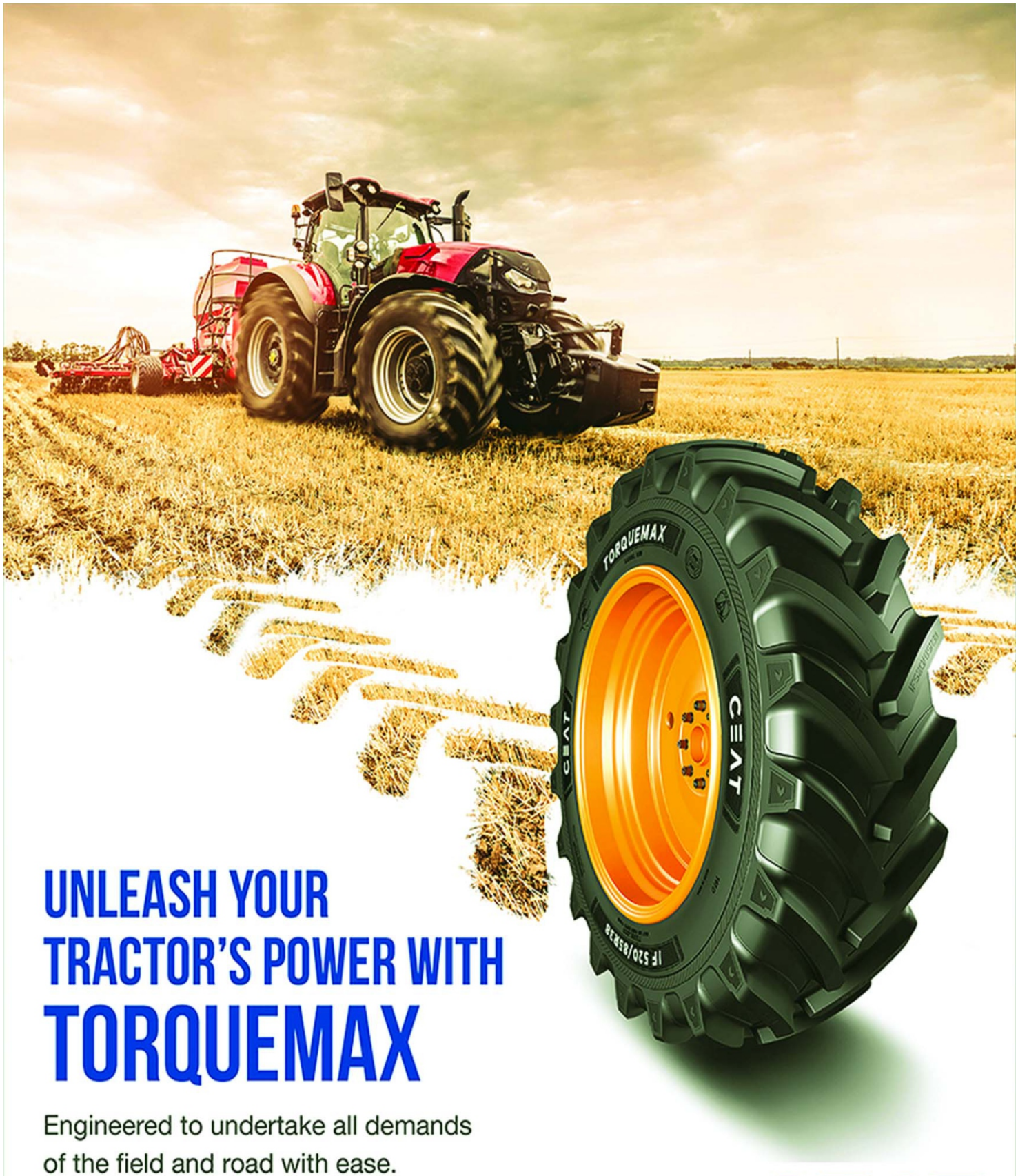

UNLEASH YOUR TRACTOR'S POWER WITH TORQUEMAX

Engineered to undertake all demands of the field and road with ease.

- Low soil compaction
- High traction
- Superior grip

Also, launching in **IF** (Increased Flexion) Technology

CEAT SPECIALTY